₹ 20

www.kewalsach.com

निर्भीकता हमारी पहचान

मार्च 2024

केवल सच

हिन्दी मासिक पत्रिका

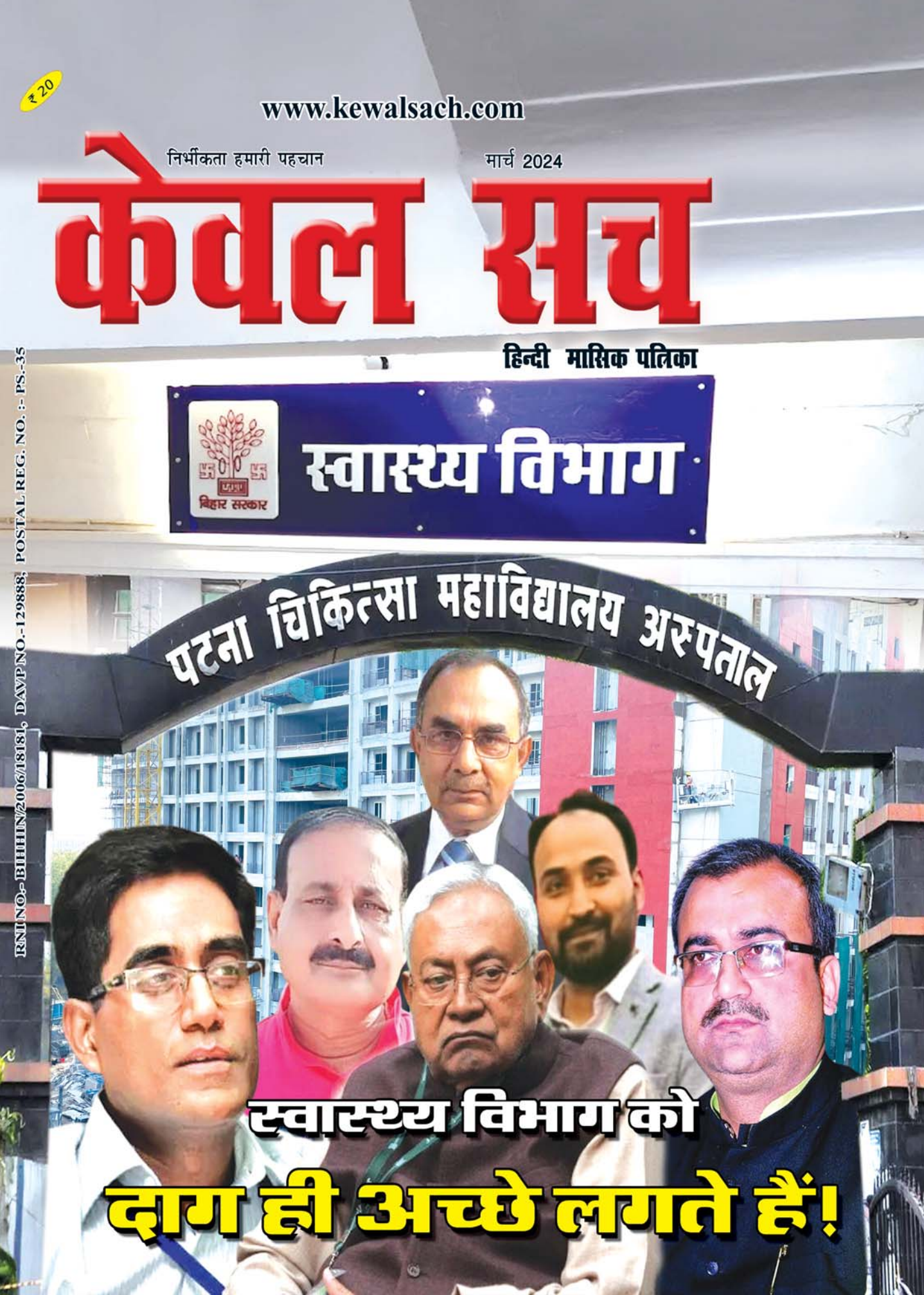

स्वास्थ्य विभाग को
दाग ही अच्छे लगते हैं!

RNI NO.-BIHHIN/2006/18181, DAVP NO.-129888; POSTAL REG. NO. :- PS.-35

जन-जन की आवाज है केवल सच

निर्भीकता हमारी पहचान

केवल सच

हिन्दी मासिक पत्रिका

Kewalachlive.in

वेब पोर्टल न्यूज

24 घंटे आपके साथ

Kewalsach news

Kewalsach news

Mob.: 9431073769, 9308815605

खबर वहीं, जो केवल सच हो

केवल सच TIMES

आत्म-निर्भर बनने वाले युवाओं को सपोर्ट करें

आपका छोटा सहयोग, हमें मजबूती प्रदान करेगा

BHIM UPI

G Pay पे Paytm

www.kewalsach.com www.kewalsachlive.in

-: सम्पर्क करें :-

पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14, मकान संख्या-28/14,

कंकड़बाग, पटना (बिहार)-800020, मो०:-9431073769, 9308815605

जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ

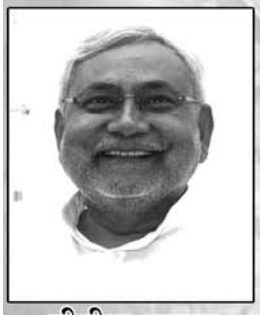

नीतीश कुमार
01 मार्च 1951

मेरी कॉम
01 मार्च 1983

शंकर महादेवन
03 मार्च 1967

शिवराज सिंह चौहान
05 मार्च 1959

अनुपम खेर
07 मार्च 1955

नवीन जिंदल
09 मार्च 1970

उमर अब्दुल्लाह
10 मार्च 1970

श्रेया घोषाल
12 मार्च 1984

वरूण गांधी
13 मार्च 1980

अमीर खान
14 मार्च 1965

हनी सिंह
15 मार्च 1984

राजपाल यादव
16 मार्च 1971

सानिया नेहवाल
17 मार्च 1990

रानी मुखर्जी
21 मार्च 1978

स्मृति जुबैद ईरानी
23 मार्च 1976

इमरान हाशमी
24 मार्च 1979

मधु
26 मार्च 1972

प्रकाश राज
26 मार्च 1965

शीला दीक्षित
31 मार्च 1938

मीरा कुमार
31 मार्च 1945

निर्भीकता हमारी पहचान

www.kewalsach.com

केवल सच

हिन्दी मासिक पत्रिका

Regd. Office :-
East Ashok, Nagar, House No.-28/14, Road No.-14, kankarbagh, Patna- 8000 20 (Bihar) Mob.-09431073769
E-mail :- kewalsach@gmail.com

Corporate Office:-
Vaishnavi Enclave, Second Floor, Flat No. 2B, Near-firing range, Bariatu Road, Ranchi- 834001
E-mail :- editor.kstimes@rediffmail.com

Delhi Office :-
Sanjay Kumar Sinha, A-68, 1st Floor, Nageshwar Talla Shastri Nagar, New Delhi - 110052
Mob.- 09868700991, 09955077308
E-mail:- kewalsach_times@rediffmail.com

Kolkata Office :-
Ajeet Kumar Dube, 131 Chitranjan Avenue, Near- md. Ali Park, Kolkata- 700073 (West Bengal)
Mob.- 09433567880 09339740757

Advertisement Rates Per Issue

COLOUR

AREA	FULL PAGE	HALF PAGE	Qr. PAGE
Cover Page	5,00,000/-	N/A	N/A
Back Page	1,60,000/-	N/A	N/A
Back Inside	1, 00000/-	60,000/-	35000
Back Inner	90,000/-	50,000/-	30000
Middle	1,50,000/-	N/A	N/A
Front Inside	1, 00000/-	60,000/-	40000
Front Inner	90,000/-	50,000/-	30000

B & W

AREA	FULL PAGE	HALF PAGE
Inner Page	60,000/-	35,000/-

1. एक साल के नियमित विज्ञापन पर पत्रिका के वेवसाइट **www.kewalsach.com** के फ्रंट पर भी विज्ञापन निःशुल्क तथा आपका वेवसाइट से सीधा लिंक हो सकता है।
2. एक साल के नियमित विज्ञापन पर 10 प्रतिशत की रियायत।
3. आपके प्रोडक्ट या संगठन के प्रचार-प्रसार हेतु आलेख को उचित स्थान।
4. पत्रिका द्वारा सामाजिक कार्य में आपके संगठन/प्रोडक्ट का बैनर/फ्लैक्स को उचित स्थान देकर आपके संगठन का व्यापक प्रचार-प्रसार।
5. विज्ञापन का भुगतान चेक या आर.टी.जी.एस. से ही मान्य होगा।

महाप्रबंधक (विज्ञापन)

मरीज की सुरक्षा के लिए भी बने कानून

अपनी प्रतिक्रिया हमारे ई-मेल पर दें:- editor.kstimes@rediffmail.com

भारत देश में विकास सही रूप से नहीं होने का सबसे बड़ा कारण है सरकारी जाने को सत्ता में बने रहने के लिए लुटाया जाए भले ही मध्यम वर्गीय परिवार का खून चूस क्यों नहीं लिया जाए। भोजन, रोजगार, स्वास्थ्य बीमा सहित तमाम प्रकार के सुविधा 70 प्रतिशत लोगों को मुफ्त में मिल रहा है लेकिन सरकार के खजाने भरने का काम मध्यम वर्गीय परिवार ही करता है। सरकारी योजना का लाभ से वंचित और बड़े स्तर पर लोन से भी वंचित किया जाता है. सरकार की नीतियों की वजह से स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में महालूट हो रहा है और मरीज के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर एम्स, सफदरजंग, सभी राज्य की सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज है तो फिर इन स्थलों पर आयुष्मान भारत योजना का बोर्ड यहां क्यों लटका हैं। 50 लाख रुपए सालाना पैकेज के बाद भी सरकार के डॉक्टर अपना प्राइवेट हॉस्पीटल खुलेआम चला रहे हैं, प्रचार के मध्यम ऑन कॉल डॉक्टर आकर मरीज का बिल बढ़ाते हैं और परिजन को भयभीत करते हैं ताकि उनसे मोटी रकम वसूल की जा सके। जितनी धनराशि आयुष्मान भारत योजना पर प्रतिवर्ष किया जा रहा है अगर उसका सही इस्तेमाल हो तो सभी राज्यों में उच्च स्तरीय हॉस्पीटल का संचालन किया जा सकता है, जिससे सरकारी खजाना लूटने से भी बचेगा और मरीज का समुचित ईलाज भी होगा। जिस प्रकार सरकारी एवं प्राईवेट हॉस्पीटल के डॉक्टर और स्टॉफ के सुरक्षा के लिए कानून बना दिया गया है उसी प्रकार मरीज एवं उनके परिजन के लिए भी कानून बने ताकि डॉक्टर की जिम्मेवारी होगी की वह मरीज की जान बचा सके साथ ही ऐसा कानून बनना चाहिए, जिससे हॉस्पिटल में ईलाज से मौत हो जाती है तो उस मरीज से आगे की धनराशि नहीं वसूल की जाए। सरकार अस्पताल के डॉक्टर किसी भी सूरत में प्राइवेट हॉस्पीटल नहीं चला सकते और ना ही ऑन कॉल जाकर मरीज का दोहन कर सकें।

मरीज और चिकित्सक का जो भावनात्मक संबंध था, वह अर्थयुग में धूमिल होता जा रहा है। तीन दशक पूर्व एक मरीज जब डॉक्टर और हॉस्पीटल के पास पहुंच जाता था तो उस मरीज और परिजन को लगता था कि अब उसकी जान बच सकती है लेकिन आज खुद डॉक्टर और हॉस्पीटल प्रबंधन को सिर्फ पैसा से सरोकार रह गया है, भले ही पेशेंट का कुछ भी हो। मरीज से जितनी राशि बटोरी जा सकती है बटोर लो, भले ही मरीज कर्ज में डूब जाए, घर द्वार बिक जाए। आमजनता के हितों की रक्षा के लिए केंद्र एवं राज्य की सरकार काफी मजबूत कानून बनाकर अधिकार दी है, जैसे- सूचना का अधिकार, भोजन का अधिकार, रोजगार का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, चिकित्सा का अधिकार (आयुष्मान भारत), लोक सेवा का अधिकार, वगैरह वगैरह। इन अधिकारों की वजह से देश की जनता को काफी राहत मिली है, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में निजी क्षेत्र की बढ़ती तानाशाही पर प्रतिबंध लगाने में केंद्र एवं राज्य सरकार दोनो विफल है बल्कि सरकार के मिलीभगत से देश की जनता का विश्वास का कत्ल किया जा रहा है। केंद्रीय विद्यालय में नामांकन की प्रक्रिया जितना जटिल है कि आम आदमी साहस ही नहीं जुटा पाता है और तो और सांसद एवं मंत्री का कोटा समाप्त हो जाने की वजह से प्राइवेट स्कूल की दादागिरी इतनी बढ़ गई है की जिस स्कूल को जितना इच्छा करे उतनी फीस वसूल करता है। सरकार की महत्वकांक्षी योजना शिक्षा का अधिकार अधिनियम में भी बड़े स्तर पर धांधली है, जिसको सरकार के साथ अधिकारी भी जानते हैं और मिल बांटकर खा जाते हैं। ठीक उसी प्रकार नरेंद्र मोदी ने भारत देश की बीमार जनता की समुचित ईलाज के लिए प्रति व्यक्ति पांच लाख रुपए (आयुष्मान भारत) देकर बहुत सार्थक प्रयास तो किया लेकिन आयुष्मान भारत योजना से मरीज को राहत मिलने से कहीं अधिक प्राइवेट हॉस्पिटल को चलाने में कारगर साबित हो रहा है। आज देश के सभी राज्यों एवं उसके शहरो में कुकुरमुत्ते की तरह खुल रहे प्राइवेट हॉस्पीटल के लिए आयुष्मान भारत योजना किसी वरदान से कम नहीं है। डॉक्टर एवं पूंजीपति ठेकेदार मिलकर अन्य व्यवसाय से अधिक हॉस्पीटल/नर्सिंग सेंटर खोल रहे हैं, जहां ग्राहक होता है मरीज और उसका गवाह बनता है उसका परिजन। आज प्राइवेट हॉस्पीटल में डॉक्टर की संवेदना अपने मरीज को स्वस्थ रखने के बजाय उससे कैसे अधिक से अधिक धनराशि वसूल कर लिया जाए, उसका टारगेट रहता है क्योंकि प्राइवेट हॉस्पीटल में अधिकांशत: डॉक्टर कॉल पर आते हैं और उनकी फीस काफी तगड़ी रहती है, जिसका बिल मरीज से वसूला जाता है। फाइव स्टार होटल की तरह अब हॉस्पीटल भी बन चुका है और तमाम प्रकार की सुविधाएँ यहां उपलब्ध है और उसकी कीमत को आयुष्मान भारत भारत सरकार और प्राइवेट मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी चुकता करती है। अगर कोई मरीज न तो आयुष्मान भारत का लाभार्थी है और न हीं मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी से कवर्ड तो वैसे मरीज और उनके परिजन को बजाज फाइनेंस कंपनी से लोन लेकर हॉस्पीटल का बिल का भुगतान करना पड़ता है। आज प्राइवेट हॉस्पीटल को लाभ दिलाने के लिए जिस प्रकार सरकार, मंत्रालय और विभाग की मिलीभगत से सरकारी खजाने से खरबों की महालूट की जा रही है और आयुष्मान भारत योजना से सिर्फ भला प्राइवेट हॉस्पीटल को ही हो रहा है क्योंकि जो लाभुक हैं उनको यह पता ही नहीं है की उनके कार्ड से कितनी धनराशि खर्च किए गए, वह इसलिए भी आवाज नहीं उठाते की उनको तो यह सुविधा मुफ्त में मिल रही है। कई लाभुक तो इसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं और कार्ड से मोटी रकम भी वसूल रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल से सांठ-गांठ करके ईलाज के नाम पर सरकार के द्वारा मिलने वाली राशि का बंदरबाट कर लेते हैं। वही दूसरी तरफ मध्यम वर्गीय परिवार सरकार को टैक्स भी देता है, लेकिन उसको किसी प्रकार की सुविधा मुहैया नहीं कराया जाता, बस उसके कमाई से खून चूस लेता है। सरकार जितनी धनराशि आयुष्मान भारत योजना में खर्च कर रही है, उन रुपयों से देश के विभिन्न राज्यों एवं उनके शहरों में बेहतरीन स्वास्थ्य विभाग को कारगर एवं सभी प्रकार के संसाधनों से लैश किया जा सकता है, परंतु ऐसा करने से महालूट करनेवाला गैंग को तगड़ा झटका लग सकता है। आयुष्मान भारत योजना के पहले भी स्वास्थ्य विभाग में महालूट का अंजाम बीपीएल वालो से किया जाता था। दोनों योजना में महालूट होता है इसकी हजारों खबरें सार्वजनिक हो चुकी हैं और कई हॉस्पीटल को काली सूची में डाला गया है। स्वास्थ्य विभाग में तभी सुधार होगा जब सरकारी हॉस्पीटल के डॉक्टर प्राईवेट हॉस्पीटल या क्लीनिक नहीं खोल सकते अन्यथा उनपर मरीज के साथ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हो और उनपर कानून कड़ा से कड़ा हो। एक तरफ सभी सरकारी एवं प्राईवेट हॉस्पीटल में बड़ा बोर्ड लगा मिलता है, जिसमे यह सूचना रहती है कि हॉस्पीटल में तोड़-फोड़ करना, डॉक्टर और स्टाफ के साथ अभद्र व्यवहार एवं मारपीट करना गैर जमानतीय अपराध है और इसके लिए 3 साल की सजा एवं 50 हजार का जुर्माना भी देना होगा तथा संबंधित व्यक्ति से नुकसान की दोगुनी राशि वसूल की जाएगी, का कानून है परंतु मरीज के साथ जिस प्रकार गाजर-मूली की तरह खेला जा रहा है और उसके परिजन से अकूत खजाना लूट लिया जाता है और उसको सही जानकारी तक नहीं मिलती, उसके लिए डॉक्टर और हॉस्पीटल स्टाफ पर किसी प्रकार की करवाई होनी चाहिए। लाखों रुपए वसूल करने के बाद भी मरीज की मृत्यु हो जाए तो प्राईवेट हॉस्पीटल को मरीज के परिजन से एक भी रुपए नहीं वसूल किए जायेंगे, उसका कानून नहीं बनना चाहिए?

फरवरी 2024

आपको केवल सच पत्रिका कैसी लगी तथा इसमें कौन-कौन सी खामियाँ हैं, अपने सुझाव के साथ हमारा मार्गदर्शन करें। आपका पत्र ही हमारा बल है। हम आपके सलाह को संजीवनी बूटी समझेंगे।

केवल सच

हमारा पता है :-

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका
द्वारा:- ब्रजेश मिश्र
पूर्वी अशोक नगर, रोड़ नं.- 14, मकान संख्या- 14/28
कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार)
फोन:- 9431073769/ 8340360961/ 9955077308

हमारा ई-मेल
kewalsach@gmail.com, editor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

बिहार

संपादक जी,

केवल सच पत्रिका के फरवरी 2024 अंक में आपका संपादकीय बर्बाद, आबाद और फिर बर्बाद बिहार में पिछले 32 वर्षो की राजनीति एवं विकास की सटीक समीक्षात्मक जानकारी दी है तथा इसके लिए जिम्मेदार नीतीश कुमार पर सकारात्मक व्यंग किया है. बिहार की गौरवशाली इतिहास के जानकारी के साथ वर्तमान समय की राजनीति पर पठनीय सामग्री पाठको के बीच रखा है. स्पष्ट एवं बेबाक टिप्पणी लिखना ही केवल सच की साख को मजबूत करता है।

✦ **संजय पाठक, लेखा नगर, खगौल पटना**

उथल पुथल

ब्रजेश जी,

केवल सच पत्रिका अब झारखंड की राजनीतिक खबरों को भी महत्व देकर खबर को प्राथमिकता से प्रकाशित करने लगा है, जबकि पहले सिर्फ पुलिस एवं अपराध की खबरों को ही स्थान देता था। 2024 के फरवरी अंक में झारखंड सरकार में हुई उथल पुथल राजनीति को बहुत सटीक ढंग से गुड्डी साव ने लिखा है जो पढ़ने योग्य है। दूसरी खबर देश की आन बान शान हैं धोनी में भी धोनी के जीवन वृत्त को बारीकी से जानकारी योग्य बातों को पाठकों के समक्ष रखा है।

✦ **महेश गुप्ता, काको रोड, रांची**

सोमनाथ से अयोध्या

मिश्रा जी,

केवल सच पत्रिका का मैं नियमित पाठक हूं। संतोष पाठक की फरवरी 2024 अंक में प्रकाशित खबर सोमनाथ से अयोध्या तक संघर्ष के गाथा को पूरी गंभीरता के साथ पूर्व में किए गए आडवाणी के सार्थक प्रयास के साथ लालू यादव की राजनीति को भी स्थान दिया है आलेख में। उत्तर प्रदेश के कल्याण सिंह के प्रयास को भी आलेख में उचित स्थान देना अच्छी पत्रकारिता का परिचय है। इस प्रकार संघर्ष यात्रा को लेख के माध्यम से जीवंत करने के लिए पत्रकार महोदय को धन्यवाद.

✦ **कौशल यादव, मीना बाजार लखनऊ, यूपी**

सरकारी दामाद

मिश्रा जी,

केवल सच पत्रिका भ्रष्टाचार के विरुद्ध पूर्ण बेबाकी के साथ खबर को मजबूती के साथ वर्षो से लिखता आ रहा है। फरवरी 2024 अंक में पत्रकार शशि रंजन सिंह एवं राजीव शुक्ला ने 'नीतीश ने डॉ ठाकुर को सरकारी दामाद (राबर्ट वाड्रा) घोषित किया' के खबर में बिहार राज्य के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच के अधीक्षक पर विभागीय कार्रवाई चल रही है, पूरा पुख्ता सबूत के साथ खबर को लिखा गया है। राज्य सरकार की स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त लापरवाही को लगातार केवल सच पत्रिका उजागर करके सरकार के संज्ञान में लाता है।

✦ **अनिरुद्ध प्रसाद, राजा बाजार, पटना**

हर बार नीतीश कुमार

संपादक जी,

फरवरी 2024 अंक का कवर स्टोरी 'मुख्यमंत्री हर बार नीतीश कुमार' में अमित कुमार ने बिहार सरकार एवं राजनीति के पलटीमार स्थिति पर व्यंग्यात्मक विषय को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इस अंक में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच के संबंध पर तथ्यात्मक कारणों का भी सही उल्लेख किया है। केवल सच पत्रिका राजनीति पर सटीक विश्लेषण करके खबर को पाठकों के समक्ष रखते हैं, जिससे केवल सच की महत्ता बढ़ जाती है। राजनीति की खबरों का भंडार है केवल सच।

✦ **दीपक सिंह, साकची मार्केट जमशेदपुर झा**

कर्पूरी ठाकुर

संपादक जी,

'कार्यकर्त्ता प्रधान राजनीति के नायक कर्पूरी ठाकुर' और 'आधुनिक बिहार के निर्माण में बिहार केसरी डा श्रीकृष्ण सिंह' दोनो आलेख में मिथिलेश कुमार ने बिहार की राजनीति और जीवन पर सटीक विश्लेषण किया है। दोनों आलेख पढ़कर ऐसा लगा की शिखर पर पहुंच पाना मुश्किल है, लेकिन संघर्ष करने वाला एक दिन मुकाम हासिल करता ही है। वही संजय सिन्हा की खबर 'यह किसान नहीं बल्कि ठेकेदार हैं' एवं दूसरी खबर 'बागेश्वर धाम सनातन संस्कृति की ओर' वाली खबर छोटी सही पर कारगर है।

✦ **कामेश्वर झा, सरिता बिहार, नई दिल्ली**

अन्दर के पन्नों में

10

बदलती रही राजनीतिक परिदृश्य.....46

सात चरणों में होगा लोकसभा चुनाव.....56

डबल मर्डर का खुलासा.....83

RNI No.- BIHHIN/2006/18181, DAVP No.- 129888

समृद्ध भारत खुशहाल भारत

निर्भीकता हमारी पहचान

केवल सच

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका

वर्ष:- 18, | अंक:- 214, | माह:- मार्च 2024, | मूल्य:- 20/- रू

फाउंडर

स्व० गोपाल मिश्र

संपादक

ब्रजेश मिश्र

9431073769 8340360961

editor.kstimes@rediffmail.com

kewalsach@gmail.com

प्रधान संपादक

अरूण कुमार बंका	7782053204
सुरजीत तिवारी	9431222619
निलेन्दु कुमार झा	9431810505, 8210878854
सच्चिदानन्द मिश्र	9934899917
रामानंद राय	9905250798
डॉ० शशि कुमार	9507773579

संपादकीय सलाहकार

अमिताभ रंजन मिश्र	9430888060, 8873004350
अमोद कुमार	9431075402

महाप्रबंधक

त्रिलोकी नाथ प्रसाद	9308815605, 9122003000

triloki.kewalsach@gmail.com

महाप्रबंधक (विज्ञापन)

पूनम जयसवाल	9430000482, 9798874154
मनीष कुमार कमलिया	9934964551, 8809888819

उप-संपादक

अरविंद मिश्रा	9934227532, 8603069137
प्रसुन्न पुष्कर	9430826922, 7004808186
ब्रजेश सहाय	7488696914
ललन कुमार	7979909054, 9334813587
आलोक कुमार सिंह	8409746883

संयुक्त संपादक

अमित कुमार 'गुड्डू'	9905244479, 7979075212
राजीव कुमार शुक्ला	9430049782, 7488290565
कृष्ण कुमार सिंह	6209194719, 7909077239
काशीनाथ गिरी	9905048751, 9431644829
बिरेन्द्र सिंह	7050383816

सहायक संपादक

शशि रंजन सिंह	8210772610, 9431253179
मिथिलेश कुमार	9934021022, 9431410833
नवेन्दु कुमार मिश्र	9570029800, 9199732994
कामोद कुमार कंचन	8971844318

समाचार प्रबंधक

सुधीर कुमार मिश्र	9608010907

ब्यूरो-इन-चीफ

संकेत कुमार झा	9386901616, 7762089203
बिनय भूषण झा	9473035808, 8229070426

विधि सलाहकार

शिवानन्द गिरि	9308454485
रवि कुमार पाण्डेय	9507712014

चीफ क्राइम ब्यूरो

आनन्द प्रकाश	9508451204, 8409462970

साज-सज्जा प्रबंधक

अमित कुमार	9905244479

amit.kewalsach@gmail.com

कार्यालय संवाददाता

सोनू यादव	8002647553, 9060359115

प्रसार प्रतिनिधि

कुणाल कुमार	9905203164

बिहार प्रदेश जिला ब्यूरो

पटना (श०) :-	श्रीधर पाण्डेय	9470709185
(म०) :-	गौरव कुमार	9472400626
(ग्रा०) :-		
बाढ़ :-		
भोजपुर :-	गुड्डू कुमार सिंह	8789291547
बक्सर :-	बिन्ध्याचल सिंह	8935909034
कैमूर :-		
रोहतास :-	अशोक कुमार सिंह	7739706506
:-		
गया (श०) :-	सुमित कुमार मिश्र	7667482916
(ग्रा०) :-		
औरंगाबाद :-		
जहानाबाद :-	नवीन कुमार रौशन	9934039939
अरवल :-	संतोष कुमार मिश्रा	9934248543
नालन्दा :-		
:-		
नवादा :-	अमित कुमार	9934706928
:-		
मुंगेर :-		
लखीसराय :-		
शेखपुरा :-		
बेगूसराय :-	निलेश कुमार	9113384406
:-		
खगड़िया :-		
समस्तीपुर :-		
जमुई :-	अजय कुमार	09430030594
वैशाली :-		
:-		
छपरा :-		
सिवान :-		
:-		
गोपालगंज :-		
:-		
मुजफ्फरपुर :-	.	
:-		
सीतामढ़ी :-		
शिवहर :-		
बेतिया :-	रवि रंजन मिश्रा	9801447649
बगहा :-		
मोतिहारी :-	संजीव रंजन तिवारी	9430915909
दरभंगा :-		
:-		
मधुबनी :-	सुरेश प्रसाद गुप्ता	9939817141
:-	प्रशांत कुमार गुप्ता	6299028442
सहरसा :-		
मधेपुरा :-		
सुपौल :-		
किशनगंज :-		
:-		
अररिया :-	अब्दुल कय्यूम	9934276870
पूर्णिया :-		
कटिहार :-		
भागलपुर, :-		
(ग्रा०) :-	रवि पाण्डेय	7033040570
नवगछिया :-		

दिल्ली कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
द्वारा- संजय कुमार सिन्हा
A-68, 1st Floor,
नागेश्वर तल्ला, शास्त्रीनगर, न्यू
दिल्ली-110052
संजय कुमार सिन्हा, स्टेट हेड
मो०- 9868700991, 9431073769

उत्तरप्रदेश कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
....., स्टेट हेड

सम्पर्क करें
9308815605

पश्चिम बंगाल कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
द्वारा- अजीत कुमार दुबे
131 चितरंजन एवेन्यू,
कोलकात्ता, पश्चिम बंगाल- 700073
अजीत कुमार दुबे, स्टेट हेड
मो०- 9433567880, 9308815605

मध्य प्रदेश कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
हाउस नं.-28, हरसिद्धि कैम्पस
खुशीपुर, चांबड़
भोपाल, मध्य प्रदेश- 462010
अभिषेक कुमार पाठक, स्टेट हेड
मो०- 8109932505,

झारखंड कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
वैष्णवी इंक्लेव,
द्वितीय तल, फ्लैट नं- 2बी
नियर- फायरिंग रेंज
बरियातु रोड, राँची- 834001

छत्तीसगढ़ कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,

....., स्टेट हेड

सम्पर्क करें
8340360961

संपादकीय व प्रधान कार्यालयः-

☞ पूर्वी अशोक नगर, रोड नं:-14, मकान संख्याः- 14/28, कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार) मो०- 9431073769, 9955077308

☞ e-mail:- kewalsach@gmail.com, e ditor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

☞ स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक ब्रजेश मिश्र द्वारा सांध्य प्रवक्ता खबर वर्क्स, ए- 17, वाटिका विहार (आनन्द विहार), अम्बेडकर पथ, पटना 8000 14(बिहार) एवं पूर्वी अशोक नगर, रोड नं. 14, कंकड़बाग पटना-800020 से प्रकाशित, संपादक- ब्रजेश मिश्र। RNI NO.-BIHHIN/2006/18181

☞ पत्रिका में प्रकाशित समाचारों से संपादक की सहमति आवश्यक नहीं है।

☞ सभी प्रकार के वाद-विवादों का निपटारा पटना न्यायालय के अधीन होगा।

☞ आलेख पर कोई आपत्ति हो तो एक महीने के भीतर खंडन करें।

☞ किसी भी लेख के लिए रचनाकार/लेखक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

☞ सभी पद अवैतनिक हैं।

☞ फोटो-समाचार साभार भी (माध्यम- इंटरनेट एवं अन्य स्त्रोत)

☞ कोई भी शिकायत हमारे पते पर लिखकर भेजें।

☞ **विज्ञापन का भुगतान चेक या ड्राफ्ट एवं RTGS से ही मान्य होगा।**

☞ भुगतान Kewal Sach को ही करें। प्रतिनिधियों को नगद न दें।

☞ A/C No. :- 0600050004768
BANK :- Punjab National Bank
IFSC Code :- PUNB0060020
PAN No. :- AAJFK0065A

प्रधान संपादक

.....
.....

झारखण्ड स्टेट ब्यूरो

.....
.....

झारखण्ड सहायक संपादक

ब्रजेश कुमार मिश्र 9431950636, 9631490205
ब्रजेश मिश्र 7654122344-7979769647
अभिजीत दीप 7004274675-9430192929

उप संपादक

.....
.....

संयुक्त संपादक

.....
.....

विशेष प्रतिनिधि

भारती मिश्रा 8210023343-8863893672
.....
.....

झारखण्ड प्रदेश जिला ब्यूरो

राँची :- अभिषेक मिश्र 7903856569
:- ओम प्रकाश 9708005900
साहेबगंज :- अनंत मोहन यादव 9546624444
खूँटी :-
जमशेदपुर :- तारकेश्वर प्रसाद गुप्ता 9304824724
हजारीबाग :-
जामताड़ा :-
दुमका :-
देवघर :-
धनबाद :-
बोकारो :-
रामगढ़ :-
चाईबासा :-
कोडरमा :-
गिरीडीह :-
चतरा :- धीरज कुमार 9939149331
लातेहार :-
गोड्डा :-
गुमला :-
पलामू :-
गढ़वा :-
पाकुड़ :-
सरायकेला :-
सिमडेगा :-
लोहरदगा :-

श्री चन्द्र प्रकाश सिंह

प्रधान संरक्षक सह प्रबंध संपादक
'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**
राष्ट्रीय संगठन मंत्री, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक)
पूर्व निदेशक सदस्य, ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
09431016951, 09334110654

डॉ. सुनील कुमार

शिशु रोग विशेषज्ञ सह मुख्य संरक्षक
'केवल सच' पत्रिका
एवं 'केवल सच टाइम्स'
एन.सी.- 115, एसबीआई ऑफिसर्स कॉलोनी,
लोहिया नगर, कंकड़बाग, पटना- 800020
फोन- 0612/3504251

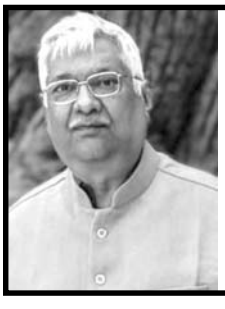

श्री सज्जन कुमार सुरेका

मुख्य संरक्षक
'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**
डी- 402 राजेन्द्र विहार, फॉरेस्ट पार्क
भुवनेश्वर- 751009 मो-09437029875

सुधीर कुमार

मुख्य संरक्षक सह निदेशक ''**मगध इंटरनेशनल स्कूल**'' टेकारी
'' **केवल सच** '' पत्रिका **एवं** '' **केवल सच टाइम्स** ''
9060148110
sudhir4s14@gmail.com

श्री आर के झा

मुख्य संरक्षक
'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**
EX. CGM, (Engg.) N.B.C.C
08877663300

बिहार राज्य प्रमंडल ब्यूरो

पटना		
मगध		
सारण		
तिरहुत		
पूर्णिया	**धर्मेन्द्र सिंह**	9430230000 7004119966
भागलपुर		
मुंगेर		
दरभंगा		
कोशी		

विशेष प्रतिनिधि

आशुतोष कुमार	9430202335, 9304441800
सुमित राज यादव	9472110940, 8987123161
बेंकटेश कुमार	8521308428, 9572796847
राजीव नयन	9973120511, 9430255401
मणिभूषण तिवारी	9693498852
दीपनारायण सिंह	9934292882
आनन्द प्रकाश पाण्डेय	9931202352, 7808496247
विनित कुमार	8210591866, 8969722700
रामजीवन साहू	9430279411, 7250065417

छायाकार

त्रिलोकी नाथ प्रसाद	9122003000, 9431096964
मुकेश कुमार	9835054762, 9304377779
जय प्रसाद	9386899670,
कृष्णा प्रसाद	9608084774, 9835829947

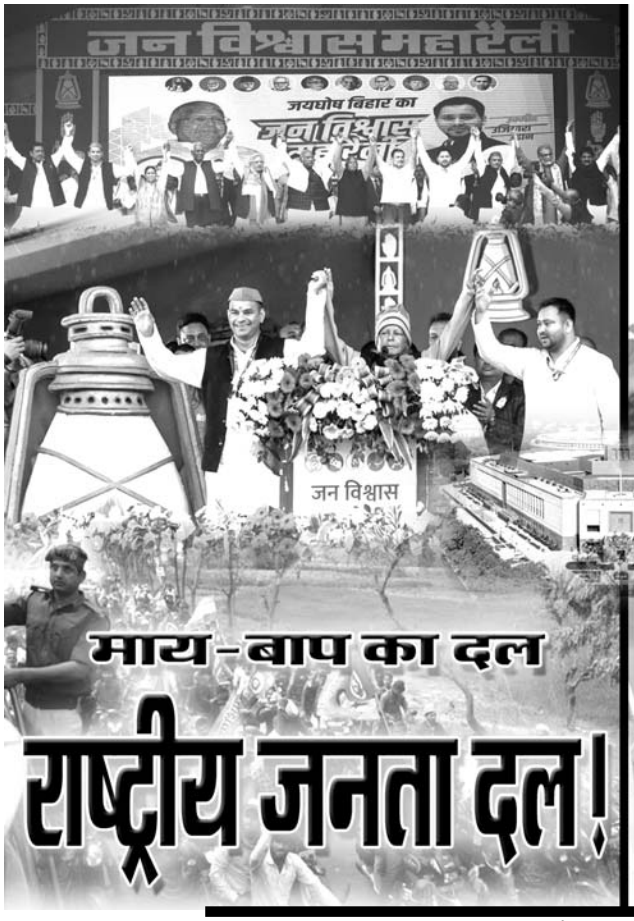

● **अमित कुमार**

18 वीं लोकसभा चुनाव का विगुल बज चुका है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर 2024 में आम चुनाव कुल सात चरणों में होंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। बिहार में लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल से शुरू होगी और आखिरी चरण का मतदान 1 जून को होगा। इसके बाद 4 जून को सभी चरणों की एक साथ मतगणना होगी एवं इसी दिन नतीजे जारी हो जाएंगे। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक बिहार में पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा। इसके बाद 26 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग होगी। तीसरे चरण के लिए 7 मई, चौथे चरण के लिए 13 मई, पांचवें चरण के लिए 20 मई, छठे चरण के लिए 25 मई और सातवें एवं आखिरी चरण के लिए 1 जून को वोट पड़ेंगे। बता दें कि पहला चरण 4 सीटें-औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई, दूसरा चरण 5 सीटें-किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका, तीसरा चरण 5 सीटें-झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया, चौथा चरण 5 सीटें-दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर, पांचवां चरण 5 सीटें-सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर, छठा चरण 8 सीटें-वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सीवान और महाराजगंज, सातवां चरण 8 सीटें-नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट और जहानाबाद में पूरे किये जायेंगे।

बहरहाल, 18वीं लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर हर वह छोटे-बड़े दल अपनी जोर आजमाइस लगाते दिखने लगे हैं। रैलियां शुरू हो चुकी है। जनता के बीच विकास के कार्यों से लेकर भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे मुख्य मुद्दों को खूब परोसा जा रहा है। दिगर बात है कि एक तरफ क्षेत्रीय पार्टियां मजबूती से अपने सीट से खड़े उम्मीदवारों को लेकर राजनीतिक रास्ता अख्तियार करने में जुटी है तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय पार्टियां पीएम के पद के लिए कुर्सी-कुर्सी खेल रही है। मुख्य रूप से राष्ट्रीय पटल पर भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान में केंद्र की कुर्सी पर विराजमान है तो वही कांग्रेस है जो उस कुर्सी से पीएम मोदी को पटखनी देने में कोई कोर-कसर छोड़ने को तैयार नहीं। लोकसभा के इस युद्ध में कांग्रेस नित इंडिया गठबंधन को साथ लेकर सभी विपक्षी दलों को एक साथ एक मंच पर लाकर केंद्र की मोदी सरकार को सत्ता से हटाने के

लिए जिस प्रकार मेहनत करते दिख रही है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार का होने वाला लोकसभा चुनाव नये प्रयोग के साथ दिलचस्प होगा। भाजपा 'मोदी की गारंटी' की नैया पर '400 के पार' का नारा दे रही है तो वही कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में 'न्याय यात्रा' कर जनता के बीच अपनी खोयी पहचान को वापस लाने के लिए प्रयासरत्त है। किन्तु जिस प्रकार कांग्रेस के भीतर के वरिष्ठ नेताओं का अपने पुराने दल को छोड़कर भाजपा में शामिल होने की होड़ जो मची है, इसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। बीते पांच राज्यों के चुनाव में कांग्रेस को मिली हार और भाजपा की अप्रत्याशित जीत के साथ ही महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश में हुए राजनीतिक खेल के बाद इंडिया गठबंधन की नीव रखने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक बार फिर महागठबंधन से अलग होकर एनडीए और मोदी के साथ आना इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा झटका है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में वापसी हो चुकी है। ओडिशा में सत्तारूढ़ बीजू जनता दल के प्रमुख नवीन पटनायक के भी जल्द एनडीए में वापसी की अटकलें हैं। अब खबर है कि भारतीय जनता पार्टी भारत के दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश में भी बड़े गठबंधन की तैयारी में है। हालांकि, आधिकारिक तौर पर अब तक कुछ नहीं कहा गया है। खबरें हैं कि भाजपा तेलुगू देशम पार्टी और जनसेना के साथ हाथ मिला सकती है। कर्नाटक को छोड़कर भाजपा दक्षिण भारत के किसी हिस्से में खास मौजूदगी दर्ज नहीं करा सकी है। हालांकि, बीते लोकसभा चुनाव में पार्टी को तेलंगाना में भी चार सीटें मिली थीं। 5 राज्यों की 127 सीटों में से भाजपा सिर्फ 29 ही हासिल कर सकी थी। इनमें 25 सीटें कर्नाटक की शामिल हैं। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि भाजपा ने आंध्र प्रदेश में 30 विधानसभा और 7 लोकसभा सीटों की मांग की है। इनमें 1 या 2 सीटें पवन कल्याण की भी शामिल हैं। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि भाजपा दक्षिण भारत की 84 सीटों पर फोकस कर रही है। खास बात है कि 5 राज्यों में सीटों की संख्या बढ़ाना भाजपा के एनडीए के लिए '400 पार' के नारे के लिए काफी अहम होगा। कभी एनडीए के शुरुआती सदस्यों में शामिल रही टीडीपी ने करीब 6 साल पहले गठबंधन से दूरी बना ली थी। अब संभावनाएं हैं कि पार्टी एनडीए

औरंगाबाद, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, उजियारपुर, बेगूसराय, नवादा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर और सासाराम समेत 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जदयू वाल्मिकी नगर, सीतामढ़ी, शिवहर, झंझारपुर, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, मधेपुरा, गोपालगंज, सीवान, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नालंदा और सीवान में चुनाव लड़ेगी। लोजपा (रा) वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मांझी की पार्टी गया और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी काराकाट सीट से चुनाव लड़ेगी। सीट बंटवारें की घोषणा से पहले विनोद तावड़े ने कहा कि भले पार्टी के चुनाव चिन्ह अलग हों लेकिन सभी 40 सीट पर एनडीए की सभी पार्टियां पूरा ताकत लगाएगी। हमलोग 40 के 40 सीट पर जीतेंगे। वही सीट शेयरिंग के घोषण के वक्त राष्ट्रीय लोकशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति पारस का जिक्र तक नहीं किया गया। दिल्ली में हाजीपुर, समस्तीपुर और नवादा में पशुपति पारस ने अपने उम्मीदवारों का नाम तय किया था। भाजपा ने हाजीपुर और समस्तीपुर चिराग को दे दिया। वहीं नवादा सीट खुद के पास रख लिया। अब देखना यह होगा कि पारस का अगला कदम क्या होता है।

हालांकि शीट शेयरिंग की घोषण से पहले एनडीए में असमंजस बना हुआ था कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों में भाजपा-जदयू के अलावे अन्य दलों के बीच कितने सीट पर सहमती बनती है। इसका हल निकालने में भाजपा शीर्ष माथापच्ची कर रही थी। वैसे बता दे कि सीट बंटवारे को लेकर भाजपा लगातार अपने

घटक दलों के साथ सम्पर्क में भी थी। बता दें कि 12 मार्च को दिल्ली में बिहार भाजपा प्रभारी विनोद तावड़े के आवास पर बिहार भाजपा के नेताओं के साथ बैठक हुई थी। उपमुख्यमंत्री सह प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेन्द्र, प्रदेश संगठन महामंत्री भीखू भाई दलसानिया इस बैठक में शामिल हुए। लगभग ढाई घंटे तक चली इस बैठक में बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों पर मंथन हुआ। पार्टी नेताओं ने सीट टू सीट बातचीत की। साथ ही सीटिंग सीटों में पर्यवेक्षकों से हर लोकसभा क्षेत्र के लिए आए चार-छह नामों में से तीन-तीन नाम भी छांटे गए। आलाकमान को हरेक लोकसभा क्षेत्र के लिए तीन-तीन नाम दिए जाएंगे। इन्हीं तीन नामों में से किसी एक को उम्मीदवार बनाया जाएगा। बैठक के बाद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि एनडीए में ऑल इज वेल है। कहीं कोई समस्या नहीं है। लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के पहले एनडीए में सीटों का बंटवारा हो जाएगा। वही चिराग पासवान के सवाल पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा था कि कोई कहीं नहीं जा रहे हैं। सब एनडीए में ही रहेंगे। उधर, दिल्ली से लौटने पर उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भी इसी तरह का दावा किया। उन्होंने कहा कि चुनाव की घोषणा होने के पहले सीटों का बंटवारा हो जाएगा। एनडीए में कहीं कोई जिच नहीं है। चिराग पासवान के सवाल पर उन्होंने कहा कि भाजपा सहयोगियों को सम्मान देती है। सबों को साथ लेकर भाजपा चलती है। इसलिए भाजपा के जो सहयोगी हैं, वे भाजपा के साथ ही रहेंगे।

कहीं कोई समस्या नहीं है। पीएम के साथ रहने में सबों को गर्व महसूस होता है।

बहरहाल, बीते दिनों बिहार की धरती पर रैलियों का जमावड़ा लगातार होते दिख रहा है। एक तरफ इंडिया गठबंधन राजधानी पटना के गांधी मैदान में हूंकार भरते देखी गई तो वही बाद में बेतिया में प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न योजनाओं के उद्घाटन के बीच जनता को संबोधित किया। सनद् रहे कि इससे पूर्व औरंगाबाद में लालू परिवार को आड़े हाथों लेते हुए भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर खूब गरजते दिखे। बता दें कि प्रधानमंत्री के बिहार दौरे के बाद से ही महागठबंधन और एनडीए के बीच 'मोदी का परिवार', परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर सियासी जंग छिड़ी हुई है। अपने बिहार दौरे में पीएम मोदी ने तेजस्वी और लालू यादव परिवारवाद को लेकर तीखे तंज कसे थे। इसके बाद गांधी मैदान में आयोजित जनविश्वास रैली में लालू यादव ने मोदी के परिवार और उनके हिंदू होने पर सवाल उठा दिया। इसके बाद भाजपा ने 'मोदी का परिवार' नाम से कैंपेन शुरू कर दिया। गौरतलब हो कि रैलियों के महाकुंभ में गृहमंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भाजपा की ओर से पटना जिले के पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र के पालीगंज में पिछड़ा-अति पिछड़ा सम्मेलन को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि पालीगंज की धरती वीरों की भूमि है। अमित शाह ने ऐलान किया कि भू-माफिया, बालू माफिया एवं गरीबों का शोषण करने वाले को उलटा लटकाकर सीधा कर देंगे। एक कमिटी बनेगी, उस रिपोर्ट के आधार पर भू-माफिया को जेल में डालेंगे। उन्होंने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को चेतावनी देते हुए कहा कि जिन्होंने गरीबों की भूमि कब्जाई है, उन्हें यह सरकार जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में आरजेडी पर माफिया राज को बढ़ावा देने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि लालू यादव ने सिर्फ पिछड़ों और अति पिछड़ों की जमीनें हथियाने का काम किया है। अमित शाह ने लालू-राबड़ी के साथ-साथ कांग्रेस राज में हुए घोटालों का जिक्र किया और कहा कि ये लोग घोटालेबाज हैं। मोदी 23 साल से मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री हैं पर हमारे नेता पर कोई 25 पैसे का भी घोटाले का आरोप नहीं लगा सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस की सोनिया गांधी का एकमात्र लक्ष्य है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है और लालू का एकमात्र लक्ष्य है बेटे को मुख्यमंत्री बनाना। मुझे बताओ क्या ऐसे लोग आपके बेटे-बेटियों का भला कर सकते हैं? आपका कोई भला करेगा तो सिर्फ नरेंद्र मोदी ही करेंगे। अमित शाह ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर पहले ही बनना चाहिए था। लालू यादव ने लालकृष्ण आडवाणी को पकड़कर राम रथ रोक दिया था। अब लालू कुछ नहीं कर सकते, बिहार की जनता हमारे साथ है। पीएम मोदी ने राम मंदिर की भूमि पूजन भी की और प्राण प्रतिष्ठा भी कराई। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव इतने सालों तक सत्ता में रहे। इन्होंने कभी भी कर्पूरी ठाकुर का सम्मान करने का काम नहीं किया। बिहार के अति पिछड़ा वर्ग से आने वाले बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया। कांग्रेस ने हमेशा अपने परिवार का सम्मान किया। लालू ने भी पूरा जीवन पिछड़ों के नाम पर परिवार के लिए ही काम किया है। लालू यादव जिनकी गोदी में जाकर बैठे हैं उस कांग्रेस पार्टी ने हमेशा पिछड़ा और अति पिछड़ा का अपमान किया। कांग्रेस पार्टी की सरकार

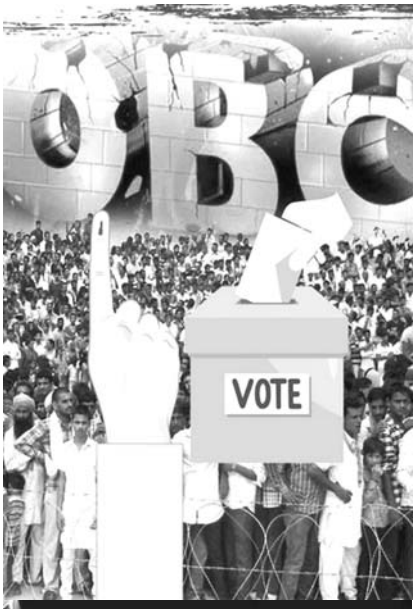

थी तब सालों तक दादा साहेब कमीशन की रिपोर्ट को वे दबाकर बैठे। इंदिरा गांधी ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को दबा दिया। जब यह संसद में पेश हुई तो राजीव गांधी ने दो घंटे भाषण देकर ओबीसी आरक्षण का विरोध किया। बीजेपी ने इसका समर्थन किया था। अमित शाह ने कहा कि पिछड़ा वर्ग आयोग को कांग्रेस पार्टी ने संवैधानिक मान्यता नहीं दी। उसी कांग्रेस का सहयोगी बने लालू प्रसाद यादव पिछड़ा और दलित हितैषी होने का दावा करते हैं। लालू अगर कोई काम कर सकते हैं तो वह यह है कि पिछड़े समाज के लोगों की जमीन हथिया लेंगे। यहां किसी माफिया का राज नहीं चल सकता। गृहमंत्री ने ऐलान किया कि भू-माफियाओं की बिहार में चलने नहीं देंगे। उन्हें उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे। इसके लिए एक कमिटी बनेगी और उसकी रिपोर्ट के आधार पर भू-माफियाओं पर कठोर कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे। पालीगंज की जनसभा में अमित शाह ने लोगों से आवाह्न किया की 2024 में 40 की 40 सीटें मोदी की झोली में डालना है। क्या आप डालोगे? कहा अभी-अभी मोदी आए थे, दो लाख करोड़ से ज्यादा की विकास की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया था। मैं आज मोदी को बिहार की जनता की ओर से विशेष बात के लिए धन्यवाद करता हूं।

बताते चले कि लोकसभा चुनाव की घोषणा में अब हफ्ते-दस दिन का वक्त बचा है। जाहिर है कि अमित शाह के बिहार दौरे का मूल मकसद हिन्दुत्व के हथियार से जातीय उभार को रोकने की अलग चाल है, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे सूबों में जातीय आधार पर चुनाव कड़वी सच्चाई है। इसलिए भाजपा इसे भी साधने की कोशिश कर रही है। वही बिहार में महागठबंधन में रहते नीतीश कुमार की सरकार ने जातिगत गणना का काम कराया था। इसमें बिहार की कुल आबादी 13 करोड़ से अधिक पाई गई है। जातिगत गणना में एक सबसे

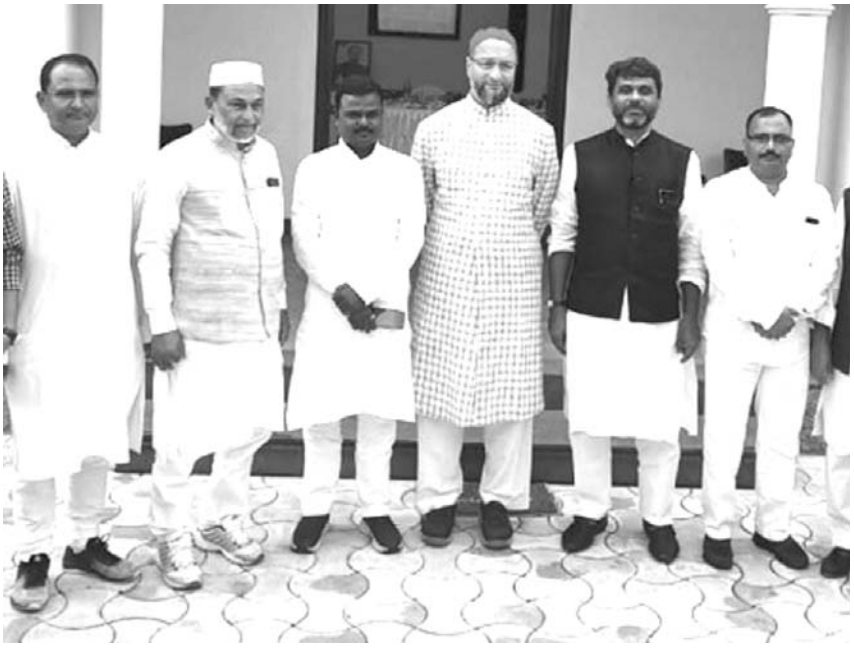

महत्वपूर्ण आंकड़ा ओबीसी का उभर कर सामने आया है, जिसे आधार बना कर नीतीश सरकार ने आरक्षण का दायरा 50 से बढ़ा कर 75 प्रतिशत कर दिया। बिहार में ओबीसी आबादी 63 प्रतिशत (27% पिछड़ा वर्ग, 36% अत्यंत पिछड़ा वर्ग) है। नीतीश के इस कदम को राजनीति में मास्टर स्ट्रोक माना गया था। इसलिए कि आजादी के बाद पहली बार जातिगत सर्वेक्षण का काम किसी सरकार ने कराया है। केंद्र सरकार ने तो पहले ही हाथ खड़े कर दिए थे। कुछ राज्य सरकारों ने कराया भी तो उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए। नीतीश ने अपने बूते यह काम कर दिखाया। हालांकि नीतीश कुमार ने जाति सर्वेक्षण का काम तो कराया, लेकिन भाजपा ने सर्वेक्षण के आंकड़ों पर अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी। सबसे पहले भाजपा ने मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना कर ओबीसी समुदाय को यह संदेश देने की कोशिश की कि ओबीसी में बड़ी आबादी यादव (बिहार में 14 प्रतिशत) समाज को वह कैसे तरजीह देती है। यादवों की आबादी यूपी, बिहार के अलावा हरियाणा और मध्य प्रदेश में भी खासा प्रभाव रखती है। अकेले बिहार और यूपी में ही लोकसभा की 120 ऐसी सीटें हैं, जहां ओबीसी वोटर निर्णायक हैं। मध्य प्रदेश और हरियाणा में ओबीसी के प्रभाव वाली सीटों को जोड़ दें तो यह संख्या 159 हो जाती है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा 118 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बिहार का शायद ही कोई चुनाव क्षेत्र हैं, जहां ओबीसी वोटर निर्णायक भूमिका में नहीं हैं। इनकी 63 प्रतिशत आबादी में जातीय आधार पर देखें तो अकेले यादवों की आबादी 14 प्रतिशत है। बिहार में इंडी अलायंस की नेतृत्वकर्ता पार्टी आरजेडी का जनाधार ही यादव वोटर हैं। आरजेडी

ने 14 प्रतिशत यादव और 18 प्रतिशत मुस्लिम को मिला कर वर्षों पहले एम.-वाई. समीकरण बनाया था, जो आज भी उसकी ताकत बना हुआ है। हालांकि पिछले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) ने अपने उम्मीदवार उतारकर मुस्लिम वोट में सेंध मारी थी। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के पांच उम्मीदवार चुनाव में विजय भी हुए। हालांकि बाद में उनके चार विधायक राजद के साथ हाथ मिला थी। सूत्रों की माने तो 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर ओवैसी अपने 11 उम्मीदवार बिहार में उतारने की तैयारी में हैं। अगर ओवैसी बिहार के मुसलमान वोटरों में अपनी सेंध लगा पाने में सफल होते हैं तो इसका नुकसान इंडी गठबंधन को उठाना पड़ सकता है और इसका फायदा एनडीए को मिल सकते हैं। वही जातीय गणना के आये रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जनता पार्टी बिहार में यादवों पर तो डोरे डाल ही रही है, ओबीसी समुदाय की दूसरी जातियों पर भी उसकी चौकस नजर है।

बहरहाल, राज्य में एनडीए की सरकार बनने के बाद अमित शाह का यह पहला बिहार दौरा था। उनके आगमन से पहले चुनावी रणनीतिकार और जन सुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी नेता पर बड़ा जुबानी हमला किया है। प्रशांत किशोर ने अमित शाह के बिहार पहुंचने से पहले बीजेपी से सवाल पूछा है। लोकसभा चुनाव अभियान के तहत ओबीसी मोर्चा के सम्मेलन में भाग लेने अमित शाह बिहार आ रहे हैं। इससे पहले 2 फरवरी और 6 फरवरी को पीएम मोदी बिहार दौरे पर आए थे। जन सुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज करते हुए कहा कि नीतीश जी पलटूराम हैं। यह बात बिहार का एक-एक बच्चा भी जानता है। मगर ठीक उतना ही बड़ा पलटीमार भाजपा वाले भी हैं। बिहार में आज से कुछ महीने पहले अमित शाह ने लौरिया में एक रैली में लोगों को संबोधित करते हुए चिल्लाकर कहा था कि बिहार का एक-एक आदमी कान खोल कर सुन लें नीतीश कुमार के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। अमित शाह से बेतिया के किसी पत्रकार ने ये सवाल पूछा नहीं था, खुद ही खड़ा होकर चिल्ला रहे थे। बोल रहे थे नीतीश के लिए सारे दरवाजे बंद हैं। लेकिन मौजूदा समय में मजाक क्या हो रहा है? प्रशांत किशोर ने कहा कि मजाक यह हो रहा है कि अमित शाह ने दरवाजा तो ठीक बंद किया पर कुंडी लगाना भूल गए। शायद यही वजह है कि फिर पलट कर नीतीश कुमार उनकी पार्टी के साथ चले गए। उन्होंने पूछा कि बिहार की आज ये दुर्दशा क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि 40

सांसदों का लालच केंद्र के नेताओं को है। बिहार की दुर्गति का कारण आज 50 सांसद बन गए है। 40 सांसदों के लालच में आज देश में कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की हो, ये दल किसी भी हद के पार जाने को तैयार हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा, अति पिछड़ा महासम्मेलन में शामिल होने पटना आ रहे हैं। पालीगंज में इसका आयोजन किया गया है। यही अमित शाह जनसभा को संबोधित करेंगे और प्रदेश के ओबीसी समाज को भारतीय जनता पार्टी का मैसेज देंगे। बिहार में आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा होने के कारण सभी राजनीतिक दलों की नजर ओबीसी और ईबीसी तबके पर लगी हुई है।

गौरतलब हो कि पालीगंज में अमित शाह और बेतिया में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आगमन से पूर्व राजधानी पटना के गांधी मैदान में इंडिया गठबंधन द्वारा जनविश्वास रैली आयोजित की गई, जिसमें जनता का भरपूर समर्थन देखा गया। पटना पटी हुई दिखी और गांधी मैदान खचाखच। इंडिया गठबंधन के नेता के खुशी का ठिकाना नहीं था इस भीड़ को देखकर। हालांकि इससे पूर्व राजद नेता व पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर बिहार के प्रत्येक जिले में जनता के बीच विश्वास बनाने में जुटे दिखे। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने दावा किया है कि इंडिया गठबंधन में शामिल दल गोलबंद होकर आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से हटा देंगे। बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में हुई रैली में लालू यादव ने कहा कि "गठबंधन के साथी गोलबंद होकर इन्हें (बीजेपी को) विदा करेंगे"। विपक्षी दलों की रैली को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने संबोधित किया। विपक्ष के सभी नेताओं ने बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र की एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला। लालू प्रसाद यादव रैली में सबसे आखिर में बोले। वो अपने पुराने रंग में नजर आए। रैली में जुटे समर्थकों से लालू यादव ने पूछा, "दिल्ली पर कब्जा करना है। तैयार हैं ना।" लालू यादव ने कहा कि बिहार की हवा देश की हवा बदल देती है। उन्होंने कहा, "बिहार की हवा मे इतना दम है कि जो बिहार फैसला लेता है वही देश के लोग अनुकरण करते हैं।" उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए में वापस लौटे बिहार के सीएम नीतीश कुमार को निशाने पर लिया। लालू यादव ने कहा कि रैली में जुटी भीड़ को देखकर नीतीश कुमार परेशान हो जाएंगे। "नीतीश कुमार पहली बार निकले तो हमने कोई गाली नहीं दिया, बस कहा कि वो पलटू राम हैं, नहीं पलटना चाहिए था। दोबारा हमसे, तेजस्वी से गलती हो गई, दोबारा ये पलट गए"। लालू यादव ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी 'देश भर में लोगों के बीच नफरत फैला रहे हैं। राम-रहीम के बंदों में नफरत फैला रहे हैं।" अपने भाषण में लालू यादव ने महागठबंधन सरकार में रहते हुए नौकरी देने के मामले में तेजस्वी की तारीफ की और कहा कि 'जब महागठबंधन की सरकार थी वो तेजस्वी से पूछते रहते थे कि आज कितना नौकरी दिया, कितनी भर्ती हुई।'

राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और विपक्षी दलों के बीच विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ नफरत, हिंसा और अहंकार है तो दूसरी तरफ मोहब्बत, भाईचारा और एक दूसरे की इज्जत है। उन्होंने दावा किया, जब तक आप मोदी को नहीं हटाएंगे, इस देश में सुख और समृद्धि नहीं रहेगी। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि किसान दुखी है, नौजवान के हाथ में नौकरी नहीं है। दस साल के उनके कार्यकाल में क्या उपलब्धि है जनता के लिए। हमें उम्मीद है कि यूपी के साथ-साथ बिहार भी बदलाव की राह पर चलेगा। सनद् रहे कि उक्त रैली में तेजस्वी यादव ने कहा कि जहां तक मेरी नजर जा रही है केवल लोग ही लोग नजर आ रहे हैं, दस लाख से ज्यादा लोग आ गए हैं। 3500 किलोमीटर की हम लोगों ने दस दिन में यात्रा की और पूरा बिहार घूमने का काम किया। आप सभी को पटना आमंत्रित किया था, इतनी बड़ी

संख्या में आप लोग आए हैं, आज रिकॉर्ड टूटा है। 17 महीने की महागठबंधन सरकार के कामों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यही गांधी मैदान है, यहां राजनैतिक रैलियां तो होती थी, लेकिन जब तेजस्वी 17 महीने सरकार में था तब नौकरियों का भी रैला यहां हुआ था। यहीं से दो लाख लोगों को नियुक्ति पत्र हमने बंटवाया था। याद दिलाते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि रोजगार मेला और रोजगार रैली हमने इसी धरती पर की है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, सबसे पहली बार आपने किसके मुंह से सुना था दस लाख नौकरी का। पटना में, बिहार में पोस्टर लगवा रहे हैं नीतीश कुमार जी, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन पोस्टर लगवा रहे हैं कि रोजगार मतलब नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब 2020 में हमने वादा किया था कि दस लाख नौकरियों का तब इन्हीं नीतीश कुमार ने कहा था कि कहां से लाएगा पैसा, अपने बाप के पास से लाकर वेतन बांटेगा। हमने दिखाया है कि संभव है, जो उसी मुख्यमंत्री से 17 साल में नहीं हुआ उन्हीं के हाथों 17 महीनों में इसी गांधी मैदान में हमने नियुक्ति पत्र बंटवाए। तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन के साथियों ने विपरीत परिस्थितियों में भी हमारा साथ दिया। इन 17 महीनों में हमने जाति आधारित जनगणना कराई, आरक्षण को 75 प्रतिशत तक किया, हमने दलितों के लिए आदिवासियों के लिए आरक्षण बढ़ाया। जिस काम को आजादी से आज तक किसी सरकार ने नहीं किया था उसे हमने केवल 17 महीनों में कर दिखाया। तेजस्वी ने कहा कि कितना भी दबाएंगे, तेजस्वी खड़ा है आपके साथ, आपको आपका अधिकार दिलाकर रखेगा। अगर आप साथ दोगे तो तेजस्वी आपके लिए मर मिटने को तैयार है। राष्ट्रीय जनता दल को मुसलमानों और यादवों की पार्टी बताने वालों को तेजस्वी यादव ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि माय की पार्टी है, मुसलमान- यादव की पार्टी है, हम कहना चाहते हैं कि ये माय-बाप की पार्टी है।

माई का मतलब :-

M-Muslim

Y-Yadav

बाप का मतलब :-

B-Bahujan

A-Agra

A-Aadhi Abadai यानी महिला और

P-Poor यानी गरीब की पार्टी है। ये ए टू जेड सबकी पार्टी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि आरजेडी का मतलब मोदी जी कुछ भी कहते रहे हैं लेकिन आरजेडी का मतलब है :-

R-Rights यानी अधिकार,

J-Jobs

D-Development

तेजस्वी ने कहा कि हाल के दिनों में आरजेडी के कई विधायकों ने पार्टी का साथ छोड़ा है। उन्हें किसी नेता के जाने से फर्क नहीं पड़ता है। कुछ विधायक इधर से उधर कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जनता को

कहां से खरीदेंगे, जनता जवाब देगी। हमारे पिता ना कभी डरे ना कभी झुके। जब लालू जी नहीं डरे तब उनका बेटा डरेगा? लड़ेंगे आखिरी सांस तक। ये विचारधारा की लड़ाई है। तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर एजेंसियों का इस्तेमाल करने और विपक्ष के नेताओं को डराने के आरोप भी लगाये। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन हुआ, तुरंत सीबीआई के लोग हमारे भाई के पास आ गए, अखिलेश जी को समन भेज दिया। हमारे तो पूरे परिवार को समन भेजा ही, लेकिन हम लोग डरने वाले लोग नहीं है। हम ना डरेंगे ना झुकेंगे, जनता की लड़ाई में जनता के साथ खड़े रहेंगे। तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा। उन्होंने कहा कि बड़े से बड़ा भ्रष्टाचारी बीजेपी में जाता है तो धुल जाता है लेकिन बीजेपी वॉशिंग मशीन के साथ-साथ डस्टबिन वाली पार्टी हो गई है। कूड़ादान हो गई है जिसमें राजनीति का सभी कचरा जा रहा है। सभी पार्टी का कूड़ा बीजेपी में चला जा रहा है। बता दें कि अपने भाषण के दौरान तेजस्वी यादव ने कई बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा कि आप सब लोग जानते हैं चाचा जी पलट गए, लेकिन पलट गए तो जहां भी रहें सुखी हैं। हमारे चाचा तो पलटी मारते ही हैं, लेकिन सम्राट चौधरी भी कम नहीं है, पांच-पांच बार पार्टी बदलते हैं। मोदी जी कह रहे थे कि मोदी की मजबूत गारंटी है। मोदी जी हमारे चाचा का गारंटी लेकर दिखाओ, कोई हमारे चाचा का गारंटी ले सकता है क्या? तेजस्वी यादव ने कहा कि जब चाचा बोल रहे हैं थे कि हम अब कहीं नहीं जाएंगे, जीवन भर यहीं रहेंगे, तब मोदी जी हंस रहे थे, मोदी जी क्यों हंस रहे थे? अरे चाचा जी, आप बुजुर्ग हैं, आपको यहीं से हाथ जोड़कर प्रणाम। लेकिन एक बात कहेंगे, जदयू 2024 में

खत्म हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में दो राजनैतिक रैलियों को संबोधित किया और राजद पर निशाना साधा। गांधी मैदान से पीएम मोदी को जवाब देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि मोदी जी आये थे कल यहां, क्या बोलकर गए, वही जुमला, झूठ प्रचार। मोदी जी झूठ बोलने की फैक्ट्री हैं। आप लोगों ने पिछली बार 40 में से 39 एमपी बीजेपी को जिताया। भाजपा के सांसदों से पूछना कि उनके जिले में भाजपा के लोगों ने क्या किया। क्या मोदी ने कोई कारखाना दिया, कोई नौकरी दी, पलायन रोका, गरीबी मिटाई, महंगाई खत्म की। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना था, वो भी नहीं दे पाये। आप कहते थे कि दो करोड़ रोजगार देंगे, पंद्रह लाख रुपये खाता में देंगे, क्या हुआ? तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा के लोग गोबर को भी गाजर का हलवा बताकर परोस देते हैं। कल आए थे प्रधानमंत्री जी, बोल रहे थे हमारे पिता के बारे में, हमको बोले-अपने पिता का नाम क्यों नहीं लेता है, अपने पिता का काम क्यों नहीं गिनाता है? तेजस्वी यादव ने जवाब देते हुए कहा कि मोदी जी, कान खोलकर सुनिए, इसी बिहार की धरती से हम बोल रहे हैं। कल आपने बोला, उसका जवाब देने आए हैं। चश्मा साफ कर लीजिए, खोलकर ये नजारा देखो। मोदी जी, जरा बताइये, यूपीए कार्यकाल में 90 हजार करोड़ का फायदा रेलवे को हुआ था, आज तक रेलवे को मुनाफा नहीं हुआ था। लालू जी ने 90 हजार करोड़ का मुनाफा रेलवे को दिया। थोड़ा आप बता दें आपने जनता को, रेलवे को कोई मुनाफा दिया या पूंजीपति को दिया? तेजस्वी यादव ने कहा कि मानसिक गुलामी से मुक्ति लालू यादव ने दिलाई। बिहार में गरीबों को उनका हक दिया। सामाजिक न्याय करके दिखाया। 1990 के बाद आज कोई भी गरीब अपने अधिकार के लिए लड़ना जानता है, पिछड़ा लड़ना जानता है, दलित लड़ना जानता है, अल्पसंख्यक भाई लड़ना जानते हैं, ये लालू ने दिया है। वही धर्म और पौराणिक कथाओं को राजनीतिक मंच से दूर रखने वाले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी भी ऐसी कथाओं का हवाला देते हुए कहा कि अमृत मंथन के बाद अमृत का कलश पहले देवताओं को नहीं मिला था। आज भी अमृत का कलश गलत हाथों में चला गया है. हमें मोदी सरकार को हटाना है। ''मोदी हटाओ, देश बचाओ"। कांग्रेस ने भी नीतीश कुमार के पाला बदलने पर उन पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार शरण में चले गए हैं। तेजस्वी के चाचा (यानी नीतीश कुमार) मामू की चाय पीने चले गए। अब वो वापस आएंगे तो उन्हें वापस नहीं लेना है। औरंगाबाद में मोदी की सभा में नीतीश ने भी कहा था कि वो शुरू से बीजेपी के साथ हैं और बीच में गायब हो गए थे, लेकिन अब कहीं नहीं जाएंगे। नीतीश की इस बात पर प्रधानमंत्रा मोदी भी हँस रहे थे और वहाँ मौजूद लोग भी।

बहरहाल, गांधी मैदान में समर्थकों की भारी भीड़ के सामने विपक्षी नेताओं के पास एक मौका जरूर था कि वो केंद्र सरकार को राजनीतिक मुद्दों पर घेर सकते थे, लेकिन इस मामले में विपक्षी नेताओं के पास मुद्दों की कमी दिख रही थी। विपक्ष ने रोजगार के उसी मुद्दे को उठाने की सबसे ज्यादा कोशिश की, जिसे तेजस्वी यादव ने अपना मुद्दा बनाया था। हालांकि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के भाषण में यह कहना कि "देश में जब भी बदलाव आता है तो तूफान बिहार से शुरू होता है। बिहार से ही बदलाव का तूफान पूरे देश में जाता है। आज देश में 40 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। छोटे व्यापारियों के काम बंद हो गए।" राहुल गांधी की इस बात पर गांधी मैदान में जमकर तालियाँ बजीं। दरअसल विपक्षी दलों की कोशिश बिहार में रोजगार को सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाना है। इस मुद्दे पर युवाओं की बड़ी संख्या भी गांधी मैदान में मौजूद दिखी। बता दें कि पटना में हुई महागठबंधन की रैली विपक्षी एकता की पहली बड़ी रैली है। यह पहला मौका भी था जब कई विपक्षी दल एकसाथ केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट हुए थे। पटना में विपक्षी नेताओं ने नौकरी के अलावा जातिगत गणना पर भी बात की, विपक्ष ने हर साल दो करोड़ नौकरी, किसानों की आय दोगुनी, सभी गरीबों को पक्के मकान जैसे मुद्दों पर भी बात की, लेकिन इन सबके विकल्प में उनकी योजना क्या होगी, इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहा गया। विपक्ष के पास बीजेपी के मुकाबले संसाधनों की कमी है और बहुत कम समय में तैयारी करने के बाद भी पटना में लोगों की भारी भीड़ जुटाई गई, इस लिहाज से विपक्ष की रैली काफी सफल दिखती है। केंद्र सरकार के दस साल हो चुके हैं और बहुत से लोगों का मोहभंग भी हुआ है लेकिन वोटरों को अपनी तरफ खींचने के लिए

विपक्ष को कुछ ठोस बातें करनी होंगी। मसलन देश में अगर बेरोजगारी अपने रिकॉर्ड स्तर पर है तो लोगों को रोजगार देने के लिए विपक्षी दलों के पास क्या योजना है, इसकी ज्यादा चर्चा नहीं की गई। दिगर बात है कि किसी नेता या राजनीतिक दल की जनसभा में आमतौर पर उनके समर्थक ही नजर आते हैं। ऐसी सभाओं में लगने वाली भीड़ से यह भी दिखता है कि इलाके में किस दल को कितना बड़ा समर्थन हासिल है। समर्थकों का उत्साह और नेता के चेहरे का भाव यह बताता है कि उसके दावे और जमीनी हकीकत में कितना बड़ा फासला है। बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बिहार में अपनी सभाओं के दौरान अच्छी भीड़ जुटाते नजर आ रहे हैं। तेजस्वी के साथ बड़ी संख्या में बिहार के युवा दिख रहे हैं और उनको अपने पिता लालू प्रसाद यादव के बनाए वोट बैंक का लाभ भी मिल रहा है। इस साल जनवरी में नीतीश कुमार के एनडीए में जाने के बाद से तेजस्वी यादव पहली बार जनता के बीच पहुंचे हैं। 20 फरवरी से वो राज्य अलग-अलग इलाकों के दौरे कर चुके हैं। उनका मकसद बिहार में हाल ही खत्म हो चुकी 'महागठबंधन' सरकार की उपलब्धियाँ गिनाना था। तेजस्वी यादव का दावा है राज्य में 17 महीने की 'महागठबंधन' सरकार, नीतीश कुमार के 17 साल की सरकार पर भारी रही है। तेजस्वी का यह भी दावा है कि उनके सरकार में रहते जो काम हुआ उसका श्रेय आरजेडी को जाता है। वो इसी दावे के साथ राज्यभर में 'जन विश्वास यात्रा' की। इस यात्रा में वो नीतीश कुमार पर भी निशाना साध रहे थे और केंद्र सरकार पर भी हमलावर दिखे। तेजस्वी राज्य सरकार में रहते हुए जातिगत गणना और चार लाख लोगों को नौकरी देने के अपने दावे को दोहरा रहे थे। उनका यह भी दावा है कि इससे देशभर में नौकरी और रोजगार बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है। दरअसल बिहार में सरकारी नौकरी एक बड़ा मुद्दा है। राज्य में रोजगार के अन्य साधनों की कमी में युवाओं की पहली पसंद सरकारी नौकरी ही होती है। तेजस्वी यादव का कहना है कि "नरेंद्र मोदी हर साल दो करोड़ रोजगार देने की बात करते थे, लेकिन लोग देख रहे हैं कि सेना में नौकरी का क्या हाल कर दिया। रेलवे की वैकेंसी की क्या हालत है।" साल 2020 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान तेजस्वी यादव अपनी सरकार बनने पर बिहार में दस लाख सरकारी नौकरी देने का वादा कर रहे थे। हालाँकि उस दौरान नीतीश कुमार एनडीए में थे और तेजस्वी यादव के मुताबिक नीतीश कुमार दस लाख नौकरी को असंभव बता रहे थे। तेजस्वी यादव का आरोप है कि नीतीश कुमार कहते थे कि इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे। बिहार में रोजगार एक ऐसा मुद्दा है जिसको जनता के बीच ले जाने में तेजस्वी यादव सफल नजर आते हैं। बिहार में फिलहाल तेजस्वी यादव जहाँ से गुजर रहे हैं वहाँ उनके और बीजेपी के बीच मुकाबले की बात हो रही है। अगर नीतीश कहीं चर्चा में आ रहे हैं तो बार-बार गठबंधन बदलने की वजह से ही आ रहे हैं। हालाँकि प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता अब भी बहुत से लोगों के बीच बरकरार है। प्रधानमंत्री का काम और उनकी शैली लोगों को पसंद आ रही है। हालांकि तेजस्वी यादव की सभा में एक बात जो स्पष्ट नजर आती है वो ये है कि चाहे आरजेडी के कट्टर समर्थक ही क्यों न हों, उनके मन में तेजस्वी को लेकर बिहार का विधानसभा चुनाव है, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव अभी करीब डेढ़ साल दूर है और उससे पहले अभी लोकसभा चुनाव होने हैं। लोकसभा में फिलहाल बिहार की 40 में से 39 सीटों पर एनडीए का कब्जा है। हालाँकि साल 2019 में हुए पिछले लोकसभा चुनावों के बाद राज्य में साल 2020 में विधानसभा चुनाव हुए थे और विधानसभा में तेजस्वी यादव की पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। उन चुनावों में महज कुछ सीटों के फासले से महागठबंधन को बहुमत नहीं मिल पाया था और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे। वही तेजस्वी यादव ने पिछले चुनावों में भी रोजगार को बड़ा मुद्दा बनाया था और इस बार भी उनके प्रमुख चुनावी मुद्दे में यही है। लेकिन पिछली बार की कमी को दूर करने के लिए उन्होंने आरजेडी को 'एमवाई' के साथ ही 'बाप' का दल बताना शुरू कर दिया है। तेजस्वी यादव अपने नारों और दावों के दम पर जनता को रिझाने की कोशिश में लगे हुए हैं लेकिन बिहार के सियासी मैदान में वो सत्ता पक्ष का मुकाबला करने में अकेले भी नजर आते हैं। हालाँकि नीतीश के एनडीए में शामिल होने के बाद बड़ी संख्या में मुस्लिम और सेक्युलर वोट

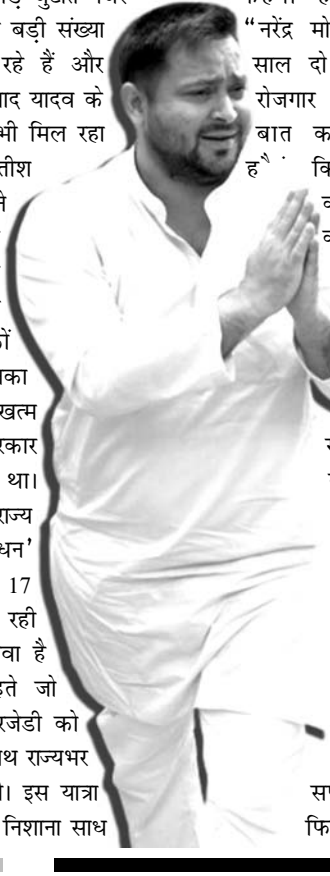

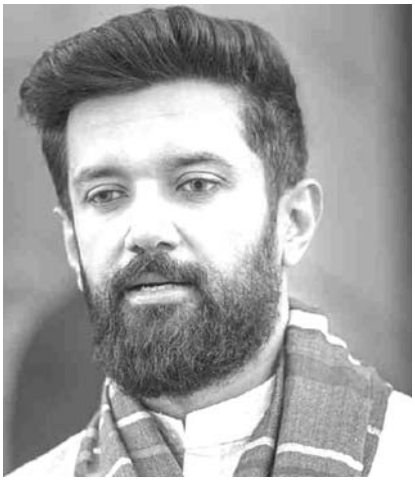

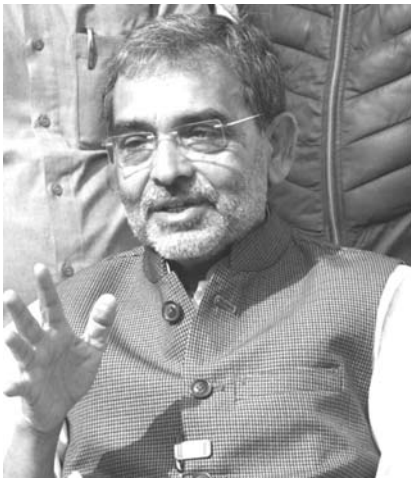

तेजस्वी और विपक्ष के खेमे में नजर आ रहे हैं तो अगर बिहार में सेक्युलर वोटों का बंटवारा नहीं हुआ तो इसका फायदा भी विपक्ष को मिलेगा। तेजस्वी को कुछ अन्य मुद्दों पर भी फायदा मिल सकता है। उनका मुकाबला 'ओल्ड हॉर्स' यानी पुराने नेताओं से दिखता है। इस मामले में वो अपने विरोधियों पर कुछ भारी पड़ सकते हैं। लोकसभा चुनावों के दौरान तेजस्वी यादव को एनडीए से मुकाबला करना है, जो लगातार दो बार चुनाव जीतकर केंद्र की सत्ता पर काबिज है। जाहिर है अगर जनता के बीच सत्ता विरोधी कोई भी रुझान होगा तो इसका फायदा तेजस्वी यादव और महागठबंधन को मिलेगा।

नीतीश कुमार भी करीब दो दशक से राज्य की सत्ता पर काबिज हैं लिहाजा उनके खिलाफ भी अगर एंटी इन्कमबेंसी फैक्टर काम करता है तो इसका सीधा नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है और ऐसा लोकसभा के साथ-साथ विधानसभा चुनावों में हो सकता है। कुछ जानकारों का ये भी मानना है कि नीतीश कुमार अपनी सियासी लोकप्रियता के निचले पायदान की तरफ हैं। हालांकि वर्तमान राजनीतिक समीकरण इशारा करते हैं कि तेजस्वी यादव के लिए चुनाव की राह आसान तो नहीं होगी। कांग्रेस का हाथ और वाम दलों का साथ तेजस्वी के लिए भले ही मौजूद है पर नीतीश के साथ चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के अलावा बीजेपी का वोट है, जिसे मात दे पाना तेजस्वी यादव के लिए आसान नहीं है।

बिहार में 2024 के लोकसभा चुनाव का सियासी पारा चढ़ना शुरू हो गया है। बीजेपी की 'मोदी की गारंटी' वाले नारा और विपक्ष का 'संविधान खतरे में है' का नारा तेजी पकड़ रहा है। 3 मार्च को पटना में विपक्षी इंडिया गठबंधन की पहली संयुक्त रैली में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, सीताराम येचुरी, डी राजा, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेता शामिल हुए। ये साफ है कि कोई भी बिहार से नजर नहीं हटाना चाहता है। यहाँ की 40 लोकसभा सीटें सरकार बनाने के लिए हमेशा अहम रहती हैं। 2019 में एनडीए को यहाँ 39 सीटें मिली थीं। इस बार क्या होगा इन सीटों का? इंडिया अलांयस हो या एनडीए, गुंजाइश दोनों नहीं छोड़ना चाहते हैं। क्या एनडीए के लिए बिहार की जमीन पर फिर से 2019 जैसी जीत दर्ज करना मुश्किल होगा? और अगर होगा तो कितना? ये सवाल इसलिए और भी जरूरी हो जाता है क्योंकि हिंदी भाषी राज्यों में बिहार इकलौता प्रदेश है, जहाँ बीजेपी को कभी मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिल पाई है। आखिर क्यों? इस पर एक लंबी राजनीतिक सामाजिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की चर्चा हो सकती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब नीतीश एनडीए में थे तब इस गठबंधन को 40 में से 39 सीटें मिली थीं। आरजेडी अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी, फिर नीतीश ने एनडीए छोड़कर राजद और कांग्रेस के साथ महागठबंधन का हाथ थामा था। बिहार को ऐसे राज्य के तौर पर देखा गया जहाँ बीजेपी को विपक्षी गठबंधन से कड़ी चुनौती मिल सकती थी, बावजूद इसके कि ओपिनियन पोल भाजपा की जीत की भविष्यवाणी कर रहे हैं। नीतीश का इंडिया ब्लॉक में होना उसे मजबूती दे रहा था। सामाजिक जोड़-तोड़ की राजनीति में माहिर नीतीश कुमार के जाति जनगणना के नतीजे घोषित करने को एक मास्टरस्ट्रोक बताया जा रहा था, जिससे उनकी चर्चा राष्ट्रीय तौर पर हुई। ओबीसी वोट बैंक का एक बड़े हिस्से को अपनी ओर खींचने वाली भाजपा ऐसा लगा कि

बैकफुट पर दिखी। पश्चिम और उत्तर भारत के हिंदी भाषी राज्यों जैसे हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आदि में एनडीए पहले ही सियासी रूप से शीर्ष पर है जबकि दक्षिण में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद लिए बीजेपी के लिए बिहार में अच्छे प्रदर्शन का दोहराना जरूरी था, फिर नीतीश कुमार ने विपक्ष को छोड़कर एक बार फिर से बीजेपी का दामन थाम लिया। प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक रैली (02 मार्च, औरंगाबाद) में ठहाकों के बीच नीतीश कुमार ने कहा कि हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर-उधर होने वाले नहीं हैं। हम रहेंगे आप ही के साथ। जानकारों के मुताबिक ये बिहार में समाजवाद का लंबा इतिहास है, जिसने बीजेपी को अपने बल पर सत्ता से अभी तक दूर कर रखा है। जेपी आंदोलन से निकले बिहार के नेताओं का पिछले तीन दशकों से बिहार की राजनीति में बोलबाला रहा है। समाजवादी नेताओं की लंबी सूची में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का नाम भी जुड़ा। नीतीश को समाजवाद के क्लासिक फ्रेम में रखना ही गलत है। ये 1994 में खत्म हो गया था। नीतीश सत्ता की राजनीति करते हैं। उनका बैकग्राउंड समाजवाद का है और इसलिए बहुत सी बातें आपकी आदत बन जाती हैं और जब आपकी ट्रेनिंग जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर के यहां से हुई हो, तो आप जहरीले सांप्रदायिक नहीं हो सकते हैं।

बहरहाल, जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार के सियासी पाला बदलने से बिहार में सत्ता का स्वरूप ही नहीं बल्कि गठबंधन का समीकरण ही बदल गया है। नीतीश के महागठबंधन में रहते हुए चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में मजबूत पिलर माने जा रहे थे, लेकिन जेडीयू की एंट्री होते ही सारा खेल बदलता नजर आ रहा था। जेडीयू और बीजेपी अपनी-अपनी जीती लोकसभा सीटें छोड़ने लिए तैयार नहीं थी, जिसके चलते चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा को सीटें हासिल करने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही थी तो जीतनराम मांझी की गया लोकसभा सीट की मनोकामना पर भी संकट गहराया हुआ दिखा। इसके चलते एनडीए में सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा था। बिहार में बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर जबरदस्त तरीके से पेंच फंसा हुआ दिख रहा था। सूबे में 40 लोकसभा सीटें है, जिसमें से 39 सीटों पर एनडीए का कब्जा है। 2024 के चुनाव में सूबे की सभी 40 सीटों को जीतने का प्लान बीजेपी ने बना रखा है, जिसके लिए नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी की पटकथा लिखी गई। नीतीश के आने से बिहार में एनडीए का सियासी समीकरण जरूर मजबूत हुआ है, लेकिन साथ ही कुशवाहा-चिराग-मांझी की सियासी उम्मीदों पर ग्रहण लगता नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि इसी कारण चिराग पासवान ने बिहार में पीएम मोदी की दोनों रैलियों से दूरी बनाए रखा,

लेकिन दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। ज्ञात हो कि 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन का हिस्सा बीजेपी, जेडीयू और अविभाजित एलजेपी थी। बीजेपी और जेडीयू ने 17-17 सीटों पर चुनाव लड़ा था जबकि 6 सीटों पर एलजेपी चुनाव लड़ी थी। बीजेपी अपनी सभी 17 सीटें जीत गई थी जबकि जेडीयू को 16 सीटों पर कामयाबी मिली थी। एलजेपी अपने कोटे की सभी 6 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। इस बार एनडीए गठबंधन में बीजेपी, जेडीयू, जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम के अलावा एलजेपी के दोनों धड़े शामिल हैं। इस तरह एनडीए का कुनबा बड़ा हो गया है, लेकिन सभी अपने-अपने डिमांड से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। इसके चलते सीट शेयरिंग पर पेच फंसा था। बीजेपी बिहार में भले ही भाई की भूमिका में रहना चाहती है, लेकिन जेडीयू 2019 में जीती हुई सीटों को छोड़ना नहीं चाहती है। जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा इस बार एनडीए में टिकट के नए दावेदार हैं तो एलजेपी के दोनों धड़े पिछली बार से कम सीटों पर मानने को तैयार नहीं थे। बीजेपी को बड़े भाई की भूमिका में एनडीए के सभी सहयोगी चाहते हैं, लेकिन अपनी हिस्सेदारी छोड़ने को भी कोई तैयार नहीं था। एनडीए में नीतीश कुमार की गैरमौजूदगी में उपेंद्र कुशवाहा 2014 में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, तब उन्हें तीन सीटें मिली थी। कुशवाहा तीनों सीटों जीतने में कामयाब रहे थे। वही बता दें कि नीतीश 2022 में महागठबंधन में शामिल हुए तो कुशवाहा ने जेडीयू से बगावत कर एनडीए का हिस्सा बन गए। चिराग पासवान ने भी एनडीए के साथ खड़े हो गए, वो भी तब जब उनके चाचा पशुपति पारस उनसे पार्टी छीनकर मोदी सरकार में मंत्री बन गए थे। चिराग को लगा था कि फिर से एनडीए में रामविलास पासवान की तरह रुतबा हासिल हो जाएगा। कुशवाहा ने तीन लोकसभा सीटों के साथ केंद्र में मंत्री पद की

उम्मीदें पाल रखी है तो चिराग पासवान ने भी छह सीटों की डिमांड कर रहे थे, लेकिन नीतीश के पाला बदलते ही दोनों ही नेताओं का सारा गणित बिगड़ गया है। एनडीए में चिराग पासवान और पशुपति पारस को छह सीटें देने की बात चल रही थी, लेकिन भाजपा शीर्ष ने पांच सीटें चिराग पासवान की पार्टी को दे दी गई, वही पारस का 40 लोकसभा सीटों में से किसी एक पर भी का जिक्र होता नहीं दिखा। सनद् रहे कि चाचा और भतीजे दोनों के बीच हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर जो लड़ाई चल रही थी, उस पर भी चिराग के नाम की मुहर लग गई। हालांकि पशुपति पारस हाजीपुर से वर्तमान सांसद हैं, लेकिन चिराग पासवान ने भी अपने दिवंगत पिता रामविलास पासवान की विरासत का हवाला देते हुए हाजीपुर सीट पर अपना दावा ठोक रखा था। बिहार की हाजीपुर लोकसभा सीट पर चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान के बीच शह और मात का खेल चल रहा है। इस खेल में लोजपा रामविलास के मुखिया चिराग भारी पड़ते नजर आ रहे हैं।

सूत्रों के अनुसार एनडीए के सीट बंटवारे में केंद्रीय मंत्री एवं रालोजपा प्रमुख पारस को अपनी सीटिंग सीट हाजीपुर गंवानी ही पड़ी और तो और पारस के बगावती तेवड़ ने उन्हें एनडीए का अब हिस्सा भी नहीं रखा है। बिनोद तावड़े की प्रेस वार्ता के बाद सीट शेयरिंग पारस की लोजपा का कही जिक्र भी नहीं है। हालांकि सीट शेयरिंग से पूर्व चिराग भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा से मुलाकात किये थे, मुलाकात के बाद हाजीपुर सीट को लेकर पूछे गये पत्रकारों के सवालों पर चिराग के चेहरे पर सांकेतिक खुशी बयां कर रही थी की यह सीट पर सहमती बन गई है। अलबत्ता चाचा-भतीजा के बीच खींचतान के बीच भतीजा चिराग पासवान भारी भी पड़ गये। ऐसा तब है जबकि पशुपति कुमार पारस ने दावा किया था कि वे हर हाल में हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का भी कहना था कि दुनिया की कोई ताकत उन्हें हाजीपुर से दूर नहीं कर सकती है। ऐसे में सीटों की इस दावेदारी में पारस को अगल-बगल खिसकने की नौबत आयी तो दूसरे भतीजे की सीट भी इसमें फंस सकती है क्योंकि दूसरा भतीजा समस्तीपुर से सांसद हैं और अब तो एनडीए की मुहर हाजीपुर के साथ-साथ समस्तीपुर पर भी लोजपा रामविलास यानी चिराग को मिल चुकी है। ऐसे में पशुपति पारस ने एनडीए से विद्रोह करने की ठान ली है। बताते चले कि पशुपति पारस के

आवास पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। इसमें फैसला लिया गया कि पार्टी के वर्तमान सांसद अपनी सीटों से चुनाव लड़ेंगे। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए पशुपति कुमार पारस ने कहा कि मीडिया के माध्यम से आई खबरों के मुताबिक हमारी पार्टी को तरजीह नहीं दी जा रही है। इससे हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं में निराशा है। हमारा आग्रह है कि हमारी पार्टी के 5 सांसदों पर फिर विचार करें। अगर हमें उचित सम्मान नहीं दिया गया तो हमारी पार्टी कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है। मैं हाजीपुर से चुनाव लड़ूंगा। प्रिंस राज समस्तीपुर से और चंदन सिंह नवादा से चुनाव लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन के नेताओं से हमारी कोई बात नहीं हुई है। हम अभी वेट एंड वॉच कर रहे हैं, पर जिस तरह से हमारी पार्टी को तरजीह नहीं दी गयी है, कार्यकर्ता और नेता इससे निराश हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो पशुपति पारस ने बिहार एनडीए में बगावत कर दी है। हालांकि गेंद उन्होंने बीजेपी के पाले में डाल दी है। अब बीजेपी की इसपर क्या प्रतिक्रिया रहती है यह देखने वाली बात होगी।

बताते चले कि सीट शेयरिंग के फैसले से पूर्व भाजपा नेताओं ने एनडीए सहयोगियों से मान-मन्नोवल के लिए मुलाकात दर मुलाकात की। वहीं दूसरी तरफ कुशवाहा, नीतीश से बगावत करके एनडीए के साथ आए थे, उन्हें तीन सीटों की उम्मीद थी किन्तु एक सीट पर ही उन्हें संतोष करना होगा। हालांकि माना जा रहा था कि बीजेपी उन्हें अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाना चाहती है। ज्ञात हो कि एनडीए में सीट शेयरिंग का मामला न सुलझने के चलते चिराग पासवान ने बिहार में पीएम मोदी के कार्यक्रम में शरीक नहीं हुए थे। इतना ही नहीं बीजेपी के 'मोदी का परिवार' अभियान में भी चिराग शामिल नहीं हुए जबकि खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताया करते थे। बताते चले कि 10 मार्च को चिराग ने मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज में रैली की। रैली में भारी भीड़ थी। चिराग भी जोश में थे लेकिन बयान उन्होंने बहुत सोच-समझकर दिया। चिराग पासवान ने कहा था कि मैं यहां मीडियाकर्मियों की भीड़ देख रहा हूं, जो यह जानने के लिए उत्सुक है कि चिराग पासवान किसके साथ हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि चिराग पासवान केवल बिहार के लोगों के साथ हैं। चिराग पासवान का गठबंधन सिर्फ बिहार की जनता के साथ है। हर पार्टी, हर गठबंधन चाहता है कि चिराग पासवान उसके पक्ष में हो। ऐसा इसलिए है, क्योंकि लोग 'बिहार पहले बिहारी पहले' वाली नीति से प्रभावित हैं, जो कि राज्य को पुराने पिछड़ेपन से बाहर निकालना चाहते हैं। चिराग के शब्दों पर गौर किया जाए तो वो चाहते तो गठबंधन के पार्टनर के तौर पर एनडीए का नाम ले सकते थे। वो चाहते तो बीजेपी का भी नाम ले सकते थे क्योंकि पिछले तीन साल से वो खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते रहे हैं। लेकिन उन्होंने गठबंधन का पार्टनर बिहार की जनता को बताया। लगे हाथ ये भी बता दिया कि हर गठबंधन को उनकी जरूरत है। चिराग की इन्हीं बातों ने उनके अगले कदम को लेकर सस्पेंस बढ़ा दिया। चिराग पासवान अपनी सियासी बाजी बहुत संभलकर खेल रहे हैं। हालांकि समझा जाता है कि एनडीए में नीतीश की वापसी के बाद से ही चिराग पासवान नाराज हैं। नीतीश कुमार के एनडीए में आने के बाद बीजेपी चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा को बहुत खास तवज्जो नहीं दे रही थी। इसके अलावा जीतन राम मांझी का भी मामला उलझा हुआ था, क्योंकि वो जिस गया सीट पर दावेदारी कर रहे हैं, वो सीट अभी नीतीश कुमार की पार्टी के पास है। जेडीयू अपनी सीटिंग सीट किसी भी सूरत में नहीं छोड़ना चाहती है। जिसकी वजह से चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा बेबस नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें विपक्षी खेमे के साथ भी बहुत ज्यादा सियासी फायदा नहीं दिख रहा था। सूत्रों की मानें तो नीतीश कुमार के आने से पहले तक एनडीए में सीटों को लेकर ज्यादा पेच नहीं था, लेकिन नीतीश कुमार की वापसी के बाद पूरा गणित प्रभावित हो गया।

गौरतलब हो कि बिहार में लोकसभा के साथ ही विधानसभा के चुनाव भी हो जाए, आजकल बिहार के सियासी गलियारे समेत मीडिया

में भी ऐसी चर्चाएँ सुनने को मिल रही हैं। तो क्या इन चर्चाओं का कोई आधार है या ये बस ऐसे ही अफवाहें भर हैं? यकीनन, ये चर्चा आधारहीन नहीं है। क्योंकि लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान हो चुका है किन्तु कुछ दिनों पहले तक ऐसी चर्चाएं जरूर उठी थी। कुछ तो है, जिसका डर है, जिसकी पर्दादारी है दबे-छिपे चर्चा यही है कि नीतीश कुमार की हार्दिक इच्छा है कि लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव भी करवा दिए जाएं, बस बात बनने भर की देर है। बात बननी भी है तो भाजपा आलाकमान से, जिसे अगर अपना फायदा नजर आया तो, वे भी आसानी से तैयार हो जाएंगे। सिर्फ ये मान लेना कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी में टूट के डर से भाजपा के साथ चले गए, बेवकूफी होगी। ललन सिंह और राजद के जरिये जद(यू) में टूट की खबरें मीडिया में प्लांट करवाई गयी थी, नीतीश कुमार को भयभीत करने के लिए और ऐसी खबरें प्लांट करवाने वाले लोगों को यह अच्छे से पता था कि पिछले कुछ समय से नीतीश कुमार को अपने अलावा किसी पर भरोसा नहीं रहता। किसी पर नहीं मतलब किसी पर नहीं। यहाँ तक कि आरसीपी सिंह, उपेन्द्र कुशवाहा और ललन सिंह जैसे अपने नजदीकी लोगों पर भी नहीं और इसका असर भी हुआ। पहले नीतीश कुमार ने ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया और फिर महागठबंधन से नाता तोड़ भाजपा के साथ चले गए, हालांकि, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर भाजपा के साथ वे किन शर्तों पर गए? क्या महज 17 लोकसभा सीटों के लिए, जो संभवतः राजद के साथ रहते हुए भी उन्हें मिल सकता है, या एकाध सीटें कम मिलती। निश्चित ही इस डील की सबसे बड़ी शर्त यह रही होगी कि अगला 5 साल एक बार फिर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर मिले। नीतीश कुमार यही चाहते रहे होंगे कि वे लोकसभा चुनाव में भाजपा को फायदा पहुंचाएं और विधानसभा चुनाव में भाजपा उन्हें एक बार फिर अगले 5 साल के लिए बड़े भाई की भूमिका में देखे। यह डील मानना भाजपा के लिए इतना आसान होगा? दूसरी तरफ नीतीश कुमार इंडिया एलायंस के निर्माण के दौरान ही सार्वजनिक घोषणा कर चुके थे कि 2025 का चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इंडिया एलायंस में भाव न मिलने, यथोचित पद या सम्मान न मिलने (पीएम पद का उम्मीदवार) से वे आहत थे। हालांकि, इंडिया अलायंस के निर्माण में उनकी महती भूमिका को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन, कांग्रेस ने इस मोड पर आ कर ओबीसी कास्ट सर्वे, आरक्षण सीमा बढाने जैसे नीतीश कुमार के मुद्दे को लपक लिया और यहां पर नीतीश कुमार ने खुद को ठगा महसूस किया। बिहार में शिक्षक भर्ती और के.के. पाठक का मसला महागठबंधन को भारी पड़ सकता है। क्रेडिट लेने की जो होड़ मची, उससे भी नीतीश कुमार को लगा कि वे इस रेस में पीछे छूट गए हैं। हालांकि यह भी सच है कि 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा तेजस्वी यादव ने ही अपने चुनावी घोषणापत्र में किया था, जिस वजह से बिहार के विगत विधानसभा चुनाव का पूरा माहौल ही बदल गया था। राजद से नाता तोड़ने के बाद, तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा और रैली में जिस तरह से भीड़ जुटी है, उसे देखते हुए भी नीतीश कुमार का आत्मविश्वास कहीं न कहीं डोला है और अब वे चाहते होंगे कि जल्द से जल्द लोकसभा के साथ ही विधानसभा के भी चुनाव हो जाए। वही नीतीश कुमार को किसी पर भरोसा नहीं और भाजपा के लिए अब नीतीश कुमार को बड़े भाई के रूप में स्वीकारना आसान नहीं, ऐसे में नीतीश कुमार दोनों चुनाव एक साथ करवा कर गिव एंड टेक फार्म्यूला पर काम करना चाहते है और उसके बाद भी उनके पास पाला बदलने का ऑप्शन रहेगा, लेकिन, क्या भाजपा के लिए यह इतना आसान होगा? बिल्कुल नहीं। बिहार में नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से भाजपा और राजद के बीच बफर स्टेट की भूमिका में रहे हैं। भाजपा यह अच्छी तरह जानती है कि नीतीश कुमार अभी अपने राजनीतिक करियर के सबसे बुरे और कमजोर दौर से गुजर रहे है। नीतीश कुमार को भी इस बात का एहसास है कि उनके जूनियर (पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव) अब काफी परिपक्व हो चुके हैं और तकरीबन मास लीडर में कनवर्ट हो चुके हैं। आगे बिहार की लड़ाई राजद बनाम भाजपा की ही होने वाली है, फिर नीतीश कुमार इस बात को भी कैसे भूल सकते है कि उनके मौजूदा साथी (भाजपा) ने पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान चिराग पासवान के जरिये उन्हें और अधिक कमजोर बना दिया था, वह भी साथ चुनाव लड़ते हुए। तो फिर 1 साल बाद होने वाले बिहार विधान सभा चुनाव से पहले भाजपा न जाने क्या-क्या कर सकती है? यह अन्देशा नीतीश कुमार को है, इसीलिए वे भीतर ही भीतर यह चाहते होंगे कि दोनों चुनाव एक साथ हों लेकिन भाजपा फिलहाल लोकसभा चुनाव पर फोकस्ड है। उसका लक्ष्य यही होगा कि वह ओबीसी कास्ट सेन्सस, ओबीसी आरक्षण जैसे मुद्दों की सवारी कर बिहार से 40 के 40 सांसद जीत कर आए, विधानसभा की बाद में देखेंगे, लेकिन नीतीश कुमार अगर 17 के 17 लोकसभा सीटें जीत भी जाते हैं तो उनके हाथ क्या आएगा? 2025 में उनके हाथ में क्या मुख्यमंत्री का पद रहेगा? यह सवाल नीतीश कुमार को परेशान कर सकता है, बल्कि परेशान कर रहा है।●

टीकट नहीं मिलने पर नेताओं के मिजाज बदले लोकसभा चुनाव 2024

● संजय सिन्हा

ऐसे तो सभी दलों के नेताओं को पार्टी टिकट नहीं मिलने पर उनके असली चरित्र सामने आता रहा है, पर इस 2024 के आम चुनाव में भाजपा के नेताओं का असली चेहरा सामने आ रहा है, अभी मात्र बीजेपी के 195 सीटों के नाम का ऐलान होने पर भारत के कद्दावर नेता अपनी लटकी हुई चेहरा लेकर सामने आ गयें हैं, भारत के नंबर एक चांदनी चौक लोकसभा के वर्तमान सांसद डाक्टर हर्षवर्धन सन्यास लेने का एक्स पर घोषणा कर दिया, डाक्टर हर्षवर्धन पांच बार विधायक दो बार सांसद रहे उन्होंने दिल्ली सरकार में एवं भारत सरकार में मंत्री रहे हैं, वही पूर्वी दिल्ली से क्रिकेटर सांसद गौतम गंभीर भी अपने को फिर से क्रिकेट में रुचि लेने की बात कही हैं, गौतम गंभीर न तो अपने क्षेत्र में जाते थे और न ही जनता से मिलते थे, सबसे मजे की बात है कि झारखंड से हजारीबाग के लोकसभा सांसद और पूर्व बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता व वित्त एवं विदेश मंत्री रहे यशवंत सिन्हा के पुत्र जयंत सिन्हा ने शक्रिय राजनीति से अलग होने की बातें कही है, परंतु बीजेपी और सरकार

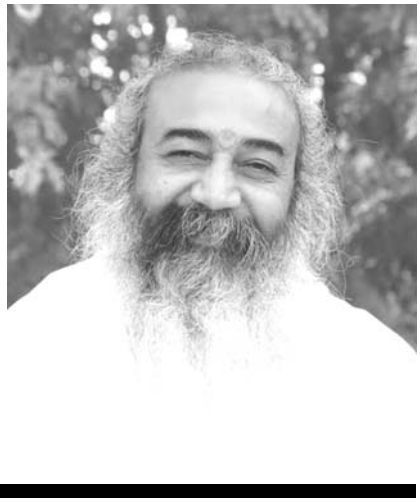

के साथ रहने की बातें भी कह डाली हैं, उन्होंने कहा है कि मैं जलवायु परिवर्तन पर काम करता रहूंगा अगर गाँव की भाषा में कहा जाये कि मिस्टर सिन्हा सिर्फ अपने पिताजी को परिवर्तन कर लिया होता तो आज दोनों बाप बेटे मोदी सरकार में मजा काट रहे होते शायद कोई मंत्री तो कोई राज्यपाल होतें? परंतु यहाँ पर पुरी तरह जयंत सिन्हा फेल हो गयें और अपने पिता को विपक्षी हीत में परिवर्तन होने से बचा नहीं पाये? बिहार में एक कहावत है कि 'रोटियो गईल और टीकड़ीयो', यही हाल इस जयंत सिन्हा पिता-पुत्र को हो गई, बिहार के एक और नेता कम अभिनेता ज्यादा हैं शत्रुध्न सिन्हा दर-दर भटक रहे हैं कि कोई तो हमें कमसे कम सांसद तो बना दें? शत्रुघ्न सिन्हा का सभी समाज में एक अच्छी समान थी जो अब बिल्कुल नहीं है, आज श्री सिन्हा बंगाल में चिल्ला चिल्लाकर कर बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी ही सबसे अच्छा उम्मीदवार प्रधानमंत्री की हैं, क्या आज बंगाल की स्थिति कैसी है? संदेशखाली में क्या हो गया उन्हें मालूम नहीं क्या? ऐसे नेता यही सब नहीं है? वो सभी नेता भी है जो कभी कांग्रेस में थे अब अपने लिए बीजेपी में आ गयें हैं, कल तक नौटंकीबाज सन्यासी प्रमोद कृष्णन, कोमेडी ज्यादा क्रिकेटर कम नवजोत सिंह सिद्धू बीजेपी में आने के लिए बहुत पैतरा बना रहा है परंतु बीजेपी उन्हें नहीं ले रहीं हैं, ऐसे नेता के बोल तुरंत बदल जातें हैं, जबकि जनता इतना जल्दी बदलने को तैयार नहीं होती, अभी तो बहुतों नेताओं के भाषा रंग बदलेगें जैसे जैसे टिकट के लिए नाम की घोषणा होगी, इसबार होली में रंगों के साथ साथ नेताओं के रंग बदल देखने को मिलेगा।●

अभी कलम उठाइये

आपके सामने हो रहे भ्रष्टाचार एवं अपराध की खबर की समीक्षा करें और सरकार सहित पुलिस-प्रशासन तक उसको पहुंचाने के लिए केवल सच पत्रिका के साथ जुड़े। खबर की जानकारी इस नम्बर पर दें

सम्पर्क करें:- 9431073769/9955077308

ई-मेल:- editor.kstimes@rediffmail.com पर भेजें।

स्वास्थ्य विभाग को दाग ही अच्छे लगते हैं!

पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह ने कहा नीतीश कुमार सरकार नहीं गिरोह चला रहे हैं

● शशि रंजन सिंह/राजीव शुक्ला

नीतीश कुमार की सरकार को स्वास्थ्य विभाग में दाग ही अच्छे लगते हैं। यह हम नहीं कह रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग खुद कह रहा है। चाहे मामला बिहार के सबसे बड़े अस्पताल PMCH के अधीक्षक आई०एस० ठाकुर का हो या पटना आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल के प्राचार्य संपूर्णानंद तिवारी का हो, BMSICL के उप महाप्रबंधक (परियोजना) सागर जयसवाल का, विशेष कार्य पदाधिकारी रेणु कुमारी, औषधि निरीक्षक शंभुनाथ ठाकुर और कई ऐसे उदाहरण हैं, जिनको स्वास्थ्य विभाग ने कई आरोप प्रमाणित होने के बावजूद उन्हे सेवा विस्तार, पदोन्नति सहित कई तरह के लाभ से पुरस्कृत किया है। बिहार के सबसे दागदार पदाधिकारी डॉ० आई० एस० ठाकुर, जिन पर अभी भी विभागीय कार्रवाई लंबित है, को खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विशेष शक्ति का प्रयोग करते हुए स्वास्थ्य मंत्री के अनुपस्थिति का फायदा उठाते हुए अपने हस्ताक्षर से आनन-फानन में सेवा विस्तार कर दिया। अब तो नीतीश कुमार को सुशासन पर बोलने का हक ही समाप्त हो गया है।

सुधाकर सिंह

डॉ० आई० एस० ठाकुर, मास्टर ऑफ सर्जरी की डिग्री फर्जी और पी.एच.डी. की डिग्री फर्जी तरीके से ली, निलंबित भी हुए, अभी भी इस मामले में विभागीय कार्रवाई लंबित है। वही पटना आयुर्वेदिक कॉलेज के प्राचार्य डॉ० संपूर्णानंद तिवारी की अस्नातक, BAMS से लेकर सभी डिग्री फर्जी साबित हो चुकी है। BMSICL के उप महाप्रबंधक सागर जयसवाल के खिलाफ कई आरोप है। यहाँ तक कि विधानसभा में मंत्री को गलत जवाब भेजने का भी आरोप है। विशेष कार्य पदाधिकारी रेणु कुमारी का विभागीय लापरवाही के कारण वेतन बंद है। औषधि निरीक्षक शंभुनाथ ठाकुर पर फर्जी हस्ताक्षर से औषधि अनुज्ञप्ति निर्गत करने का आरोप है। बावजूद इसके पदोन्नति मिल रही है। BMSICL में अनुमानत: किसी उप महाप्रबंधक को एक से दो जिले आवंटित होते हैं, लेकिन सागर जयसवाल को मोतिहारी, बेतिया, दरभंगा और मधुबनी जिले आवंटित किये गये हैं। विशेष कार्य पदाधिकारी

रेणु कुमारी अभी स्वास्थ्य विभाग की सर्वे-सर्वा हैं और पूरे स्वास्थ्य विभाग में स्थानांतरण, पदोन्नति से लेकर नियुक्ति तक में इनका अहम योगदान है। औषधि निरीक्षक शंभुनाथ ठाकुर को एक के बदले दो क्षेत्र आवंटित किये गये हैं और उनको पदोन्नत करके सहायक औषधि नियंत्रक बना दिया गया।

PMCH के जबरन बनाये गये अधीक्षक आई० एस० ठाकुर का विवादों से नाता रहा है। डॉ० ठाकुर पर कई गंभीर आरोप है। डॉ० ठाकुर बिस्फी प्राथमिक केन्द्र में पदस्थापित थे, उसी दरम्यान उन्होंने फर्जी तरीके से लखनऊ, उत्तर प्रदेश का आवासीय प्रमाण पत्र बनाकर किंग जॉर्ज अस्पताल, लखनऊ से एम.एस. की डिग्री प्राप्त किये। मजेदार बात यह है कि इस अवधि का उन्होंने वेतन और छात्रवृति दोनों लिया। इन्होंने फर्जी तरीके से पी.एच.डी. डिग्री भी प्राप्त की। उन्हें अपने पदोन्नति के लिए पटना उच्च न्यायालय भी जाना पड़ा। पटना उच्च न्यायालय CWJC No. – 3459 of 1994 में इनके अधिवक्ता पी.के. शाही थे, जो वर्तमान में बिहार के महाधिवक्ता भी हैं। इस मामले में डॉ. महानंद सिंह ने पटना उच्च न्यायालय में LPA दायर किया (LPA No. – 173/1994), जिसमें इनके पी.एच.डी. डिग्री पर कोर्ट में मामला गड़बराने लगा, तब इन्हें अपनी पी.एच.डी. डिग्री का दावा वापस लेना पड़ा। यह LPA डॉ० महानंद सिंह द्वारा दायर की गई थी, जो कि याचिका संख्या-CWJC NO. – 3459 of 1994 के इनटरमेनर थे। विद्वान और तेज-तर्रार अधिवक्ता ने इनकी पी.एच.डी. की डिग्री कोर्ट में फर्जी साबित होने से बचा ली। डॉ. (प्रो.) इंद्र शेखर ठाकुर जी के द्वारा डॉ० विनोद पासवान, जुनियर स्नातकोत्तर छात्र को जेनरल सर्जरी विभाग, पी.एम.सी.एच. पटना का एम.एस. जेनरल सर्जरी के पेपर के परीक्षा में कम अंक देकर जान बूझकर असफल कर प्रताड़ित किये जाने का मामला भी प्रकाश में आया था। डॉ० ठाकुर जी के ऊपर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के द्वारा 20/07/2019 को मामले में कार्रवाई की गई थी, जिसके आलोक में प्रार्थी डॉ० विनोद पासवान को विषयातंर्गत पेपर में सफल किए जाने की सूचना है। यह प्रार्थी का डॉ० इन्द्र शेखर ठाकुर जी के विरूद्ध लगाए गए आरोप की पुष्टि करता है। मामले में डॉ० प्रोफेसर ठाकुर जी के विरूद्ध नीतिसंगत कार्रवाई अपेक्षित है, लेकिन अभी तक डॉ० ठाकुर जी के विरूद्ध किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि विभागीय कार्रवाई हेतु प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, कुलपति, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना एवं प्राचार्य पी.एम.सी.एच. को भी निर्देश दिया गया था, लेकिन अपने आप को मजलुमु की सरकार कहने वाले नीतीश कुमार की सरकार ने राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के फैसले को भी रद्दी की टोकड़ी में फेंक दिया

निबंधन संख्या पी०टी०-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 आश्विन 1945 (श०)
(सं० पटना 829) पटना, शुक्रवार, 13 अक्तूबर 2023

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना
13 अक्तूबर 2023

बिहार गजट (असाधारण), 13 अक्तूबर 2023

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 829-571+500-डी०टी०पी०।
Website: http://egazette.bih.nic.in

Case Status https://patnahighcourt.gov.in/CaseStatus/QUIQzAxMDM5ODQ

Skip to main content || Screen Reader Access || Text Size A+ | A | Select Theme A A

Home | About Us | Calendar | Cause List | I.T. Activities | E-Filing Guide | Search

PRESENT STATUS OF CASE : CWJC-3459/1994

Case Number :	CWJC-3459/1994	Date of Filing :	08-Apr-1994
Subject :		Registration Date :	08-Apr-1994
District :	Patna		
Petitioner :	DR.INDRA SHEKHAR THAKUR	Petitioner Advocate :	P.K.SHAHI
Respondent :	STATE and ORS	Respondent Advocate :	Y.KISHORE SC7
Purpose :		Present Status :	DISPOSED
Current Position :		Action Date :	24-Nov-1994
Court :			

DOCUMENTS RECEIVED
NO DOCUMENTS RECEIVED

LIST OF ADDITIONAL PETITIONERS
NO RECORDS

LIST OF ADDITIONAL RESPONDENTS
NO RECORDS

ADDITIONAL ADVOCATES DETAILS
NO RECORDS

LIST OF OBJECTIONS
NO RECORDS

CASE PROCEEDINGS HISTORY
NO RECORDS

IA FILING DETAILS
NO RECORDS

AO FILING DETAILS
NO RECORDS

FAX STATUS
----------ADDITIONAL FAX DETAIL----------

CERTIFIED COPY STATUS
NO RECORDS

FEE DETAIL
NO RECORDS

CERTIFIED COPY STATUS(ON WINDOW)
NO RECORDS

ORDERS

JUDGEMENTS
Record Not Found

1 of 2 22/03/2024, 18:57

U.12012/06/2024-ME-I(Pt.1) (FTS No. 8262110)
भारत सरकार / Government of India
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय / Ministry of Health & Family Welfare
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग / Department of Health & Family Welfare
(चिकित्सा शिक्षा–I/ Medical Education-I)

Nirman Bhawan, New Delhi
Dated: 07/03/2024

To,
The Additional Chief Secretary
Department of Health and Family Welfare,
Government of Bihar,
Vikas Bhawan, New Secretariat, Patna-800 015, Bihar.

Subject:- Appointment of Superintendent in-charge and Disbursement Officer in Patna Medical College and Hospital - reg.

Madam/Sir,

I am directed to refer to the subject mentioned above and to forward herewith a copy of letter dated 13/02/2024 received from [redacted], which is self explanatory.

2. In this regard, it is requested that the matter be examined and further necessary action in the matter be taken under intimation to the concerned and this Ministry.

Yours faithfully,

Chandan

(Chandan Kumar)
Under Secretary to Government of India
Tele. No. 011-23061342

Encl.: As above

Copy for similar action to :
The Secretary, National Medical Commission, Pocket-14, Sector-8, Dwarka, New Delhi – 110077.

Copy for information to:
Sh. Vikash Chandra, Indrapuri, Road no. - 12, House Number - 39, Post-Kesari nagar, Patna-800024, Bihar.

और अभी तक कोई कार्रवाई इस संदर्भ में नहीं की।

डॉ० इन्द्र शेखर ठाकुर को स्वास्थ्य विभागीय पत्र संख्या–409 (17) से किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, लखनऊ से एम.एस. सर्जरी में नामांकन लेने हेतु उत्तर प्रदेश के निवासी होने का गलत प्रमाण–पत्र लेने तथा दो वर्ष तक लगातार दरभंगा में रहकर शोध कार्य किये बिना ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से गलत ढ़ंग से पी.एच.डी. डिग्री प्राप्त करने के फलस्वरूप तत्काल प्रभाव से 11/05/2015 को निलंबित कर, उनके विरूद्ध प्रपत्र 'क' के आरोप पत्र अलग से गठित कर विभागीय कार्रवाई करने का आदेश निर्गत हुआ। पिछले आठ साल में इनके विरूद्ध विभागीय कार्रवाई चल रही है। इसी बीच वह सेवानिवृत भी हो गये और पुनः संविदा पर बहाल भी हो गये।

बिहार गजट संख्या–829 दिनांक–13/10/2023 के अनुसार उच्चत्तर पद का प्रभार प्राप्त करने के लिए ऐसे लोक सेवक पात्र नहीं होंगे, जिनके विरूद्ध कार्रवाई/आपराधिक कार्रवाई लंबित हो अथवा कोई दंड प्रभावी हो। डॉ० ठाकुर के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई लंबित होने के बावजूद विभागीय प्रमुख डॉ० ठाकुर की फाईल मुख्य मंत्री के पास स्वयं ले जाते हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिना विभाग के 9 और 7 सेक्शन में अनापत्ति प्रमाण पत्र लिए स्वास्थ्य मंत्री के अनुपस्थिति में विशेष शक्ति का प्रयोग

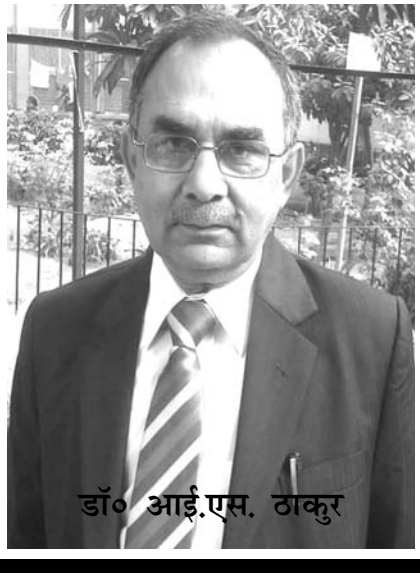

डॉ० आई.एस. ठाकुर

करते हुए फाईल पर हस्ताक्षर कर देते हैं। जब बिहार के गजट के अनुसार विभागीय कार्रवाई लंबित व्यक्ति को उच्चतर पद नहीं दिया जा सकता तो किस तरह लाडले अधिकारी को विभागीय कार्रवाई लंबित रहने के बावजूद संविदा पर अधीक्षक पी.एम.सी.एच. बना दिया। इस संबंध में भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली ने दिनांक–07/03/2024 को अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार को मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए समीक्षा करने का आदेश दिया है, साथ ही उक्त समीक्षा से स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार को अवगत करवाने का आदेश निर्गत किया है।

अधीक्षक डॉ० ठाकुर पर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में दवाओं एवं उपकरण की खरीद में अनियमितता की जाँच के लिए स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव सुधीर कुमार ने निदेशक प्रमुख, आंतरिक वित्तीय सलाहकार और वित्त पदाधिकारी, राज्य स्वास्थ्य समिति की त्रिसदस्ययी समिति बनायी, लेकिन जिसकी फाईल विभागीय प्रमुख खुद ले जाकर

www.kewalsach.com
निर्भीकता हमारी पहचान
केवल सच
हिन्दी मासिक पत्रिका
RNI NO.-BIHHIN-2006/18181 DAVP NO.-5172033 Postal Reg. No.- PT-35

प्रधान कार्यालय
पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.- 14, मकान संख्या- 14/28
कंकड़बाग, पटना- 8000 20 (बिहार)
झारखण्ड कार्यालय
सेक्टर - 1, ब्लॉक- 22, फ्लैट सं- 303
खेलगांव हाउसिंग कॉम्पलेक्स, होटवार, राँची 834009
सम्पर्क संख्या
9431073769, 9955077308, 8340360961, 9308727077
ई-मेल आईडी
kewalsach@gmail.com / editor.kstimes@rediffmail.com

पत्रांक :- 14/Kewalsach/2024 दिनांक :- 16/03/24

सेवा में ,

प्रबंध निदेशक महोदय
बीएमएसआईसीएल ,पटना।

विषय- बीएमएसआईसीएल चहेते DGM द्वारा अपनी कंपनी बनाकर नॉन शेड्यूल्ड आइटम की आपूर्ति करने के मामले में बीएमएसआईसीएल का पक्ष जानने के संबंध में ।

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि बीएमएसआइसीएलके विशेष काबिलियत से भरपूर अपने अधिकारी सागर जायसवाल को दरभंगा ,बेतिया, मोतिहारी और झंझारपुर का DGM बनाया है, चार बड़े क्षेत्र का अधिकारी बनाना अपने आप में जांच का विषय है । विदित हो कि अनुमंडलीय अस्पताल बगहा के संबंध में विधानसभा में सागर जायसवाल के कारण गलत जवाब दिया गया ,लेकिन सागर जायसवाल का बाल बांका नहीं हुआ उल्टे बीएमएसआईसीएल के विद्वान और ईमानदार अधिकारी इंद्रजीत कुमार सीजीएम प्रोजेक्ट पर कार्रवाई हो गई ।अब हालात यह है कि उनका मनोबल इतना बढ़ गया है कि इन चारों बड़े क्षेत्र में अपना कंपनी "SARKS" SARVS (किसी नजदीकी व्यक्ति के नाम से) बनाकर नॉन शेड्यूल्ड आइटम की आपूर्ति ठेकेदार पर दबाव बनाकर करवाते हैं इसकी जांच आप अपने स्तर से भी करवा सकते हैं।

अतः आपसे निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों की जांच कर बीएमएसआईसीएल का पक्ष केवल सच को देने की कृपा करें ताकि अगले अंक में केवल सच पत्रिका बीएमएसआईसीएल का भी पक्ष रख सके ।

भवदिय
शशि रंजन सिंह
सहायक संपादक
केवल सच
(हिन्दी मासिक पत्रिका)

प्रतिलिपि :-

अपर मुख्य सचिव महोदय , स्वास्थ्य विभाग ,बिहार पटना।

MOB-8210772610

मुकेश रौशन

मुख्यमंत्री से हस्ताक्षर करवाते हों, उन्हें इस समिति से कुछ बाल भी बाका हो सकेगा, इसकी उम्मीद भी बेईमानी है! अपर सचिव द्वारा REMINDER देने के बाद भी अभी तक इस पर जाँच भी शुरू नहीं हो सका है। केवल सच द्वारा निदेशक प्रमुख (नर्सिंग) से बात करने पर उन्होंने कहा कि हमने अनुमंडलीय लोक शिकायत पदाधिकारी, पटना के आदेश को ही TRUE कर दिया है। अब विभाग ही बता सकता है कि विभाग के स्तर पर बनायी गयी उच्च अधिकार प्राप्त उच्च समिति, जिसमें दो-दो विशेषज्ञ शामिल थे, उनका रिर्पोट क्यों नहीं आ पाया है? विदित हो कि अनुमंडलीय लोक शिकायत पदाधिकारी ऐसे पदाधिकारी होते हैं, जिनको कोई जाँच की शक्ति प्राप्त नहीं है।

डॉ० ठाकुर को गलत ढ़ंग से संविदा

सागर जयसवाल

दिनेश कुमार

शंभूनाथ ठाकुर

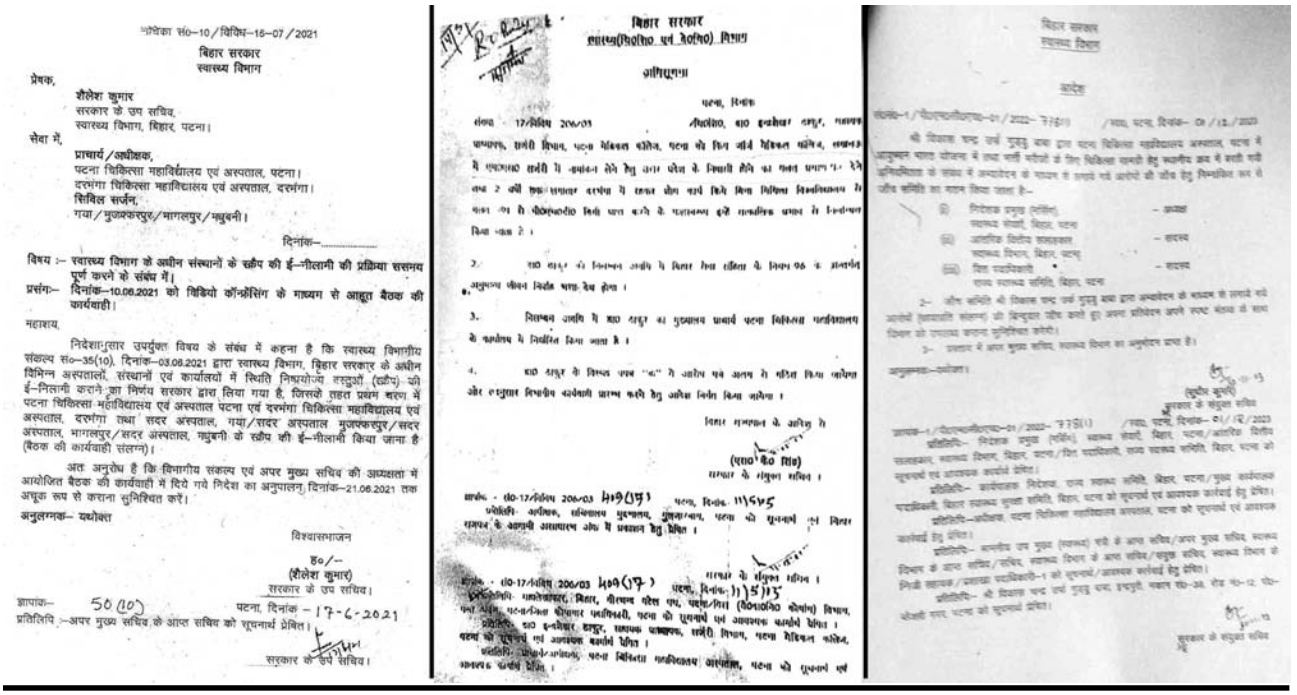

ज्ञापिका सं०–10/विविध–16–07/2021

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,
शैलेश कुमार
सरकार के उप सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,
प्राचार्य/अधीक्षक,
पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना।
दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, दरभंगा।
सिविल सर्जन,
गया/मुजफ्फरपुर/भागलपुर/मधुबनी।

दिनांक–..........

विषय :– स्वास्थ्य विभाग के अधीन संस्थानों के स्क्रैप की ई–नीलामी की प्रक्रिया ससमय पूर्ण करने के संबंध में।

प्रसंग:– दिनांक–10.06.2021 को विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आहूत बैठक की कार्यवाही।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वास्थ्य विभागीय संकल्प सं०–35(10), दिनांक–03.06.2021 द्वारा स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के अधीन विभिन्न अस्पतालों, संस्थानों एवं कार्यालयों में स्थिति निष्प्रयोज्य वस्तुओं (स्क्रैप) की ई–निलामी कराने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है, जिसके तहत प्रथम चरण में पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल पटना एवं दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, दरभंगा तथा सदर अस्पताल, गया/सदर अस्पताल मुजफ्फरपुर/सदर अस्पताल, भागलपुर/सदर अस्पताल, मधुबनी के स्क्रैप की ई–नीलामी किया जाना है (बैठक की कार्यवाही संलग्न)।

अतः अनुरोध है कि विभागीय संकल्प एवं अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक की कार्यवाही में दिये गये निदेश का अनुपालन दिनांक–21.06.2021 तक अचूक रूप से कराना सुनिश्चित करें।

अनुलग्नक– यथोक्त

विश्वासभाजन
ह०/–
(शैलेश कुमार)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक– 50 (10) पटना, दिनांक – 17-6-2021

प्रतिलिपि :–अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य(चि०शि० एवं जे०चि०) विभाग

अधिसूचना

(एस० के० सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

पर पुनः पी.एम.सी.एच. का अधीक्षक बनाये जाने के मामले में विधान सभा में राजद के विधायक डॉ० मुकेश रौशन ने सरकार के फैसले पर आवाज (प्रश्न) उठाया था, सरकार की ओर से भी आश्वासन दिया गया कि सरकार जल्द ही जाँच कराकर विधि सम्मत कार्रवाई करेगी, लेकिन ''जिस पर कृपा नीतीश की होई, उसे जाँच और कार्रवाई का भय न होई''। राजद के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह ने कहा कि यह तो एक उदाहरण मात्र है, नीतीश कुमार पूरी तरह से अधिकारियों के गिरफ्त में हैं। उनका साफ कहना है कि राजा जैसा चाहता है, वैसे ही नौकरशाह करते हैं। नीतीश कुमार के शासन मे नौकरशाह ही शासक हैं। मंत्री को नीतीश कुमार नौकरशाह के माध्यम से सही में काम ही नहीं करने देते हैं। नीतीश कुमार खुद भी भ्रष्ट हैं और उनके गिरोह के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भी भ्रष्ट हैं। उनका मानना है कि डॉ० आई० एस० ठाकुर को पुनः संविदा पर अधीक्षक नियुक्त करके उन्होंने अति–पिछड़ों और दलितों का हक मारा है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के दवाब में सरकार ने 13/10/2023 को बिहार गजट निकाल कर साफ कर दिया, दागदार व्यक्ति का उच्चतर पद पर नियुक्ति नहीं होगी, तो नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के सरकार से हटते ही डॉ० आई० एस० ठाकुर जैसे भ्रष्ट अधिकारी, जिनके ऊपर विभागीय कार्रवाई लंबित हो, उन्हें संविदा पर पी. एम.सी.एच. जैसे संस्थान का अधीक्षक नियुक्त कर दिया।

स्वास्थ्य विभाग के आदेश संख्या–50 (10) दिनांक–17/06/2021 के आलोक में अस्पताल में निष्प्रयोग वस्तुओं (स्क्रैप) की ई–नीलामी करना था, इसमें भी डॉ० आई० एस० ठाकुर के द्वारा सरकार के निर्देश का पालन नहीं किया गया। उपकरण एवं उपस्करों को कौड़ियों के भाव बेच दिया गया। यहाँ तक कि कई अच्छे उपकरण को स्क्रैप उपकरणों से बदल कर मँहगे दामों में बेच दिया गया। केवल सच जल्द ही आपको पी.एम.सी.एच. स्क्रैप घोटाले का सच विस्तार से बताएगा। सरकार ने सभी प्राकार के संस्थानों में स्क्रैप घोषित करने के लिए अलग–अलग समिति बनायी, जिनमें मेडिकल कॉलेज में प्राचार्य अध्यक्ष होंगे, सदस्य के रूप में अधीक्षक और उपाधीक्षक होंगे और स्क्रैप का सामान भारत सरकार के Metal Scrap Trade Corporation Limited (MSTCL) (भारत सरकार के उपक्रम) के माध्यम से ही ऑक्शन होना है।

दूसरी तरफ BMSICL, जिसके ऊपर पूरे बिहार के अस्पतालों के निर्माण का जिम्मा है। आज BMSICL के कई बड़े प्रोजेक्ट में अच्छी तरह कार्य कर अपनी महत्ता सिद्ध की है, लेकिन इधर के कई वर्षों में उसमें भ्रष्टाचार को भी नया आयाम दिया है। BMSICL के उप महाप्रबंधक सागर जयसवाल, जिनका भाजपा सांसद संजय जयसवाल और मंत्री मंगल पांडेय और पूर्व के प्रबंध निदेशक दिनेश कुमार से करीबी रिश्ता है। हम यह बात ऐसे में नहीं कर रहे हैं, इसका प्रमाण है। सागर जयसवाल को मिलने वाले जिले, सागर जयसवाल को दरभंगा, मधुबनी, मोतिहारी और बेतिया जैसे जिले

आवंटित हैं, जबकि सागर जयसवाल के कारण मंत्री स्वास्थ्य को विधान सभा में गलत जवाब देना पड़ा और इसका खमियाजा मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना) इन्द्रजीत कुमार जैसे विद्वान अभियंता को भुगतना पड़ा और उन्हें BMSICL से चलता कर दिया गया, लेकिन सागर जयसवाल को सिर्फ कारण बताओ नोटिस देकर उसे चार महत्वपूर्ण जिले आवंटित कर दिये गये। जब सागर जयसवाल के ऊपर इतने लोगों का हाथ हो तब सागर जयसवाल ने अपने संबंधि के नाम से SARVS नामक कम्पनी खोलकर अपने आवंटित जिले के प्रोजेक्ट में घटिया स्तर के Non Schedule Items ठिकेदारों पर दवाब देकर लगवाने लगा। आज BMSICL द्वारा निर्मित 50 बेडेड अस्पताल (बगहा), 50 बेडेड अस्पताल दरभंगा (बिरौल), 100 बेडेड अस्पताल (डी.एम.सी.एच.), 400 बेडेड अस्पताल सर्जिकल ब्लॉक राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय बेतिया, माँ-बच्चा अस्पताल (एम. सी.एच.) मोतिहारी, मॉडल अस्पताल ढाका और मॉडल अस्पताल मोतिहारी में लगे Non Schedule Item जैसे Oxygen Pipeline (MGPS), Cotton Furniture, O.T., Electic Wire, STP, GTP, Fire Fighting, Laundry, कुछ Medical Equipment Item और कुछ Surgical Item की जाँच करवाई जाये तो दूध का दूध और पानी का पानी साबित हो जाएगा। केवल सच ने BMSICL के प्रबंध निदेशक को पत्र लिखकर इस मामले में पक्ष रखने का आग्रह किया लेकिन आलेख लिखे जाने तक केवल सच को अभी तक BMSICL का पक्ष प्राप्त नहीं हुआ है। BMSICL के उप महाप्रबंधक (परियोजना) सागर जयसवाल ने इतनी अकुत सम्पति अर्जित की है कि उसने कई जिले ही नहीं बल्कि कई राज्यों में अपनी सम्पति अर्जित की है। साथ ही पत्नी और परिवार के सदस्यों के नाम से कई सारे शेयर बॉन्ड की भी खरीद की है। सागर जयसवाल के काले कारनामे का काला सच आगे भी केवल सच आपको बताएगा। इसलिए पढ़ते रहिए सिर्फ केवल सच।

सहायक औषधि नियंत्रक/निरीक्षक शंभुनाथ ठाकुर अभी तो दरभंगा जिले में पदस्थापित हैं, लेकिन वह जहाँ भी रहते हैं, भ्रष्टाचार की नदी बहाते रहते हैं। उनके ऊपर पटना में रहते हुए बिहार की सबसे बड़ी दवा मंडी जी. एम. रोड में फर्जी लाईसेन्स देने का मामला प्रकाश में आया था, जिसपर जाँच भी की गई थी, लेकिन नतिजा ढाक के तीन पात वाली हो गई। क्योंकि पैसों की खनक के आगे सुशासन की सरकार नतमस्तक हो जाती है। अभी दरभंगा में शंभुनाथ ठाकुर के ऊपर औषधि मुख्यालय से जाँच भी बैठी थी, लेकिन नतीजा फिर वही, ऊपर से औषधि निरीक्षक शंभुनाथ ठाकुर को पदोन्नति देते हुए सहायक औषधि नियंत्रक बना दिया गया, साथ ही उन्हें एक और क्षेत्र आवंटित कर दिया गया, ताकि वह अपने कमाई का एक हिस्सा मुख्यालय भी पहुँचा दें। जब सरकार ने बिहार गजट संख्या - 829 दिनांक 13/10/2023 जारी कर दागदार छवि वाले अधिकारियों को उच्चतर पद नहीं देने का कानून बनाया तो फिर कैसे शंभुनाथ ठाकुर की पदोन्नति की गई।

तेजस्वी यादव

स्वास्थ्य विभाग के लाडली विशेष कार्य पदाधिकारी रेणु कुमारी को कार्य में लापरवाही और भ्रष्ट आचरण के कारण पिछले पाँच वर्षों से वेतन बंद है। बिना वेतन के पिछले तीन वर्षों से स्वास्थ्य विभाग की अघोषित प्रमुख बनी हुई है। उन्हें नियम के विरूद्ध वाहन और आदेशपाल दिया गया है। आज रेणु कुमारी का ऐसा टेरर है कि उनके कलिग अधिकारी भी उनके खिलाफ बोलने से डरते हैं। स्वास्थ्य विभाग में सच्चाई का साथ देने वाले और रेणु कुमारी के विपरित जाने वाले दो अधिकारियों की रेणु कुमारी ने विभाग से छुट्टी करवा दी। रेणु कुमारी के कारण विभाग में जरूरी उपस्करों का आभाव हो गया है। अगर संयुक्त सचिव द्वारा कोई भी आदेश रेणु कुमारी के पुछे बिना निकाला जाता है तो रेणु कुमारी अपने हस्ताक्षर से तुरंत दूसरा आदेश निकाल देती है, जबकि कार्मिक विभाग के आदेश के अनुसार उप सचिव से न्यूनतम स्तर के अधिकारी कोई भी अधिसूचना या स्थानांतरण आदेश नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन मंत्री मंगल पांडेय और मंत्री तेजस्वी यादव की विशेष कृपा पात्र एवं विभागीय प्रमुख की लाडली रेणु कुमारी को विशेष छूट प्राप्त है। ●

वोट के खातिर धृतराष्ट्र बने नीतीश

तालिमि मरकज, टोला सेवक और विकास मित्र का बढ़ाया वेतन बाकी को दिखाया ठेंगा

● शशि रंजन सिंह/राजीव शुक्ला

महाभारत में पुत्र मोह में धृतराष्ट्र ने राजधर्म का त्याग कर दिया था। कलयुग में नीतीश कुमार ने वोट धर्म के कारण राजधर्म का त्याग कर दिया है। यूं तो वोट की राजनीति सभी राजनीतिक पाटी करते हैं, लेकिन बिहार में सुशासन की सरकार अपने कर्मचारियों के बीच भी भेद-भाव कर वोट की राजनीति कर रही है। नीतीश कुमार की सरकार ने तालिमि मरकज, टोला सेवक और विकास मित्र के मानदेय में वृद्धि कर दी। बिहार सरकार में संविदा आधारित कर्मचारी लगभग 11 लाख हैं। आवास सहायक, लेखा सहायक, आवास पर्यवेक्षक, स्वाच्छता पर्यवेक्षक, किसान सलाहकार, विकास मित्र, तालिमि मरकज, मनरेगा के कार्यक्रम पदाधिकारी (पी.ओ.)/रोजगार सेवक, व्यवसाय अनुदेशक, न्याय मित्र, ग्राम कचहरी सचिव, विभिन्न विभागों में कार्यरत अभियंता, नगर प्रबंधक, कार्यपालक सहायक, कार्यालय परिचारी, आशुलिपिक, आई.टी. ब्वॉय, किसान सलाहकार, चिकित्सक, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, चालक, मतस्य प्रसार पदाधिकारी, महिला पर्यवेक्षिका (आँगनबाड़ी) जैसे कई पद राज्य सरकार में संविदा पर आधारित हैं। इसलिए बिहार की सरकार को ''ठेके पर सरकार'' भी कहा जाता है, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार ने अल्पसंख्यक और दलित वोट के कारण विकास मित्र, तालिमि मरकज और टोला सेवक का मानदेय वृद्धि ढोल-नगाड़े के साथ किया। क्या बिहार सरकार बाकी पदों में आरक्षण को समाप्त कर दी है? अगर बाकी पद भी आरक्षण आधारित है, तो सभी पद में दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, अति-पिछड़ा और महादलित है, तो फिर सिर्फ तीन पदों के कर्मचारियों को वेतन वृद्धि क्यों किया गया?

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में संविदा पर नियोजित कर्मियों की सेवा संबंधी बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरांत अनुशंसा करने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-3/एम.-19/2015 सा.प्र. -6161, दिनांक-24/04/2015 द्वारा किया गया। इस समिति ने विभिन्न विभागों में संविदा पर नियोजित कर्मियों की सेवा संबंधित बिन्दुओं के संबंध में गठित उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसाओं का अनुमोदन ज्ञापांक-12534, दिनांक-17/09/2018 को दिया। इस अनुशंसा में संविदा कर्मियों की सेवानिवृत्ति की आयु, मानदेय/पारिश्रमिक, अवकाश की अनुमानता, सेवा अवधि में मृत्यु होने पर अनुग्रह अनुदान, सेवा कर्मियों की सेवा अभिलेख का संधारण, संविदा कर्मियों के लिए यात्रा व्यय, संविदा कर्मियों को हटाये जाने की स्थिति में अपील का प्रावधान, संविदा कर्मियों की सेवा का नियमितीकरण, मातृत्व अवकाश, संविदा कर्मियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि बीमा, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम को लागू करना, संविदा कर्मियों के कार्य का वार्षिक मूल्यांकन सहित सभी बिन्दुओं पर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस समिति ने प्रधानमंत्री आवास योजना में कार्य करने वाले ग्रामीण आवास सहायक, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक, लेखा सहायक, कार्यपालक सहायक को मानदेय में पुनरिक्षण का प्रावधान किया साथ ही ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक-311722, दिनांक-26/05/2017 से स्पष्ट है कि बिहार रूरल डेवलपमेन्ट सोसाईटी, पटना की बैठक दिनांक 30/03/2017 में निर्णय लिया गया कि मनरेगा कर्मियों की भांति प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)/इंदिरा आवास योजना अंतर्गत संविदा नियोजित कर्मियों यथा-ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक, ग्रामीण आवास सहायक एवं लेखा सहायक (ग्रामीण आवास) की दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु की स्थिति में उनके निकट आश्रितों को मूल मानदेय का 60 गुणा आर्थिक सहायक प्रदान की जायेगी। इस राशि का भुगतान प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत बिहार

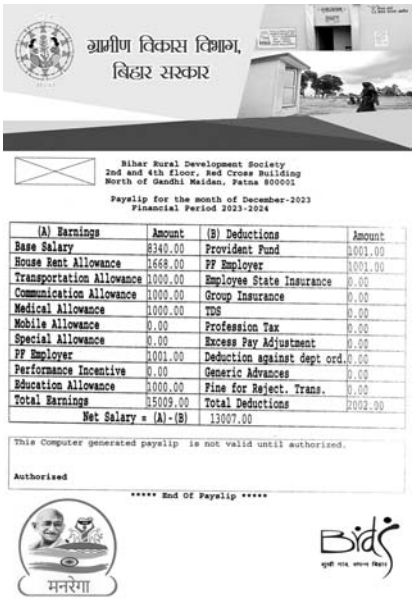

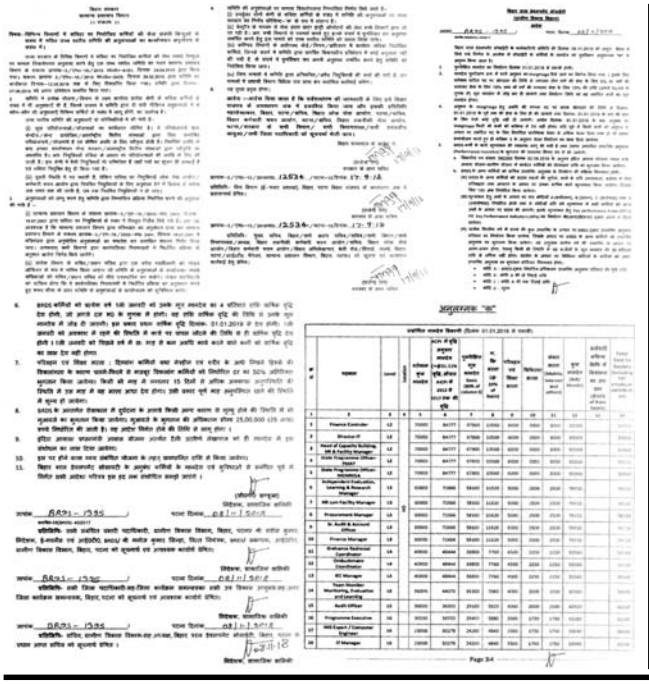

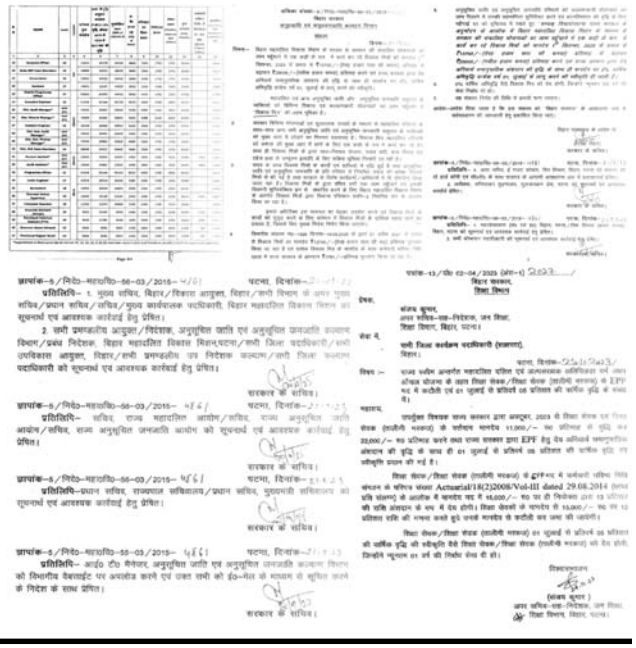

ग्रामीण विकास सोसायटी (BRDS) में विभागीय मुख्यालय स्तर पर संधारित प्रशासनिक व्यय मद की राशि से किया जायेगा। जब सरकार द्वारा बनाये गए आयोग ने सभी संविदा आधारित पदों के लिए अनुशंसाएँ की थीं, तो सरकार ने सिर्फ वोट साधने के लिए सिर्फ विकास मित्र, तालिमि मरकज और टोला सेवक का ही वेतन वृद्धि क्यों किया गया?

ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार द्वारा 2013-14 में इंदिरा आवास के क्रियान्वयन के लिए संविदा आधारित नियोजन हेतु विज्ञापन का प्रकाशन किया गया था, जिसमें ग्रामीण आवास सहायक, लेखा सहायक एवं आवास पर्यवेक्षक के पद हेतु विज्ञापन का प्रकाशन किया गया था।

☞ **शैक्षणिक योग्यता के तौर पर :-** ग्रामीण आवास सहायक के लिए इंटर, लेखा सहायक के लिए B.Com. with Computer Knowledge एवं आवास पर्यवेक्षक के लिए B.Sc. or B.Tech. की योग्यता निर्धारित की गई थी। विभिन्न जिलों में माह फरवरी 2014 से माह जुलाई 2014 तक उपरोक्त पदों का नियुक्ति पत्र वितरण किया गया था, जिसमें ग्रामीण आवास सहायक को 6681, लेखा सहायक को 9500 एवं आवास पर्यवेक्षक को 12500 रूपया मात्र का भुगतान किया जाता था। वर्ष 2018 में बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी (BRDS) के कार्यकारिणी समिति की दिनांक-08/11/2018 को बैठक में मानदेय का पुनरीक्षण किया गया, जिसका पत्रांक-BRDS-1395, दिनांक-08/11/2018 के द्वारा ग्रामीण आवास सहायक को 12580, लेखा सहायक को 16040 एवं आवास पर्यवेक्षक को 19520 रूपया मानदेय तथा इसी राशि में से EPF भी काटा जाता है। पत्रांक-BRDS-1395, दिनांक-08/11/2018 के आलोक में 03 वर्ष की सेवा के लिए 5%, 06 वर्ष की सेवा के लिए 10% एवं 09 वर्ष की सेवा के लिए 15% की राशि मूल मानदेय में जोड़कर दी जाने हेतु आदेश किया गया था, जो कि अब तक नहीं दिया गया है।

इस समिति ने अपनी अनुशंसा में कहा कि प्रत्येक विभाग के सचिव/प्रधान सचिव द्वारा एक वरीय पदाधिकारी को नोडल ऑफिसर के रूप में नामित किया जाएगा जो समिति के अनुशंसाओं के कार्यान्वयन संबंधी संचिकाओं को सचिव/प्रधान सचिव को सीधे उपस्थापित कर सकेंगे। नोडल पदाधिकारी का दायित्व होगा कि वे कार्यपालिका नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए समय सीमा के अंदर समिति के अनुशंसाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेंगे। जब समिति ने अपनी रिपोर्ट 17/09/2018 को ही सरकार को समर्पित कर दी थी, तो सरकार सिर्फ तीन पदों पर ही क्यों निर्णय ले सकी? सरकार की यह मानसिकता कहीं ना कहीं कर्मचारियों के बीच भेद-भाव का काम कर रही है। बाकी संविदाकर्मी हतोत्साहित हो रहे हैं। लगता है सुशासन बाबू की सरकार चाहती है कि संविदाकर्मी पैसों की कमी के कारण या तो नौकरी छोड़ दे या भूखे मरने पर मजबूर हो जाये। उदाहरण के तौर पर आवास सहायक का मूल वेतन 8340 रूपया है, बिहार सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानदेय निम्न प्रकार है:-

Class of Employment	Basic Per Day	Basic Per Month
Unskilled	388.00	10088.00
Semi-Skilled	403.00	10478.00
Skilled	491.00	12766.00
Highly Skilled	600.00	15600.00

अब बिहार सरकार ही बताये की वह अपने कर्मचारियों को न्यूनतम मानदेय भी नहीं दे पा रही है, जबकि पत्रांक-BRDS-1395, दिनांक-08/11/2018 के आलोक में 03 वर्ष की सेवा के लिए 5%, 06 वर्ष की सेवा के लिए 10% एवं 09 वर्ष की सेवा के लिए 15% की राशि मूल मानदेय में जोड़कर दी जाने हेतु आदेश किया गया था।●

पहल जोड़ने का कानून

CAA

● **गौतम कुमार सिंह**

नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया था। बाद में इस विधेयक को राष्ट्रपति का अनुमोदन मिल गया था। सीएए के जरिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों से संबंधित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता लेने में आसानी होगी।

☞ **नए कानून में क्या प्रावधान हैं?**

नागरिकता अधिनियम में देशीयकरण द्वारा नागरिकता का प्रावधान किया गया है। आवेदक को पिछले 12 महीनों के दौरान और पिछले 14 वर्षों में से आखिरी साल 11 महीने भारत में रहना चाहिए। कानून में छह धर्मों (हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई) और तीन देशों (अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान) से संबंधित व्यक्तियों के लिए 11 वर्ष की जगह छह वर्ष तक का समय है। कानून में यह भी प्रावधान है कि यदि किसी नियम का उल्लंघन किया जाता है तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्डधारकों का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।

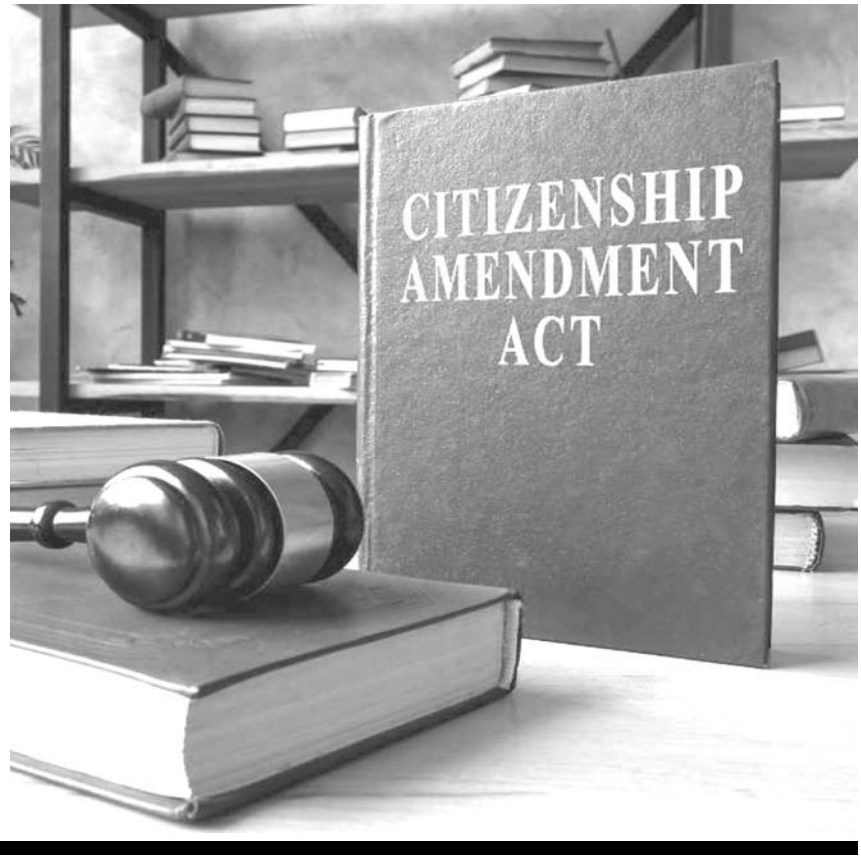

☞ **कानून की मुख्य बातें क्या हैं?**

नागरिकता अधिनियम, 1955 यह बताता है कि कौन भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है और किस आधार पर। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक बन सकता है यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता-पिता भारतीय हों या कुछ समय से देश में रह रहे हों, आदि। हालांकि, अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से प्रतिबंधित किया गया है। अवैध प्रवासी वह विदेशी होता है जो: (प) पासपोर्ट और वीजा जैसे वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना देश में प्रवेश करता है, या (पप) वैध दस्तावेजों के साथ प्रवेश करता है, लेकिन अनुमत समय अवधि से अधिक समय तक रहता है। विदेशी अधिनियम, 1946 और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 के तहत अवैध प्रवासियों को कैद या निर्वासित किया जा सकता है। 1946 और 1920 अधिनियम केंद्र सरकार को भारत के भीतर विदेशियों के प्रवेश, निकास और निवास को विनियमित करने का अधिकार देते हैं। 2015 और 2016 में, केंद्र सरकार ने अवैध प्रवासियों के कुछ समूहों को 1946 और 1920 अधिनियमों के प्रावधानों से छूट देते हुए दो अधिसूचना जारी की थीं। ये समूह अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई हैं, जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आए थे। इसका मतलब यह है कि अवैध प्रवासियों के इन समूहों को निर्वासित नहीं किया जाएगा। भले ही लोग नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने के

लिए सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन असल में वह विरोध कर रहे हैं एनआरसी और सरकार का, बल्कि यूं कहिए कि प्रदर्शन कर रहे लोग कह रहे हैं कि नागरिकता संशोधन कानून में मुस्लिमों को शामिल क्यों नहीं किया गया है? उनका आरोप है कि ये सरकार मुस्लिमों की नागरिकता छीनना चाहती है. कहा जा रहा है कि मोदी सरकार एनआरसी से बाहर हुए हिंदुओं और अन्य धर्मों के लोगों को नागरिकता संशोधन कानून के तहत नागरिकता दे देगी, जबकि उसमें शामिल मुस्लिमों को देश से बाहर निकाल देगी. लेकिन ऐसा कुछ नही है, अगर आप पूरे कानून को विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ लोग अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने या सरकार को नीचे दिखाने या तो राष्ट्रीय पटल पे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि नागरिकता कानून, नागरिकता दिलवाने के कानून है न कि छीनने का, 2016 के विधेयक में 11 वर्ष की शर्त को घटाकर 6 वर्ष किया गया था। नए कानून में इसे घटाकर पांच वर्ष कर दिया गया है।छठी अनुसूची में शामिल क्षेत्रों को छूट देने का बिंदु भी पिछले विधेयक में नहीं था।अवैध प्रवास के संबंध में सभी कानूनी कार्यवाही बंद करने का प्रावधान भी नया है।

1947 में भारत और पाकिस्तान के धार्मिक आधार पर विभाजन का तर्क देते हुए सरकार ने कहा कि अविभाजित भारत में रहने वाले लाखों लोग भिन्न मतों को मानते हुए 1947 से पाकिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे थे। विधेयक में कहा गया है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान का संविधान उन्हें विशिष्ट धार्मिक राज्य बनाता है। परिणामस्वरूप, इन देशों में हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन और ईसाई समुदायों के बहुत से लोग धार्मिक आधार पर उत्पीड़न झेलते हैं। इनमें से बहुत से लोग रोजमर्रा के जीवन में उत्पीड़न से डरते हैं। जहां उनका अपनी धार्मिक पद्धति, उसके पालन और आस्था रखना बाधित और वर्जित है। इनमें से बहुत से लोग भारत में शरण के लिए भाग आए और वे अब यहीं रहना चाहते हैं। यद्यपि उनके यात्रा दस्तावेजों की समय सीमा समाप्त हो चुकी है या वे अपूर्ण हैं अथवा उनके पास दस्तावेज नहीं हैं। आप पूरे ।ब्ज को पढ़ेंगे तो इसमें ऐसा कहीं नही लिखा गया है कि भारत के नागरिक और यहाँ रह रहे लोगो को निकाल दिया जाएगा लेकिन कुछ गलत बोलने से हमे खुद समझना होगा और लोगों को समझाना होगा।●

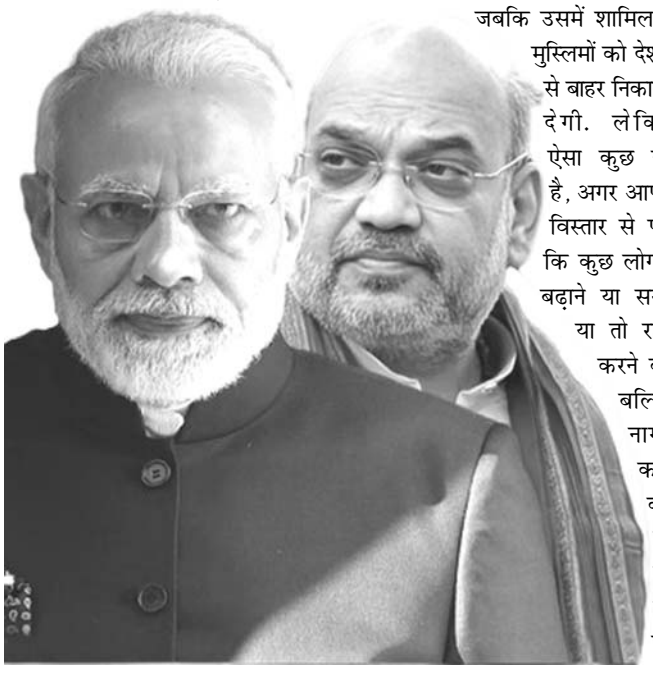

के.के. पाठक का विरोध सामाजिक नहीं राजनीतिक

● डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह

के. के. पाठक द्वारा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण करते ही शिक्षा विभाग में ऊपर से नीचे तक हड़कंप मच गया क्योंकि केके पाठक ने शिक्षा विभाग में वर्षों से लगे भ्रष्टाचार के जंग को छुड़ाने का प्रयास किया। के के पाठक द्वारा कठोर अनुशासन के साथ अपेक्षित सुधार करने का कुछ अच्छा परिणाम भी सामने आया इससे इनकार करना मुश्किल है। सबसे पहली बात तो यह हुई कि विद्यालय से गायब रहने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं पर अंकुश लगा और वह निर्धारित समय तक विद्यालय में रहने लगे हैं। जांच का दायरा और निरंतरता में भी वृद्धि हुई जिस विद्यालय में छात्र-छात्राओं की उपस्थिति भी भारी और शिक्षकों की जवाब देही भी। जब इच्छा हो अपनी

सुविधा से विद्यालय जाने और जाने की प्रवृत्ति पर कुछ हद तक रोक लगी है। टीचरों को सबसे आरामदायक काम संबंध में समझने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए निश्चित रूप के के पाठक एक आफत की तरह है। सामाजिक स्तर पर क्या-क्या पाठक के कार्यों की प्रशंसा हुई है लेकिन राजनीतिक स्तर पर के.के. पाठक का विरोध इस बात का संकेत है कि वह राजनीतिक मुद्दा बन चुके हैं। शिक्षकों को खुश करने के लिए भी कुछ राजनेता के.के. पाठक के विरुद्ध उठ खड़े हुए हैं। बताया जाता है कि विधानसभा में वैसे लोग हंगामा करते देखे गए, जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं भारी-भारी फीस वाले में पढ़ाते हैं। बताया जाता है कि अधिकांश बच्चों का नाम प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने के लिए तथा सरकारी स्कूल में सर्टिफिकेट के लिए दर्ज रहता है। इसमें भी काफी सुधार हुआ है। बताया जाता है कि केके पाठक के जाने के बाद फिर वही स्थिति अधिकांश स्कूलों में पैदा हो जाएगी 12 बजे तक लेट नहीं 3 बजे के बाद भेंट नहीं।●

सड़क के खंभे को सांसद-विधायक न चुने : पंडित दीनदयाल

● डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह

कोई बूरा उम्मीदवार केवल इसलिए आपका मत पाने का दावा नहीं कर सकता है कि वह किसी अच्छी पार्टी की ओर से खड़ा है। बुरा बुरा ही है वह किसी का भी हित नहीं कर सकता। चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। चुनाव मैदान में खड़े अनेक प्रत्याशियों में से आपको सिर्फ एक को ही चुनना है, आप सभी दलों को संतुष्ट नहीं कर सकते अंतिम निर्णय कई समस्याओं के सतर्क और सही मूल्यांकन पर निर्भर करता है। प्रत्याशी दल और उसका सिद्धांत इन सभी पर विचार करना पड़ता है। कोई बूरा प्रत्याशी केवल इसलिए आपका मत पाने का दावा नहीं कर सकता है कि वह किसी अच्छे दल की ओर से खड़ा है। उन्होंने कहा कि हाई कमान ने ऐसे व्यक्ति को टिकट देते समय पक्षपात किया होगा या नेक नियति बरतते हुए भी वह निर्णय लेन में भूल कर गया होगा। इस गलती को सुधारना उत्तरदायित्व मतदाता का कर्तव्य है।

एक समय ऐसा था कि कांग्रेस के टिकट पर सड़क की बत्ती के खंभे को भी जनता मत दे सकती थी। प्रथम आम चुनाव में आचार्य नरेंद्र देव और आचार्य कृपलानी जैसे दिग्गज नेता ऐसे कांग्रेसी प्रत्याशियों के हाथों पराजित हो गए थे, जिन कि उनकी तुलना में

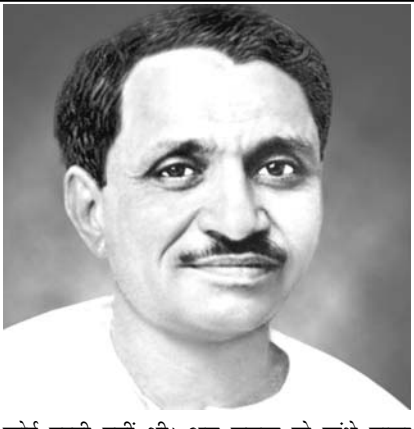

कोई हस्ती नहीं थी। अब सड़क के खंभे वाला युग बीत गया है।

राजनीति में योग्य व्यक्ति की जरूरत :- सत्ता समान्यत भ्रष्ट करती है। कांग्रेस राज सत्ता में है तो उसमें भ्रष्टाचार है कल भाजपा सत्ता में आती है तो उसमें भी यह दोष आ सकती है। उन्हें उन्होंने कहा कि जनसंघ (आज के भाजपा) सत्ता में आती है तो तो उसमें भी यह दोष आ सकता है । उन्होंने कहा कि भाजपा भ्रष्ट होती है,तो मैं इस संगठन को स्वयं अपने हाथों से समाप्त कर दूंगा एवं नए संगठन का निर्माण करूंगा जिस प्रकार महर्षि परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों को नष्ट किया एवं जब उन्हें है भगवान श्री राम जैसे सदृष्य व्यक्ति मिल गए तो वह वन को प्रस्थान कर गए।

भाजपा मीडिया प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल ने कहा कि बिहार में भाजपा का खोल पहने बड़े बड़े पद पर बहुत मिल जाएंगे परंतु माला पहनने , फोटो खिंचवाने से फुर्सत नहीं है कि मोदी जी द्वारा जनहित में दो सौ से ज्यादा योजनाएं से कोई लेना-देना नहीं है, अधिकांश योजनाएं सरकारी फाइलों का शोभा बढ़ा रही हैं। कुछ योजनाएं निम्न प्रकार है :- प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनाएं, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना दीनदयाल, उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण, कौशल्या योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रम एवं ज्योति योजना, धन लक्ष्मी योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम परिवहन योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान, प्रधानमंत्री युवा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार, प्रोत्साहन योजना गर्भवती, महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता देना वरिष्ठ नागरिकों के लिए योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल योजना, व्यापारियों के लिए भी आधार योजना डिजिटल मेला विश्वकर्म योजना आदि सैकड़ों योजना है।●

इटली, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस देश जैसा मतदान अनिवार्य हो सकता है भारत में?

● डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां की बात कार्यक्रम में तीन माह के लिए विराम देते हुए लोकतंत्र के महाकुंभ चुनाव में पहली बार वोटर बने युवाओं से रिकॉर्ड संख्या में मतदान का आग्रह किया है। अधिकतम संख्या में मतदान लोकतंत्र की जीवन दाता का प्रमाण होने के साथ लोकतंत्र के बलशाली होने का आधार है और जनता की सक्रिय भागीदारी का सूचक है। बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस,बोलिनिया इटली जैसे देशों में मतदान अनिवार्य है, मतदान न करने वालों के लिए जुर्माना का प्रावधान है।

अगले माह लोकसभा चुनाव की संभावित घोषणा और उसके चलते आचार संहिता लागू हो जाएगी, अधिकतम मतदान लोकतंत्र में जन भागीदारी का अवसर मात्र ही नहीं है बल्कि देश की दशा, दिशा तय करने में आम आदमी के योगदान का भी परिचायक है। आमतौर पर मतदान न करने के पीछे यह तर्क अधिक सुनने को मिलता है कि मेरे अकेले मत से क्या फर्क पड़ता है यह तो सही नहीं है क्योंकि कई बार दो-चार मतों से भी हार जीत होती है, यदि सभी यही सोंचने लगे तो फिर लोकतंत्र कैसे सबल और सक्षम होगा। इस दृष्टि से प्रधानमंत्री मोदी का अधिकतम मतदान को प्रोत्साहन देने का उपक्रम एवं आवाहन एक क्रांतिकारी शुरुआत कहीं जा सकती है। अब तक दुनिया के 32 देशों में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था है, यही व्यवस्था यदि भारत में लागू हो गयी तो अमेरिका और ब्रिटेन जैसे पुराने सशक्त लोकतंत्र को भी भारत का अनुकरण करना पड़ सकता है। हालांकि भारत और उनके परिस्थितियों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। भारत में अमीर लोग वोट नहीं डालते और इन देशों में गरीब लोग वोट नहीं डालते। पिछले 77 साल में हमारे यहां एक भी सरकार ऐसी नहीं बनी जिसे कभी 50% वोट मिले हो। कुल वोटो के 50% नहीं। जितने वोट पड़े उनका भी 50% नहीं। गणित की दृष्टि से देखे तो 140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में सिर्फ 20/25 करोड़ लोगों के समर्थन वाली सरकार क्या वास्तव में लोकतांत्रिक सरकार है। क्या यह बहुमत का प्रतिनिधित्व करती है। हम आज तक ऐसी ही सरकारों के अधीन ही रहे है। इसी कारण लोकतंत्र में विषमताएं एवं विसंगतियों का बाहुल्य रहा है। लोकतंत्र के नाम पर छलावा हमारे साथ होता रहा है। इसके जिम्मेदार जितने राजनीतिक दल है उतने ही हम भी है।

प्रधानमंत्री ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने की अपील करते हुए कहा कि अधिक से अधिक मतदान मतलब एक मजबूत लोकतंत्र है और मजबूत लोकतंत्र से ही विकसित भारत बनेगा। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था विकसित करने का भी समय आ गया है जिससे अपने गांव शहर से दूर रहने वाले वहां जाए बिना मतदान कर सके ,ध्यान रहे कि ऐसे लोगों की संख्या करोड़ों में है। रोजी-रोटी के लिए अपने गांव शहर से दूर जाकर जीवन यापन करने वाले सब लोगों के लिए यह संभव नहीं है। वह मतदान करने अपने घर, गांव लौट सके। उन्होंने कहा कि जिस दिन भारत में 90% से अधिक नागरिक वोट डालने लगेंगे राजनीतिक जागरूकता इतनी बढ़ जाएगी की राजनीतिक को सेवा की बजाय सुखों की सेज करने माननेवाले किसी तरह का दुस्साहस नहीं नहीं कर पाएंगे। यह बातें भाजपा में मीडिया प्रभारी डॉ लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल ने भाजपा कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा इस अवसर पर रंजीत प्रसाद, भाजपा जिला मंत्री शोभा देवी, शोभा पटेल, ममता पटेल, अनामिका पटेल, अनामिका पाण्डेय, पिंकी देवी, अंजली देवी, रूबी देवी संजू कुमारी, जितेंद्र मिस्त्री, टीपू सिंह, लक्ष्मण साहू आदि मौजूद रहे।●

भारतीय संस्कृति वैश्विक धरोहर है : कुलपति

● त्रिलोकी नाथ प्रसाद

रामकृष्ण द्वारिका महाविद्यालय (आरकेडी) में भारतीय इतिहास, विरासत तथा संस्कृति विषय पर संस्कृति मंत्रालय एवं आरकेडी के इतिहास विभाग के संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कुलपति आरके सिंह ने इतिहास एवं विरासत की प्रासंगिकता वर्तमान सक्षम आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में दर्शाया और कहा कि भारतीय संस्कृति वैश्विक धरोहर है। इस प्रकार के कार्यशाला द्वारा युवाओं को प्रेरित कर ज्ञान परंपरा की समृद्धि एवं विश्व गुरु की अवधारणा के लिए एक बार पुन: अग्रसर होने हेतु मार्गदर्शित किया। वहीं मुख्य अतिथि एमएलसी प्रो. नवल किशोर यादव ने वर्तमान बिहार एवं शिक्षा पर विस्तार से प्रकाश डाला। मुख्य वक्ता भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई के सलाहकार प्रो. प्रदीप वर्मा ने विस्तार से बिहार एवं भारतीय इतिहास एवं समृद्ध विरासत पर प्रकाश डालते हुए आधुनिक भारत के निर्माण में इसकी प्रासंगिकता को पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के माध्यम से प्रस्तुत किया। इस अवसर पर बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्य प्रो. अरुण कुमार भगत ने अपने संबोधन में संस्कार, संस्कृति एवं विकृति को समझाते हुए अपने विचारों द्वारा मार्गदर्शित किया। इसके पहले आयोजक संयोजक महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ. जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता ने सभी आगत अतिथियों का स्वागत करते हुए कार्यशाला का विषय प्रवेश कराया। इस क्रम में वर्तमान समाज एवं राष्ट्र की सभ्यता से इतिहास की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। इतिहास पुरुष पं. दीनदयाल उपाध्याय के शिक्षा दर्शन एवं डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के एक अखंड राष्ट्र की अवधारणा एवं एक राष्ट्र, एक विधान एवं एक निशान पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में स्टेट नॉडल ऑफिसर डॉ. रश्मि कुमारी के अलावा आरकेडी के शिक्षक, छात्र एवं छात्राओं की उपस्थिति रही। मंच संचालन डॉ मुकेश कुमार एवं डॉ. भावना सिहं ने संयुक्त रूप से किया। धन्यवाद ज्ञापन इतिहास विभाग के अध्यक्ष डॉ. रामाकांत शर्मा के द्वारा किया गया। इस अवसर पर पीपीयू के प्रो. राजीव रंजन, प्रो. निखिल कुमार सिंह, प्रो. योगेंद्र कुमार, डॉ. धीरेंद्र उपाध्याय, डॉ. (ले.) आशिष कुमार, डॉ. ब्रजेश राय, डॉ. प्रधान दूर्गा शंकर प्रसाद, डॉ. रविरंजन प्रसाद, डॉ. उमेश कुमार, डॉ. सरिता कुमारी, डॉ. जया, डॉ. निधि, डॉ. सुनिता, डॉ. मयूराक्षी रानी, डॉ. शिल्पी शिवानी, डॉ. स्मृति कुमारी, डॉ. मंगलमूर्ति महाविद्यालय शिक्षक, कर्मचारी संघ अध्यक्ष संजय कुमार एवं लेखापाल प्रेम कुमार एवं एनसीसी, एनएसएस के छात्र-छात्राएं भी कार्यशाला में उपस्थित रहकर अपना योगदान दिया तथा प्रतिभागी सौ शोध पत्र को कुलापति के द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया।●

मोदी जी ने भारत का सर ऊँचा किया : डॉ. लक्ष्मीनारायण

● डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह

भारत से 84 से अधिक देशों को रक्षा उपकरणों का निर्यात किया जा रहा है। इस सूची में कतर,लेबनान ,इराक, इक्वाडोर और जापान जैसे देश भी शामिल है। कृषि क्षेत्र, रक्षा उत्पादन, फार्मा ,डिजिटल, व्यवस्था के साथ ही मोबाइल उत्पादक, स्टार्टअप्स, ड्रोन हरित ऊर्जा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में भी तेजी से वैश्विक स्तर पर लीडर के रूप में स्थापित करने की और अग्रसर है। भारत का प्राचीन इतिहास गौरवशाली रहा है, इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। ब्रिटिश अर्थशास्त्री एवं इतिहासकार एंगस मेडिसन ने अपने शोध ग्रंथ में बताया है कि एक ईसवी से 1750 ई तक के खंड काल में विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी 32-46 प्रतिशत के बीच तक रही। भारत से विभिन्न कृषि, औद्योगिक उत्पादों के निर्यात का भुगतान सोने से किया जाता था। अत: भारत में स्वर्ण का अपार भंडार निर्मित हो गया था। इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाने लगा था परंतु अरब आक्रांताओं एवं ब्रिटिश शासकों ने भारत को जमकर लूटा था और अति पिछड़ा देश बनाकर छोड़ा। आज इतिहास ने पुन: नई करवट ली है और भारत अपने पुराने वैभव को प्राप्त करने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत में 1947 में राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त की और पिछले 77 वर्षों के दौरान भारत के विकास की बात करें तो ध्यान आता है कि भारत ने पूरे विश्व में आर्थिक अंतरिक्ष विज्ञान ,रक्षक, सुरक्षा ,डिजिटल, योग एवं आध्यात्म जैसे क्षेत्रों में अपना अलग मुकाम बना लिया है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में वैश्विक ताकत बनकर उभड़ा है न केवल अपने लिए सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज रहा है बल्कि कई अन्य देशों के लिए भी सैटेलाइट अंतरिक्ष में स्थापित करने में सक्षम हो गया है। विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने विश्व में मुकाम बना लिया है। किसी भी देश के लिए आर्थिक प्रगति सफल मानी जानी चाहिए, जबकि उसके अंतिम पंक्ति में खड़े नागरिक को भी देश की आर्थिक प्रगति का लाभ मिलता दिखाई दे। इस दृष्टि से विशेष रूप विशेष गरीबी एवं आय की असमानता काम करने में भारत में विशेष सफलता पाई है इसकी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक ने भी सराहना कि है । देश में 1947 में 70% लोग गरीबों की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे थे और 1920 में देस कुल आबादी का लगभग 10% हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे है। भारत में रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने की और कदम बढ़ा दिए हैं हाल में स्वदेशी निर्मित तेजस हल्का लगा को विमान मलेशिया की पहली पसंद बनकर उभरा है। आकाश मिसाइल भी भारत की पहचान है यह स्वदेशी 96% मिसाइल है। वियतनाम इंडोनेशिया और फिलीपींस के अलावा बहरीन, केन्या, सऊदी, अरब ,मिश्र, अल्जीरिया और संयुक्त अरब अमीरात में आकाश मिसाइल खरीदने में रुचि दिखाई है कई देशों ने तटीय निगरानी प्रणाली राडार और और प्लेटफार्म को खरीदने में रुचि दिखाई है। भारत फिलिपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया आदि को ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात करने की तैयारी कर रहा है। सऊदी अरब संयुक्त अरब अमीरात एवं दक्षिण अफ्रीका आदि ने मिसाइल में रुचि दिखाइए है । यह बातें भाजपा की एक बैठक में भाजपा मीडिया प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल ने संबोधित करते हुए कहा। इस अवसर पर रंजीत प्रसाद, टीपू सिंह, निशांत कुमार,भाजपा जिला मंत्री शोभा देवी शोभा पटेल, संजू कुमारी,ममता पटेल,अनामिका पटेल, अनामिका पाण्डेय, अनीता पाटनी , बब्लू शाह, जितेंद्र मिस्त्री आदि मौजूद थे।●

बिहार के एकमात्र वैद्य-प्रो. श्याम सुन्दर शर्मा

सेवा रत्न से सम्मानित

● **प्रो0 रामजीवन साहू**

राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ प्रतिवर्ष सम्पूर्ण भारत के आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के माध्यम से उत्कृष्ट सेवा करने वाले चिकित्सक को पुरुष्कार के साथ -साथ सम्मानित भी किया जाता है। पूरे भारत में 2024-25 में 13 चिकित्सकों ही चयनित हुए हैं :-

☞ वैद्य भावनाबेन अहमदाबाद, गुजरात।
☞ डॉ० ईना शर्मा कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
☞ डॉ० जी०एस० बदेशा, रायपुर, छत्तीसगढ़।
☞ वैद्य मुरली कृष्ण पारसराम, तिरूपति, आंध्रप्रदेश।
☞ वैद्य दत्तात्रेय मधुकर राव सराफ, नागपुर, महाराष्ट्र।
☞ वैद्य रामावतार शर्मा, चुरु, राजस्थान।
☞ वैद्य प्रो० श्याम सुन्दर शर्मा, भागलपुर, बिहार।
☞ प्रो० (डॉ०)विष्णु प्रसाद सरमा, गुवाहाटी, आसाम।
☞ वैद्य गोपाल शरण गर्ग, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश।
☞ डॉ० यूनूस गफ्फार सोलंकी, मुंबई, महाराष्ट्र।

☞ वैद्य मेधा पटेल, सूरत, गुजरात।
☞ डॉ० विभा द्विवेदी बरेली, उत्तर प्रदेश।
☞ वैद्य संतोष भगवान राव नेवपुरकर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र।

इस सूची को देखने से स्पष्ट है कि बिहार प्रांत से एकमात्र वैद्य प्रो0 श्याम सुन्दर शर्मा हैं। श्याम सुन्दरजी सिल्क नगरी भागलपुर मुंदीचक के रहने वाले हैं। संयोग है कि ये मेरे गुरुबन्धु हैं। इनके पिताजी का नाम श्री रामस्वरूप शर्मा है। ये भागलपुर के प्रसिद्ध विद्यालय मारवाड़ी पाठशाला में वाणिज्य के अध्यापक थे। वे पाठशाला के सभी विद्यार्थियों के साथ पुत्र के समान पढ़ाते थे। फलस्वरूप भगवान भी इनके लिए बड़े दयालु बने। ज्येष्ठ पुत्र प्रो0 श्याम सुन्दर शर्मा आयुर्वेदिक डाक्टर बने। जिन्हें सेवा रत्न से सम्मानित किया गया। द्वितीय पुत्र विष्णु कुमार शर्मा भारतीय रिजर्व बैंक से मैनेजर पद से रिटायार्ड किये हैं। तृतीय पुत्र नरेश कुमार शर्मा मैनेजिंग डायरेक्टर पद से रिटायर्ड किये हैं और छोटा पुत्र डाक्टर रमेश कुमार शर्मा भागलपुर कृषि महाविद्यालय में प्रोफेसर हैं। चार मार्च 2024 को अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय सेंटर के भीम विशाल कक्ष में राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ संस्थान का 27वें दीक्षांत समारोह और 29वें संगोष्ठी का आयोजन किया गया और भारत के चयनित डाक्टरों को मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा, स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्रीमती अनु नागर, एम्स न ई दिल्ली के निदेशक डा0 एम0 श्रीनिवास,एम्स जोधपुर के कार्यकारी निदेशक डा0 गोवर्धन दत्त पुरी, आयुष मंत्रालय के केन्द्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् में महानिदेशक प्रो0 रवीनारायण आचार्य, न ई दिल्ली के राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ शाशिनिकाय के पूर्व अध्यक्ष वैद्य देवेन्द्र निगुणा और केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एवं केन्द्रीय आयुष मंत्रालय के बरिष्ठ अधि कारीगण उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डा0 मनसुख मांडविया कर रहे थे। राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ की स्थापना 1976 में जयपुर की गई। यह भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अंतर्गत कार्य कर रहा है।●

विधान सभा घेराव में हिंसक झड़प

● **अमित कुमार सिंह/अनिता सिंह**

आजादी के 77 साल बीत जाने के बाद भी मूल अतिपिछड़ो की राजनीतिक दशा और दिशा मे कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। सरकार कहती है जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी राजनीतिक भागीदारी नेताजी चुनाव के समय मिठी-मिठी बाते करती है जननायक कर्पूरी ठाकुर जयंती तो सभी मनाते है लेकिन उनकी राजनीतिक भागदारी की कोई बात नहीं करता है। आज मूल अतिपिछड़ी की राजनीतिक भागीदारी इतनी बढ़ी आबादी रहते हुये भी हाशीये पर है। मुठी भर लोग शासन कर रहे है। माल मालिक ने मिर्जा खेले होली-सरकारी नौकरी में थोड़ी भागीदारी छोड़कर सता की मुख्य धारा से अति पिछड़ा समाज अभी भी पूरी तरह कोसो दूर है। अतिपिछड़ो के लिए जिला परिषद की आरक्षित 8 सीटो मे सात नगर निगम तीनो महा पौर (मेयर) की सीट को नीतीश कुमार के अतिपिछड़ो सिर्फ (तेली) ने हड़प लिया है। कुछ यही हाल मुखिया, वार्ड, जिला परिषद, पंचायत समिति का यही हाल है। विधान सभा का 2020 में 110 अतिपिछड़ी जातियो की भागीदारी लगभग 5 से 6 प्रतिशत और इन तेली तमोली दांगी इन तीनों जातियो की भागीदारी 4 प्रतिशत है। इन तीन जातियो को मूल अतिपिछड़ा की श्रेणी से नही हटाया गया तो 110 मूल अतिपिछड़ा जातियो का अस्तित्व धीरे-धीरे समाप्त हो जायेगा। तेली तमोली (चौरसिया) दांगी (कोयरी) को मूल अति पिछड़ी जाति की श्रेणी से अलग किया जाय एवं प्रथम ग्रुप बनाकर इनको समानुपातिक आरक्षण मिले। रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट सार्वजनिक हो ताकि मंडल कमीशन के लागु होने के 32 साल वाद यह पता चल सके कि इसका लाभ कुछ ही जातिया उठा रही है। 95% जातिया वंचित है। इसलिए केन्द्रीय सेवाओ मे अतिपिछड़ी जातियों के लिए 18% आरक्षण का प्रावधान किया जाय। साथ ही सम्मानित अब्दुल क्यूम अंसारी एवं पर्वत पुरूष दशरथ मांझी को मरणोपरान्त भारत रत्न से सम्मानित करे। 1951 सर्वे के अनुसार बिहार में 79 अतिपिछड़ी जातिया थी मुर्गरी लाल आयोग की रिपोर्ट मे 94 और अब यह बढ़कर 113 पहुँच गई है। राजनीति और अन्य कारणो से सम्पन्न तीन जातियाँ तेली तमोली दांगी को अतिपिछड़ा श्रेणी मे शामिल कर लेने से मूल अतिपिछड़ी जातिया की औसत 80 से 90 तथा कही-कही सौ फीसदी तक हकमारी हुई। बिहार में अतिपिछड़ा हिन्दु 34% व मुसलमान 11% की आबादी लगभग 45 फिसदी है। अगर सरकार इन्हे MLA 243 में 45% = 109 सीट MLC 75 में 34 सीट 45%, ससंद 16 का 45% = 7 सीट सांसद 40 का 45% = 18 सीट की भागीदारी होती। अगर सरकार 36% भागीदारी देती है। तो विधान सभा के 243 में 88 विधायक लोक सभा के 40 में 15 सांसद तथा राज्य सभा 16 मे 6 सांसद तथा विधान परिषद के 75 में 27 विधान परिषद अतिपिछड़ा समाज के बनेगें। लेकिन वर्तमान मे 243 मे 19, विधान सभा सदस्य है विधान परिषद के 75 मे 4 राज्य सभा के 16 मे 2 तथा लोक सभा सदस्य के 40 मे 7 है। मूल अतिपिछड़ा समाज शैक्षणिक, राजनैतिक एवं आर्थिक विकास से वंचित है। इसे आगे बढ़ाने की दिशा मे पहल करते हुए जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने 1 अक्टुबर 1978 को मुर्गरी लाल आयोग की अनुशंसा के आलोक में आरक्षण की अधिसूचना निर्गत की गई थी। अतिपिछड़ा की मांग को कुचलने का काम तेजस्वी यादव और उसकी पार्टी ने किया विधान सभा घेराव मे हजारो हजार की संख्या में पहुँचे अतिपिछड़ी जाति की महिला पुरूष पर बर्बरता से लाठी चार्ज होता रहा लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के नेताओ को इस बात से कोई मतलब नही है। साथ ही उन्होने कहा कि सरकार और विपक्ष पार्टी का नेतृत्व को गंभीरता से नही ले रही है। इस बार

लोकसभा और विधान सभा चुनाव मे अतिपिछड़ा ये बता देगा कि हम एक है अति पिछड़ो की हकमारी करने वालो के विरोध में सड़क से सदन तक खड़े रहेगे। इसके लिए 100 वार भी MLC की सदस्यता चली आय मुझे गम नही पाँच सूत्री मांग को लेकर समस्तीपुर कपूरी ग्राम से पटना पदयात्रा एवं मिलर हाई स्कूल मे हुआ कार्यक्रम से लालू, नीतीश कुमार ने बौखलाकर रामवली चन्द्रवंशी को गैर कानूनी तरीके से विधान परिषद की सदस्यता खत्म कर दी। अतिपिछड़ी जाति इन चाचा भतीजा की दोगली राजनीति को समझ गई अब अतिपिछड़ी जाति झण्डा ढोनेवाली नहीं है। विधान परिषद सभापति देवेश चन्द्र ठाकुर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू यादव के दबाव में और तेजस्वी के परिषद की सदस्यता समाप्त करने के पत्र सभापति को दिया। सरकार बदलने के बाद नीतीश के दबाव मे टिकट प्राप्त करने के लिए नियम को ताक पर रखते हुए। आनन फानन मे सदस्यता समाप्त कर दी। जबकि नियमानुसार सदन मे पार्टी हित का उल्लंघन करने पर कारवाई करने का प्रावधान है। दरअसल जननायक के मूल अतिपिछड़ो को लुटते अधिकार पर आवाज उठाने से 35 वर्षो से बिहार मे शासन कर रहे दोनो क्षत्रपो ने उभरते नेतृत्व को चुप करने के लिए साजिश के तहत निष्कासन कराया गया। डॉ0 रामवली सिंह चन्द्रवंशी वाबू के निष्कासन से 110 मूल अतिपिछड़ा वर्ग के लोगो में काफी रोष है। इसका दुष्परिणाम लागू नीतीश कुमार और सभापति को भुगतना होगा। अतिपिछड़ा आरक्षण बचाओ सघर्ष मौर्या ने विधान सभा का घेराव करने के लिए मार्च निकाला। राम गुलाम चौक पर इन प्रदर्शनकारियो को रोकने के लिए वैरिकेटिग की गई थी। वैरिकेटिग को तोड़कर जब प्रदर्शनकारी आगे बढ़े तो हालात वेकाबू हो गई। पुलिस से हिसक झंडप हो गई पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इससे भगदड़ मच गई। कई घायल हो गये। सदर एसडीओ श्रीकान्त कंडलिक खाडेकर धारा 144 का हवाला देते हुए। जगह खाली करने की अपील करने लगे। लेकिन प्रदर्शनकारी मानने को तैयार नही थे। वरीय अधिकारियो ने मार्च का नेतृत्व कर रहे रामवली चन्द्रवंशी से प्रदर्शन समाप्त करने की अपील की गई। इसके बाद मार्च समाप्त कर दिया गया परिषद रामवली चन्द्रवंशी ने कहा कि हमलोग शांतिपूर्ण ढंग से विधान सभा का घेराव करने जा रहे थे। लेकिन पुलिस ने रोक दिया। उन्होने आरोप लगाया कि पुलिस ने महिला प्रदर्शनकारियों के साथ छेड़खानी भी की है। इसकी दशा और दिशा मे परिर्वतन नहीं हुआ। बिहार के जिला परिषद के आरक्षित 8 मे 7 तेली, बिहार के 3 मेयर आरक्षित से 3 तेली बिहार लोक सेवा आयोग के 103 मे 91 सिर्फ तेली नियुक्त साथ ही शिक्षक, दरोगा, सिपाही, सचिवालय सहायक, जनवितरण की दुकान पर कब्जा जमाये बैठे है। लगभग 80% व्यापार पर सिर्फ तेली का कब्जा बाजार में है। मूल अति पिछड़ा का 90 से 95% तेली, तमोली, दांगी कब्जा जमाये बैठे है। ऐसे मे मूल अति पिछड़ा का विकास कैसे संभव है। डॉ0 रामवली चन्द्रवंशी

ने 36% आरक्षण को लागु करने की मांग की। नगर निगम मे 17 मे 3 सीट सुरक्षित में भी जिसमे मेयर के तीनो सीट पर तेली जाति का कब्जा है। उक्त बाते उन्होने मिलर स्कूल मे सभा को संबोधित करते हुए कहा, साथ ही विधान परिषद प्रो0 रामवली सिंह चन्द्रवंशी ने 2015 मे तेली, तमोली और दांगी को मूल अतिपिछड़ा में शामिल करने पर कड़ी आलोचना की ये तीनो को मूल अति पिछड़ा से नही हटाया गया तो आने वाला लोक सभा विधान सभा मे खमियाजा भुगतने के लिए तैयार रहे। प्रो0 रामवली ने अतिपिछड़ा पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए एससी/एसटी के तर्ज पर अतिपिछड़ा अत्याचार निवारण कानुन बनाने, पंचायत नगर निकाय मे 33% आरक्षण करने, रोहिणी कमीशन रिपोर्ट सार्वजनिक करने जिसमें 95% जातियो को आरक्षण का लाभ नहीं मिलने की बात कही। साथ ही उन्होने कहा कि आजकल कथनी और करणी मे फर्क है। लोगो को आज गांधी और कपूरी के मांगो पर चलने को लेकर हुई थी। पर 2015 में तीन जाति तेली तमोली और दांगी को मूल अतिपिछड़ा में शामिल कर हकमारी हुई है। ये तीनों जाति की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत है और व्यापार मे तथा शहरीकरण मे भी आगे है। तेली के पास अकुत सम्पति है। आज अति पिछड़ा वर्ग के कई मंत्री और एलएलसी है। लेकिन आरक्षण जो मूल अतिपिछड़ा की मांग है। उस पर किसी की जुबान नही खुली। बिहार में 7 माह पूर्व चुनाव हुआ जिसमें तेली जाति के मेयर का तीनो सीट हडंप लिया। जिला परिषद अध्यक्ष पद के 8 अतिपिछड़ा का सुरक्षित या जिसमे 7 सीट तेली ने हडंप लिया। 2015 में शामिल तीनो जातियो ने हडंप लिया। प्रो0 चन्द्रवंशी ने कहा कि मूल अतिपिछड़ा की आबादी को जागरूक करने और उनका अधिकार दिलाने के लिए लहु का एक-एक कतरा देने के लिए तैयार हूँ। आप सभी आज संकल्प लेकर जाये कि आप झूठ नेताओं के बहकावे में नहीं आये। जनगणना पर उन्होने कहा कि सरकार वार्ड स्तरीय सूचि रखे। ताकि लोग उसे देखे। एक दो माह के भीतर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जायेगा। जिसमे सभी जिला के लोगो को जागरूक किया जायेगा। अजय कानू ने कहा कि वोट हमारा राज तुम्हारा नही चलेगा, नहीं चलेगा, साथ उन्होने कहा कि बिहार मे तीन और केन्द्र सं0 दो मांगे है। बिहार में पहली बार मूल अति पिछड़ा की इतनी बड़ी रैली का आयोजन हुआ है। उन्होने कहा कि मांगे पूरी नही होती है तो बड़ा आन्दोलन होगा। 2015 मे तेली, तमोली, और दांगी को शामिल कर मूल अति पिछड़ा को ठगने का काम किया है। तब से इसकी दशा दिशा में और बद से बदतर स्थिति हो गई है। प्रो0 शिव जतन ठाकुर अतिपिछड़ा के लोग एक रहे तो हमे कोई हरा नहीं सकता। अगर मुस्लिम आवादी जोड़ दिया जाय तो 50% मूल अति पिछड़ा हमारी आबादी होगी। मौके पर डॉ0 सत्यानंद चौधरी, विजय चौधरी, नितू सिंह, रेखा कुमारी, सुरेश निषाद, बिहार निषाद संद्य प्रदेश संगठन मंत्री राजु निषाद, अशोक कुमार, युवा नेता लवकुश कुमार चन्द्रवंशी, डॉ0 उमाशंकर शहनी, अजय कानू, मनोज सिंह चन्द्रवंशी, अभिषेक कुमार चन्द्रवंशी, विजय कुमार राय, संतोष महतो, प्रयाग शहनी, शिव चन्द्र मंडल समेत मोर्चा के हजारो-हजार की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे।●

राजनीति में कदम रखने की तैयारी में

गैंगस्टर अशोक महतो

नव विवाहिता मुंगेर से लड़ सकती हैं चुनाव

● **मिथिलेश कुमार**

नवादा बीते दो दशक पूर्व मगध क्षेत्र में पिछड़ों और अतिपिछडों में अपनी गहरी पैठ रखने वाले जिले के कुख्यात बाहुबली रहे गैंगस्टर अशोक महतो ने दिल्ली की लड़की से शादी रचा ली है। महतो ने कुमारी अनीता के साथ सात फेरा लिया। अब अशोक महतो अपने प्रतिद्वंद्वी रहे अखिलेश सिंह की तरह राजनीति में अपना भाग्य अजमाना चाहते हैं। सूत्रों के अनुसार महतो ने आरजेडी से मुंगेर लोकसभा सीट पर दावा ठोक दिया है और अपनी पत्नी कुमारी अनिता को चुनाव मैदान में उतारने का एलान किया है अशोक महतो ने अपनी शादी के बारे में कहा था कि विवाह करेंगे और मंगलवार की देर रात अशोक महतो ने विवाह कर लिया। बीते 19 मार्च की रात अचानक लगभग 50 गाड़ी की काफिला के साथ अशोक महतो दूल्हा बनकर पटना जिले के मां जगदंबा स्थान के मंदिर में पहुंचे और शादी रचाई। शादी समारोह में बारात बनकर उनके चाहने वाले व उनके सहयोगी और परिवार शामिल हुए। अशोक महतो और उनकी पत्नी कुमारी अनिता के परिवार के सदस्य शादी समारोह में शामिल हुए। दिल्ली की रहने वाली कुमारी अनीता से शादी हो गई। बताया जाता है कि कुमारी अनीता स्नात्तकोत्तर डिग्री धारी है और दिल्ली में निजी कम्पनी में कार्यरत थी।

☞ **पटना के करौटा मां जगदंबा स्थान मंदिर में हुई शादी :-** पटना जिला के सलेमपुर थाना क्षेत्र के करौटा मां जगदंबा स्थान मंदिर में 50 गाड़ी की काफिला के साथ अशोक महतो विवाह रचाने के लिए पहुंचे और सात फेरा लेकर कुमारी अनिता की मांग में सिंदूर भर दिया। 55 साल की उम्र में अशोक महतो ने अपनी जीवन साथी को चुन लिया है।

☞ **कभी जिले के बाहुबली थे अशोक महतो :-** नवादा के वारिसलीगंज में 1990 की दशक में अखिलेश सिंह व बाहुबली अशोक महतो की तूती बोलती थी। 17 साल तीन महीने बाद जेल से निकलने के बाद लंबा काफिला निकला, समर्थन मिले और जब लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई तो अशोक महतो भी चुनाव मैदान में उतर गए।

☞ **रहा है लम्बा आपराधिक इतिहास :-** अपराधी अखिलेश सिंह व अशोक महतो गिरोह नवादा, नालन्दा व शेखपुरा जिले में सक्रिय था जिसका नेतृत्व किया करता था जिसमें पिंटू महतो भी शामिल था। जिले में दो समानानंतर गिरोह के बीच वर्चस्व कि लड़ाई के दौरान दर्जनों नर संहार में सैकड़ों लोगों कि जाने गयी. लोगों में आतंक का खौफ व्याप्त था। अशोक महतो और उसका गिरोह 2005 में मौजूदा संसद सदस्य (लोकसभा) राजो सिंह की हत्या के लिए जिम्मेदार था। अशोक

महतो को कैद कर लिया गया था लेकिन 2002 में वह नवादा जेल से भाग गया। जेल से भागने के दौरान पिंटू महतो ने तीन पुलिस अधिकारियों की हत्या कर दी थी। कहा जाता है कि गिरोह के नेता या तो कुर्मी या कोइरी जाति से थे, और उन्हें नालंदा,नवादा और शेखपुरा क्षेत्रों में पिछड़ी जातियों का समर्थन प्राप्त था। 1990 के दशक के अंत में बड़ी संख्या में जाति के लोगों की हत्या के लिए महतो और उसका गिरोह जिम्मेदार था। महतो और गैंगस्टर अखिलेश सिंह के बीच प्रतिद्वंद्विता ने बिहार के नवादा , नालंदा और शेखपुरा जिलों के 100 से अधिक गांवों को प्रभावित किया था।

☞ **खाकी द बिहार चैप्टर** :- आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा की किताब पर आधारित वेब सिरीज, अशोक महतो का नाम पर भी वेब सीरीज बनाया गया था। हालांकि इस वेब सीरीज का अशोक महतो समर्थकों ने विरोध भी किया है और कहा है कि इस सीरीज में कुछ कहानी गलत भी है।

☞ **उपेंद्र कुशवाहा ने अशोक महतो के समर्थन में उठाया था आवाज** :- उपेंद्र कुशवाहा अशोक महतो के बहाने नीतीश कुमार के लव-कुश समीकरण पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं। वे यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोइरी जाति के अशोक महतो के साथ अन्याय हो रहा है। कहा है कि अगर आनंद मोहन को जेल से पेरोल पर रिहा किया जा रहा है तो अशोक महतो को क्यों सलाखों के पीछे बंद रखा गया है।

☞ **समर्थकों की जुटी थी भीड़** :- इधर, पकरीबरावां प्रखंड क्षेत्र के बढ़ौना गांव निवासी अशोक महतो उर्फ साधू जी 17 दिसंबर को भागलपुर कारा से रिहा होने के बाद अपने पैतृक घर बढ़ौना देर शाम को सैकड़ों समर्थकों के साथ पहुंचे थे। अशोक महतो कि रिहाई के बाद समर्थकों कि उमड़ी भीड़ एवं वाहनों का काफिला ने बाहुबली शहाबुद्दीन कि याद दिला दी थी. वारिसलीगंज क्षेत्र में लौटने पर समर्थकों ने चातर मोड़ और बढ़ौना मोड़ पर महतो का जोरदार स्वागत किया था.बहरहाल लोकसभा चुनाव में राजनितिक दलों के द्वारा अशोक महतो को किस हद तक भरोसा किया जाता है वह चुनाव ही बताएगा. हालांकि अशोक महतो का मुंगेर से चुनाव लड़ने कि तैयारी चल रही है।●

महत्वपूर्ण होगा लोकसभा 2024 का चुनाव

● **मिथिलेश कुमार**

लोकसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है। चुनाव का बिगुल बजते ही विभिन्न राजनैतिक दलों के कार्यकर्ताओं में टिकट को लेकर दावेदारी शुरू है वही कई पूर्व एवं वर्तमान विधायक, सांसद, विधान पार्षद टिकट को लेकर पार्टी बदलने को तैयार हैं कई बदल भी चुके हैं. चुनाव कि फिजा बरसात कि तरह हो गयी है. उम्मीद के अनुसार ही तारीखें घोषित होते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष में बयानबाजी बढ़ गई है। देश में होने वाले ये आम चुनाव इस बार कई मायनों में खास रहने वाले हैं। इस चुनाव से राजनीतिक स्थिरता से लेकर अगले 20 साल के विजन की तस्वीर साफ हो जाएगी। लोकसभा चुनावों की तारीखें घोषित किए जाने के साथ ही जैसी कि उम्मीद थी, सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी और तेज हो गई। सत्ता पक्ष और विपक्ष की इस नोक-झोंक को लोकतंत्र की खूबसूरती मानकर नजरअंदाज कर दिया जाए तो भी इन चुनावों से जुड़े कई अहम पहलू हैं, जो इसे खास बनाते हैं। 20वीं सदी का अंतिम दशक अगर राजनीतिक अस्थिरता का पर्याय बन गया था तो 21वीं सदी अपने साथ स्थिरता लेकर आई। न केवल अटल बिहारी वाजपेयी की अगुआई वाली सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा किया बल्कि उसके बाद पहले डॉ. मनमोहन सिंह और फिर नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली सरकारों ने देश को लगातार 10-10 साल का शासन दिया। अब इस बार के चुनाव में जहां इसका नेतृत्व अगले 20 वर्षों का विजन पेश कर रहा है, वहीं कांग्रेस नेतृत्व इसे लोकतंत्र बचाने का आखिरी मौका करार दे रहा है। यानी इन चुनावों का फलक पांच साल के काम के आधार पर अगले पांच साल के लिए जनादेश के सामान्य ट्रेंड तक सीमित नहीं रहा।

दिलचस्प है कि सत्तारूढ बीजेपी इन चनावों में जिन फैसलों पर सबसे ज्यादा जोर दे रही है, वे भले पांच वर्षों के मौजूदा सरकार के कार्यकाल के दौरान लिए गए हों, लेकिन उन मुद्दों से जुड़े हैं जो वर्षों नहीं, दशकों से इसके मूल मुद्दों के रूप में पहचाने जाते रहे हैं। चाहे राममंदिर, अनुच्छेद 370 और सीएए की बात हो या ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर पूजा शुरू होने की ये सारे मुद्दे बीजेपी के इस दावे को मजबूती देते हैं कि वह जो कहती है, करके दिखाती है। विपक्षी दलों ने इन चुनावों में उन लोगों को संबोधित करने और अपनी ओर खींचने की रणनीति बनाई जो बीजेपी के जाने-पहचाने नैरेटिव के प्रभाव से बाहर माने जाते हैं। आइएनडीआइए बना कर हर सीट पर साझा प्रत्याशी खड़ा करने की सोच के पीछे यही इरादा था। मगर नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी और ममता बनर्जी का आइएनडीआइए से बाहर रहने का फैसला इस रणनीति के आजमाए जाने से पहले ही नाकाम होने का संकेत है। बहरहाल, देखना होगा कि आगे विपक्षी दल अपना केस वोटरों के सामने कितने कारगर ढंग से रख पाते हैं। महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे पुराने मुद्दे भी उठाए ही जा रहे हैं, लेकिन वोटर के फैसले में इनकी कितनी भूमिका रहेगी यह अभी स्पष्ट नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दो-दो यात्राओं से उपजे प्रभाव की परीक्षा भी इन्हीं चुनावों में होनी है। कुल मिलाकर, विपक्ष और सत्ता पक्ष कुछ भी कहे देशवासियों की जागरूक चेतना को देखते हुए यह तय माना जा सकता है कि आम चुनाव का यह लोकतांत्रिक पर्व एक बार फिर देश में लोकतंत्र की जड़ों को गहरा ही करेगा।●

आत्ममंथन करने का अवसर है बिहार दिवस : रामरतन प्रसाद सिंह रत्नाकर

● मिथिलेश कुमार/मनीष कमलिया

बिहार भारत के सांस्कृतिक इतिहास का लीलाभूमि रहा है।इस भूभाग पर शासन करने वाले अधिकांश राजा सत्य अहिंसा और प्रजापालन को अपना धर्म माना है। रामायण काल में मिथिला के राजा जनक ने सुखाड़ पड़ने पर हल जोता था। ढ़ाई बार हल जोतने पर सीता निकली थी। आज भी किसान ढ़ाई रेखा खेत जोत कर सीता प्राप्त करने की भावना रखते हैं। यह लांगल पद्धति है। बिहार के किसान पुरुषार्थी माने जाते हैं। महाभारत काल में पुराणों के अनुसार व्रहदर्थ के पुत्र महाराज जरासंध प्रतापी वैदिक धर्म मानने वाले प्रजा पालक राजा हुए और ज्ञानी लोगों को भी खेती करने का संदेश दिया था। कृषि कला एवं अन्य विभागों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए राज्य दरबार में बुलाकर सम्मानित करने का वृतांत ग्रंथों में है। सबसे बड़ी बात है कि इस वंश के जरासंध सहदेव से लेकर रिपुंजय तक 40 राजा हुए और कुल 940 साल तक शासन किया। लेकिन राजा होने के लिए कभी युद्ध नहीं हुआ। ईसा पूर्व 277 से 236 में मौर्य वंश के प्रतापी राजा अशोक मगध के अत्यंत तेजस्वी, साहसी शासक हुए। कलिंग युद्ध के व्यापक जनसंहार ने अशोक को पश्चाताप के सागर में डुबो दिया और बौद्ध धर्म की सादगी से प्रभावित होकर वह सम्राट से प्रियदर्शी हो गए। सार्वभौम धर्म के सर्वप्रथम निरूपण का श्रेय उन्हीं को दिया गया है।

मान्यता है कि लौह धातु का उपयोग सबसे पहले बिहार में ही हुआ था।कई मान्य विद्वान मानते हैं कि प्रथम वैदिक अवधारणा के अनुसार राजगृह के आसपास प्रथम गांव बसा था। शिक्षा के क्षेत्र में नालंदा विश्वविद्यालय में देश-विदेश के छात्र शिक्षा पाते थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग सातवीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय में छात्र के रूप में और फिर प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हुए। ह्वेनसांग की यात्रा वृतांत के अनुसार राजगृह के पूर्वी हिस्से में सुस्वादू चावल पैदा होता था। अंधेरा घनीभूत था अंग्रेज देश का शासक था। देसी राजा, नवाब सामंत अंग्रेजों के पक्षपाती थे। कई ढंग के शोषण दोहन का तांडव जारी था। उस कालखंड में खासकर पलासी के युद्ध के पूर्व बिहार अलग हुआ करता था। परंतु बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल बिहार और उड़ीसा ईस्ट इंडिया कंपनी के चले जाने के कारण बिहार सूबा का अस्तित्व समाप्त हो गया और वर्ष 1886 में बिहार प्रेसिडेंसी का हिस्सा बन गया जो 1905 तक बना रहा। 1905 में बंगाल प्रेसिडेंसी से पूर्वी बंगाल अलग कर दिया गया। इस बीच बिहार उड़ीसा और छोटानागपुर बंगाल से अलग करने की घोषणा 12 दिसंबर 1912 को की गई थी। जिसकी अधिसूचना 22 मार्च 1912 को निकाली गई थी। इस कारण बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है।

भारतीय स्वतंत्रता के लिए आंदोलन उबड़ खाबड़ रास्तों और दिशाओं के सफर पर था।यह आंदोलन लगभग सौ सालों से जारी था। लेकिन सबों के अर्थात जाति, धर्म, भाषा ,भौगोलिक विविधता वाले समाज को सही लक्ष्य की ओर बढ़ाने के लिए भारतीय राजनीतिक क्षितिज पर एक ऐसा दायित्वमान नक्षत्र का उदय हुआ जिसके अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत बिहार के चंपारण जिले से हुई। महात्मा गांधी ने आंदोलन में जिन जिन तरीकों का उपयोग चंपारण में किया उन्हीं के सहारे राष्ट्र का नेतृत्व भी उन्हें मिला। लोकमान्य तिलक ने कई दिनों तक मुंबई के एक जज के सामने खड़े होकर जो बहस की थी। उसमें उन्होंने ब्रिटिश सरकार को उनके अन्याय के खिलाफ खूब ललकारा था। तिलक ने कहा मैं निर्दोष हूं लेकिन एक राजनीतिक और एक सत्याग्रही में फर्क होता है। तिलक ने कहा मैं निर्दोष हूं। उनकी तकनीक दूसरी थी। लेकिन चंपारण के कलेक्टर के पूछने पर कि तुम क्या कहते हो महात्मा गांधी ने कहा था मैं तुम्हारे कानूनों को तोड़ने वाला हूं। तुम मुझे सजा दे सकते हो गांधी जी के इस आशातीत साहस को देखकर बिहार के अंग्रेजी राज के पदाधिकारी कांप उठे थे। बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन में किसान संगठनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 1917 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1927 से 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किसान सत्याग्रह में अंग्रेजी राज समाप्त होने जमीनदारी राज समाप्त होने का शंखनाद किया गया था। स्वतंत्रता आंदोलन के लिए क्रमबद्ध संघर्ष के दौरान 11 अगस्त 1942 को बिहार के सात सपूत गोलीकांड में पटना सचिवालय के सामने शहीद हो गए और 23 हजार स्वतंत्रता सेनानी जेलों में बंद किए गए। आजादी के संघर्ष के समय जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्वतंत्रता चाहती थी। वही सुभाष चंद्र बोस, स्वामी सहजानंद सरस्वती किसान मजदूरों को वाजीब हक दिलाना चाहते थे।1947 में भारत आजाद हो गया। 110 साल बिहार प्रदेश के गठन के बाद 47 साल संघर्षों में व्यतीत हुए और 75 साल नवनिर्माण का काल रहा।आजादी के बाद बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉ श्री कृष्ण सिंह आजादी के संघर्ष काल में 7 साल 10 दिन जेल में रहे थे। श्री बाबू के मंत्रिमंडल में अनुग्रह नारायण सिंह, के.बी सहाय जैसे व्यक्तित्व के धनी मंत्री बने थे। श्री बाबू की सरकार ने शोषण पर आधारित जमींदारी प्रथा समाप्त किया।देश का प्रथम रासायनिक खाद कारखाना सिंदरी में स्थापित किया। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ने के लिए गंगा नदी में राजेंद्र पुल निर्माण कराया। डालमिया और बरौनी को औद्योगिक केंद्र बनाया। शिक्षा के विकास के लिए कई विश्वविद्यालय स्थापित किया। प्राकृतिक आंगन में नेतरहाट स्कूल का निर्माण कराया। वे इस तरह के स्कूल और खोलना चाहते थे। जहां पढ़ने वाले विद्यार्थी बिहार के आधारभूत संरचना के प्रति सदा सजग रहे। राष्ट्रभाषा परिषद और हिंदी साहित्य सम्मेलन भवन पटना में स्थापित किया। आजादी के बाद बिहार में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार सत्ता में आई। इस बीच अत्यंत पिछड़ी जाति से आने वाले समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर कार्यकर्ता प्रधान राजनीति के तहत के रूप में स्मरण किए जाते हैं।

1974 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति के नाम से जन आंदोलन हुआ मुख्य विषय भ्रष्टाचार मिटाना था। इसके पूर्व डॉ राम मनोहर लोहिया ने सक्रांति का नारा दिया था। बिहार समाजवादियों का गढ़ माना जाने लगा। 1974 के जन आंदोलन के कोख से जनता पार्टी का गठन संघ सोशलिस्ट पार्टी संगठन कांग्रेस के मिलने के बाद गठित हुई। डॉ राम मनोहर लोहिया के विचार नामक पुस्तक में जातिवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि शीर्षक लेख में डॉक्टर लोहिया ने लिखा, दूसरी प्रवृत्ति से भी शूद्र समानता हासिल कर सके ऐसा नहीं लगता।इस प्रवृत्ति से शूद्र स्वयं द्विज बन जाने की कोशिश करता है और द्विजों के गुणों के बजाय उसके अवगुण अपनाता है। जरूरत इस बात की है कि शूद्रों ,पिछड़ों में ऐसा नेता निकले। जिनके पीछे ना सिर्फ शूद्र बल्कि द्विज भी चलने में गौरव अनुभव करें। 110 साल का बिहार में लगातार लोकतंत्र कमजोर पड़ता जा रहा है और धर्मतंत्र प्रभावकारी होते जा रहा है।अब तो करोड़पति ही विधायक, सांसद हो सकते हैं। इसी यक्ष प्रश्न के लिए आत्ममंथन की जरूरत है। कारण सबों के साथ सबों के विश्वास के बिना सब कुछ अधूरा है।●

नवादा लोकसभा क्षेत्र में बदलती रही राजनीतिक परिदृश्य

राजद ने उतारा स्थानीय उम्मीदवार, हो सकती है बगावत

● मिथिलेश कुमार

मगध प्रमंडल का नवादा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कई मायने में बिहार की राजनीति में अहम भूमिका निभाता है 2024 के लोकसभा चुनाव में स्थानीय उम्मीदवार की मांग ने जोर पकरी और क्षेत्रीय पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने स्थानीय प्रत्याशी श्रवण कुशवाहा पर भरोसा जताते हुए अपना सिंबल दिया है. एनडीए गठबंधन ने अपना प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की है लेकिन लोजपा से सीट छीन जाने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में भी स्थानीय प्रत्याशी का मुददा बना दिया है. इसके प्रबल दावेदारों में हिसुआ विधायक अनिल सिंह, राजयसभा सांसद विवेक ठाकुर एवं वारिसलीगंज की विधायक अरुणा देवी का भी नाम आ रहा है. लेकिन भाजपा के आंतरिक स्रोतों से मिली जानकारी के अनुसार हिसुआ के पूर्व विधायक अनिल सिंह रेस में हैं. हालांकि परिणाम की बात करें तों नवादा संसदीय क्षेत्र में महागठबंधन के घटक दलों एवं एनडीए में सीधी भिड़ंत होने की संभावना बन रही हैं लेकिन राजद से पूर्व विधायक राजब्ललभ यादव के भाई विनोद यादव को सिंबल नहीं मिलने पर निर्दलीय प्रत्याशी बनने पर राजद को नुकसान पहुंच सकती हैं जिसका फायदा एनडीए को मिल सकता हैं. बिहार झारखंड सीमा का नवादा लोकसभा संसदीय क्षेत्र राजनीति का प्रयोग शाला रहा है। चुनाव के दौरान जातीय समीकरण के हावी रहने से विकास का मुद्दा गौण हो जाता है। बिहार का कश्मीर के नाम से प्रचलित ककोलत

नवादा संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित सांसद व पार्टी

वर्ष	नाम	दल
1952	ब्रजेश्वर प्रसाद	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (गया-पूर्व-एससी के रूप में)
1952	राम धनी दास	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (गया-पूर्व-एससी)
1957	सत्यभामा देवी	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
1957	राम धनी दास	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
1962	राम धनी दास	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
1967	सूर्य प्रकाश पुरी	स्वतंत्र
1971	सुखदेव प्रसाद वर्मा	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
1977	नथुनी राम	भारतीय लोक दल
1980	कुंवर राम	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
1984	कुंवर राम	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
1989	प्रेम प्रदीप	भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)
1991	प्रेम चंद राम	भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)
1996	कामेश्वर पासवान	भारतीय जनता पार्टी
1998	मालती देवी	राष्ट्रीय जनता दल
1999	डॉ० संजय पासवान	भारतीय जनता पार्टी
2004	वीरचंद पासवान	राष्ट्रीय जनता दल
2009	डॉ० भोला सिंह	भारतीय जनता पार्टी
2014	गिरिराज सिंह	भारतीय जनता पार्टी
2019	चन्दन सिंह	लोक जनशक्ति पार्टी

नवादा संसदीय क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या
(15.03.2024 के अनुसार)

विधानसभा	पुरुष	महिला	थर्ड जेंडर	कुल
रजौली	174535	162476	19	337030
हिसुआ	201003	184822	49	385874
नवादा	188757	174828	14	363599
गोविन्दपुर	168984	155804	34	324822
वारिसलीगंज	186911	171527	33	358471
नवादा जिला	920190	849457	149	1769796
बरबीघा	122122	111585	1	233708

रामधनी दास संयुक्त रूप से सांसद रहे। अगले चुनाव में ही नवादा से पहली महिला सत्यभामा देवी संसद की सीढियां चढ़कर सदन तक पहुंची। डेढ़ दशक तक इस संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस का दबदबा रहा। लेकिन वर्ष 1967 में पकरीबरावां क्षेत्र के बुधौली मठ के महंथ सूर्य प्रकाश नारायण पुरी स्वतंत्र रूप से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। 1971 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने वापसी की और पार्टी के सुखदेव प्रसाद वर्मा चुनाव जीता। आपातकाल के बाद हुए चुनाव में यहां कांग्रेस को बड़ा झटका लगा और 1977 के आम चुनाव में भारतीय लोक दल के नथुनी राम सांसद रहे। 1980 में लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस सांसद कुंवर राम को जीत मिली और वे 1989 तक सांसद रहे। इसके बाद से आज तक नवादा सीट पर कांग्रेस की वापसी नहीं हो सकी । लोकसभा चुनाव 1989 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रेम प्रदीप विजयी रहे। पहली बार भारतीय जनता पार्टी प्रमुख दल के रूप में उभरी। हालांकि पार्टी के कामेश्वर

जलप्रपात इसी क्षेत्र में है। नवादा संसदीय क्षेत्र कौआकोल का रानीगदर मानव सभ्यता का उदय स्थल रहा है। यह सप्तऋषियों की तपोभूमि रही है। रामायण और महाभारत काल के कई प्रसंग यहां की जनश्रुतियों में आज भी कही-सुनी जाती हैं। महावीर व बुद्ध ने इस धरती से विश्व को अंहिसा और शांति का संदेश दिया है। मौर्य साम्राज्य का अंश रही नवादा नगरी राजनीति की प्रयोगशाला रही है। आजादी के बाद वर्ष 1951 में हुए पहले लोकसभा चुनाव में नवादा से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ब्रजेश्वर प्रसाद व

पासवान चुनाव हार गए और दूसरे स्थान पर रहे। वर्ष 1991 में माकपा से प्रेमचंद राम जीते। 1996 में भाजपा के कामेश्वर पासवान ने जीत दर्ज की। लेकिन 1998 में हुए मध्यावधि चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार मालती देवी ने इन्हें हरा दिया। 1999 के चुनाव में यह फिर भाजपा की सीट रही। नए सहस्राब्दी के साल 2004 में हुए पहले चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के वीरचन्द पासवान संसद पहुंचे। इसके बाद से नवादा संसदीय सीट पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) का कब्जा है। 2009 में भोला सिंह और 2014 में गिरिराज सिंह भारतीय जनता पार्टी से सांसद रहे। जबकि 2019 में राजग की सहयोगी पार्टी लोकजन शक्ति के चंदन कुमार सांसद रहे।

☞ **आजादी के बाद कई बार बदला है नवादा संसदीय क्षेत्र :-** आजादी के बाद पहले आम चुनाव से लेकर अबतक इसकी सीमाओं में काफी परिवर्तन हुआ है। वर्ष 1957 से पहले यह गया पूर्वी संसदीय सीट का हिस्सा था। इसके बाद नए परिसीमन के तहत संसदीय क्षेत्र संख्या-34 के रूप में इसका गठन हुआ। अगले लोकसभा चुनाव के पूर्व साल 1962 में यह बदलकर संसदीय क्षेत्र संख्या-42(सुरक्षित) के रूप में अस्तित्व में आया, जो करीब चार दशक तक अपने स्वरूप में रहा। इस दौरान गया जिले का अतरी विधानसभा क्षेत्र इसका हिस्सा हुआ करता था। नए सहस्राब्दी के प्रारम्भ में वर्ष 2004 में फिर से इसका परिसीमन बदला और यह संसदीय क्षेत्र संख्या-39 के नए कलेवर में सामने आया। वर्तमान में रजौली, हिसुआ, नवादा, गोविन्दपुर, वारिसलीगंज और शेखपुरा जिले का बरबीघा विधानसभा क्षेत्र इसमें शामिल है।

☞ **जातीय समीकरण और स्थानीय प्रत्याशी का मुद्दा है हावी :-** नवादा लोकसभा सीट लंबे समय तक जातीय हिंसा और नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है। प्रत्येक चुनाव में विकास के मुद्दे गौण ,कास्ट फैक्टर हावी रहता है। भूमिहार और यादव बहुल इस क्षेत्र में राजनीति की धूरी इन दो जातियों के इर्द-गिर्द घूमती है। हालांकि कुशवाहा और वैश्य समाज के अलावा मुस्लिम वोटर भी जीत-हार के बड़े फैक्टर है। वर्ष 2009 में परिसीमन बदलने के बाद यह सामान्य सीट हो गई। जिसके बाद राजग ने इस सीट से भूमिहार प्रत्याशियों के लिए दरवाजा खोल दिया। परिणाम भी दिखे। इस बार के चुनाव में स्थानीय प्रत्याशी का मुद्दा भी हावी रहेगा।

☞ **प्रत्याशियों की जीत-हार में महिलाएं दिखा रहीं दम-खम :-** पिछले कुछ चुनावों से महिलाओं की भागीदारी अव्वल रही है। पुरुषों की अपेक्षा उनका मतदान प्रतिशत कहीं अधिक है। लोकसभा चुनाव 2019 में नवादा जिले के 48.76 फीसदी पुरुषों ने मतदान किया, तो 49.76 फीसदी महिला मतदाताओं ने अपना वोट डाला। पुरूषों से महिलाएं दो कदम आगे ही रही। 2015 के विधानसभा चुनाव में भी पुरुषों की अपेक्षा 3.36 फीसदी अधिक महिला वोटरों ने मताधिकार का प्रयोग किया था। गांव-नगर की सरकार हो या संसद की। महिलाएं प्रत्याशियों के जीत-हार में अपना दम-खम दिखा रही है।●

अभी कलम उठाइये

आपके सामने हो रहे भ्रष्टाचार एवं अपराध की खबर की समीक्षा करें और सरकार सहित पुलिस-प्रशासन तक उसको पहुंचाने के लिए केवल सच पत्रिका के साथ जुड़े। खबर की जानकारी इस नम्बर पर दें

सम्पर्क करें:- 9431073769/9955077308

ई-मेल:- editor.kstimes@rediffmail.com पर भेजें।

अर्थतंत्र के दायरे में सिमट कर कराहता लोकतंत्र

● **मिथिलेश कुमार**

विधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था लोकतंत्र का अर्थ है एक ऐसी जीवन पद्धति जिसमें स्वतंत्रता, समता और बंधुता समाज जीवन के मूल सिद्धांत होते हैं। बदलते परिवेश में अर्थतंत्र के बीच लोकतंत्र सिमटकर कराह रहा है। विश्व में भारतीय संविधान एवं लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की सराहना भी की जाती रही है। परन्तु बदलते वैश्विक माहौल में भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में अर्थतंत्र की घुसपैठी होने के कारण परिवर्तन की दिशा में है। लोकसभा या राज्यसभा तथा विभिन्न राज्यों में विधान परिषद एवं विधानसभा चुनाव में अर्थतंत्र की पनाह में स्वच्छ लोकतंत्र की परिभाषा धूमिल हो रही है। बिहार में ग्राम पंचायत सरकार गठन के लिये चुनाव आयोग के द्वारा लोकसभा चुनाव कराए जाते रहे हैं। स्वच्छ एवं पारदर्शी तथा भयमूक्त चुनाव कराने के लिये संकल्पित चुनाव आयोग कई चरणों में चुनाव प्रक्रिया पूरी की जा रही है। अब पंचायत चुनाव राज्य के विभिन्न लोकसभा में कराए भी जा रहे हैं चुनाव में पारदर्शिता को लेकर ईवीएम एवं बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से चुनाव को पूर्ण पारदर्शिता के साथ शातिपूर्ण ढंग से सम्पन्न भी कराए जाने हैं। परन्तु इन सबों के बीच चुनाव में अर्थतंत्र प्रणाली की दविश कहीं न कहीं चुनाव को निश्चित तौर पर प्रभावित कर रही है। स्वच्छ और मजबूत लोकतंत्र का शशक्त रीढ़ चुनाव की प्रक्रिया है जो संवैधानिक दृष्टिकोण से निश्चित अवधि के बीच कराए जाते हैं। एक जमाना था जब चुनाव में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वाले व्यक्ति भी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा कर लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपना योगदान देना शुनिश्चित करते थे। हालांकि ऐसा नहीं की आज वह प्रक्रिया या व्यवस्था बंद हो गयी है लेकिन इतना जरूर है कि चुनाव में धन और बल की अहमियत ज्यादा हो गयी है। लोकसभा चुनाव में सभी प्रत्याशियों को खर्च करने की सीमा दी गयी है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि खर्च असीमित हो गयीहै। अगर माना जाय तो मुखिया जिला परिषद, पंचायत समित्ति प्रमुख जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव बिना अर्थतंत्र के सम्भव नहीं हो पा रहा है। हम भारतीय प्राचीन समय से ही सामंतशाही व राजशाही व्यस्था में जीने के आदी रहे हैं। हमारी इस सोच का फायदा उठाकर राजनीतिक दलों में बंशवादी तत्वों का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है। भारत चूंकि बहुधर्मी देश है। यहां नागरिकों में जातीय व उपजातीय तथा सांस्कृतिक विभिन्नता बहुत अधिक है। इसे ही ध्यान में रखते हुए संविधान में 'विभिन्नता में एकता व राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता' जैसे शब्द डाले गए।

'लोकतंत्र' को लोग महज शासन की एक पद्धति समझ बैठने की भूल कर बैठते हैं। ये एक जीवन पद्धति है और सामाजिक दर्शन भी है। यहाँ तरह के विचारों, दर्शनों, धर्मों, नस्लों और क्षेत्र के लोगों में बगैर किसी भी तरह यथा सामाजिक, आर्थिक व लैंगिक भेदभाव के एक दूसरे की सोच धर्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों का सम्मान होना भी आवश्यक है। हमारी इसी सोच की वजह से गिने चुने लोग हमें बरगलाकर, भ्रमित कर वास्तविक सत्ता पे कब्जा कर लेते हैं। जबकि सही मायनों में लोकतंत्र उसी देश या समाज में संभव है जहाँ स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व जीवन की एक पद्धति के रूप में प्रचिलित हो भारतीय समाज, धर्म व दर्शन की निवृत्तिमार्गी प्रवित्ति ने 'कोड नृप होइ हमहिं का हानी' जैसी सोच को बढ़ावा दिया। भारतीय जनता की छाती पे एक के बाद एक देशी विदेशी शासक दस्तक देते रहे लेकिन हमारा मानना था ईश्वर उसके पापों का दंड देगा। हम हमेशा अपना अगला जन्म सुधारने में लगे रहे। इस जन्म में हमारे ऊपर कितने अत्याचार होते रहे हमने अपने शासक से पलटकर प्रश्न नहीं पूछा। जब कभी हमें अपने राजा या जागीरदार के अत्याचार महसूस भी हुए तो हम अपने 'अवतारवाद की संकल्पना में मशगूल हो जाते थे। कोई राम या कृष्ण आएगा, कोई चंद्रगुप्त मौर्य या समुद्रगुप्त आएगा, कोई पृथ्वीराज चौहान या महाराणा प्रताप आएगा। कोई रानी झाँसी या भगत सिंह आएगा। पिछड़ी व दलित जातियाँ भी इसी भ्रम में जीती हैं। वे भी वाल्मीकि, वेदव्यास से लेकर पेरियार और अम्बेडकर जैसों के इन्तजार में हाँथ पे हाँथ धरकर बैठी रहती हैं तमाशा देखने। मुस्लिम मस्त हैं कि अल्लाह इन्हें कयामत के दिन दंडित करेगा। इसी मनोवृत्ति की वजह से आज 21वीं सदी में भी हमें अपने कष्ट दिखाई नहीं देते। किसानों को कृषि क्षेत्र की दुर्दशा और किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याएं नहीं दिखती। या तो वो अपने जातीय दम्भ में खुश है या राष्ट्रवाद का धतूरा खा के मस्त है। उन बेचारों को ये भी नहीं पता कि कोई निर्जीव भूमि या निर्जीव आर्यावर्त, या निर्जीव भारत माता राष्ट्र हो ही नहीं सकती। बगैर कृषक मजदुर पुत्र के भारत माता की कल्पना भी संभव नहीं। जनता के मूल मुद्दों शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार की माँग के लिए सड़क पे आने के लिए तैयार नहीं। अब इस तरह के माहौल में पली बड़ी जनता से ये अपेक्षा करना कि उसको साल भर से धरने पे बैठे किसान दिखेंगे बढ़ती मंहगाई व बेरोजगारी, बढ़ता भ्रष्टाचार, गिरता रूपया, अर्थव्यवस्था, संवैधानिक संस्थाओं का स्वास, गुलाम होता प्रेस के बीच लोकतंत्र अर्थ तंत्र के दायरे में सिमट रहा है जो आने वाले दिनों के लिये लोकतंत्र के लिये खतरा ही होगा। क्योंकि जिस देश के शासक किसानों की समस्याओं को 14 महीनों तक नजरअंदाज कर सैकड़ों किसानों की शहादत पर अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिये मदमस्त हो अंततः दोनों सदनों से पारित कृषि बिल कानून को वापस लेने की घोषणा किसानों के लिये वरदान होगा यह तो सरकार की नीति निर्धारण तथ्यों पर निर्भर करती है। 2024 का लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग के द्वारा जारी किये गए दिशा निर्देश के बाबजूद लोकतंत्र के महापर्व में देश के सभी राज्यों के सभी लोकसभा क्षेत्रों में कमोबेश अर्थ तंत्र के दायरे में लोकतंत्र सिमटने की पूरी संभावना है. धन बल एवं शाम दम दंड भेद सभी गुणों से परिपूर्ण व्यक्ति ही लोकसभा के मंदिर में प्रवेश कर देश के बड़े बड़े पूँजीपति के लिए नए नए कानून पारित कराएंगे। ●

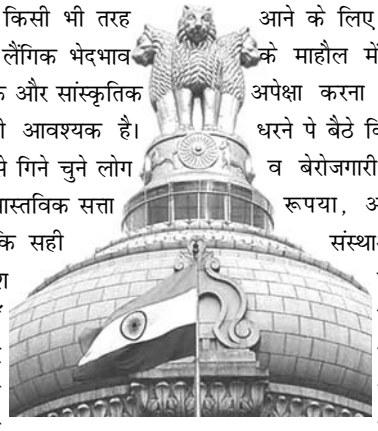

गौरैया का अस्तित्व को खतरा

● मिथिलेश कुमार

गौरैया धीरे-धीरे हमारे आसपास आने लगी है। उसकी चीं-चीं की आवाज हमारे घर आंगन में सुनाई पड़ने लगी है। गौरैया संरक्षण को लेकर ग्लोबल स्तर पर बदलाव आया है। यह सुखद है। फिर भी अभी यह नाकाफी है। हमें प्रकृति से संतुलन बनाना चाहिए। हम प्रकृति और पशु-पक्षियों के साथ मिलकर एक सुंदर प्राकृतिक वातावरण तैयार कर सकते हैं। जिन पशु-पक्षियों को हम अनुपयोगी समझते हैं, वाह हमारे लिए प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित करने में अच्छी खासी भूमिका निभाते हैं, लेकिन हमें इसका ज्ञान नहीं होता। गौरैया हमारी प्राकृतिक मित्र है और पर्यावरण में सहायक है। गौरैया प्राकृतिक सहचरी है। कभी वाह नीम के पेड़ के नीचे फुदकती और चावल या अनाजा के दाने को चुगती है। कभी घर की दीवार पर लगे आईने पर अपनी हमशक्ल पर चोंच्च मारती दिख जाती है। एक वक्त था जब बबूल के पेड़ पर सैकड़ों की संख्या में घोंसले लटके होते थे, लेकिन वक्त के साथ गौरैया एक कहानी बन गई। हालांकि पर्यावरण के प्रति जागरुकता के चलते हाल के सालों में यह दिखाई देने लगी है। गौरैया इंसान की सच्ची दोस्त भी है और पर्यावरण संरक्षण में उसकी खासी भूमिका भी है।

बाजार से नेस्ट हाउस खरीद कर लटकाने अथवा आवास में बरामदे में एक कोने में जूते के डिब्बे के बीच लगभग चार सेंटीमीटर व्यास्त का छेद कर लटकाने पर गौरैया इनमें अपना घोंसला बना लेती है। सिर्फ एक दिन नहीं हमें हर दिन जतन करना होगा गौरैया को बचाने के लिए। गौरैया महज एक पक्षी नहीं है, ये हम्मारे जीवन का अभिन्न अंग भी रहा है। बस इनके लिए हमें थोड़ी मेहनत रोज करनी होगी। छत पार किसी खुली छायादार जगह पर कटोरी या किसी मिट्टी के बर्तन में इनके लिए चावल और पीने के लिए साफ बर्तन में पानी रखना होगा। फिर देखिये रूठा दोस्त कैसे वापस आता है। दुनिया में गौरैया पक्षी के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश से यह दिवस मनाया जाता है। एक समय था जब यह घर के आंगन में चहकती दिखाई देती थी, अब्ब यह धीरे-धीरे विलुप्त होती जा रही है। लेकिन हम्मारी सोच अब आहिस्ता-आहिस्ता बदलने लगी है। हम प्रकृति और जीव-जंतुओं के प्रति थोड़ा मित्रवत भाव रखने लगे हैं। घर की छत पर पक्षियों के लिए दाना-पानी डालने लगे हैं। गौरैया से हम फ्रेंडली हो चले हैं। किचन गार्डन और घर की बालकनी में कृतिम घोंसला लगाने के लिए आवश्यक है कि पेड़-पौधों और जीव-जन्तुओं को पूरा संरक्षण प्रदान किया जाए। गौरैया के संरक्षण में इंसानों की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आवास की छत, बरामदे हो गया। एयरकंडीशनरों ने रोशनदान तो क्या खिड़कियां तक बंद करवा दी। गौरैया ग्रामीण परिवेश का प्रमुख पक्षी है, किन्तु गांवों में फसलों को कीटों से बचाने के लिए कीटनाशकों के प्रयोग कर इसे दूर कर दिया है। गौरैया के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना यह भी मॉरीशस के डोडो पक्षी और गिद्ध की तरह पूरी तरह से विलुप्त हो जायेंगे। इसलिए हम सबको मिलकर गौरैया का संरक्षण करना चाहिए। गौरेया आज संकटग्रस्त पक्षी है जो पूरे विश्व में तेजी से दुर्लभ हो रही है। दस-बीस साल पहले तक गौरेया के झुंड सार्वजनिक स्थलों पर भी देखे जा सकते थे। लेकिन खुद को परिस्थितियों के अनुकूल बना लेने वाली यह चिड़िया अब भारत ही नहीं, यूरोप के कई बड़े हिस्सों में भी काफी कम रह गई है। ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी और चेक गणराज्य जैसे देशों में इनकी संख्या जहाँ तेजी से गिर रही है, तो नीदरलैंड में तो इन्हें दुर्लभ प्रजाति के वर्ग में रखा गया है। वैसे देखा जाए तो इस नन्ही गौरैया के विलुप्त होने का कारण मानव ही हैं। हमने तरक्की तो बहुत की लेकिन इस नन्हें पक्षी की तरक्की की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। यही कारण है कि जो दिवस हमें खुशी के रूप में मनाना चाहिए था, वो हम आज इसलिए मनाते हैं कि इनका अस्तित्व बचा रहे वक्त के साथ जमाना बदला और छप्पर के स्थान पर सीमेंट की छत आ गई। आवासों की बनावट ऐसी कि गौरैया के लिए घोंसला बनाना मुश्किल अथवा किसी खुले स्थान पर बाजरा या टूटे चावल डालने व उथले पात्र में जल रखने पर गौरैया को भोजन व पीने का जल मिलने के साथ-साथ स्नान हेतु जल भी उपलब्ध हो जाता है। प्रकृति ने सभी वानस्पतियों और प्राणियों के लिए विशिष्ट भूमिका निर्धारित की है। इसलिए पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए विश्व गौरैया दिवस पहली बार वर्ष 2010 ई. में मनाया गया था। प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को पूरी दुनिया में गौरैया पक्षी के संरक्षण को जागरूक करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। विदित हो कि अपने अस्तित्त्व के लिए हम मनुष्यों और पास के वातावरण से काफी जद्दोजहद करना पड़ रहा है। ऐसे समय में पक्षियों के लिए वातावारण प्रति अनुकूल बनाने में करनी चाहिए, तभी ये सहायता प्रदान हमारे बीच चह चहायेंगे। गौरैया की घटती संख्या के कुछ मुख्य कारण है- भोजन की कमी, घोसलों के लिए उचित स्थानों की कमी तथा तेजी से कटते गौरैया के बच्चों का भोजन दस-पन्द्रह दिनों में सिर्फ कीड़े-मकोड़े ही होते है। लेकिन आजकल खेतों से लेकर अपने गमले पौधों में भी रासायनिक उपयोग करते है, जिससे ना को कीड़े लगते है और ना का समुचित भोजन पनप पाते। इसलिए गौरैया समेत हजारों पक्षी हमसे रूठ कर शायद वो लगभग विलुप्त होने की कगार पर किसी कोने में अपनी अन्तिम सांसे गिन रहे होंगे।●